"संगठन ही जनता की शक्ति का आधार है"
-शहीद शंकर गुहा नियोगी

मितान

छत्तीसगढ़ के मजदूर किसानों की आवाज

निर्जी वितरण हेतु

११ मई से १७ मई १९९७

१ मई मजदूर-दिवस तिहार

रायपुर मा छत्तीसगढ़ न्यायाग्रह के ललकार

कोना-कोना लें लाईन किसान-मजदूर ६० हजार

१११ बच्छर पहिली अमरीका देस के कमैया मन हा ८ घण्टा कार्य-अवधि के न्यायोचित मांग बर आंदोलन करे रिहीन. ओखर ऊपर बर्बर पुलिसिया दमन होइस अऊ १ मई १८८६ के दिन शिकागो शह मा कतको कमैया भाई मन शहीद होगे रिहीन. न्याय ला स्थापित करे बर कुर्बानी की धारा में चलने वाला लाल-हरा झण्डा के संगवारी, किसान अऊ मजदूर छत्तीसगढ़ के कोना-कोना ले रायपुर पहुंचीन अऊ न्याय के आग्रह बर, शोषण-विहीन छत्तीसगढ़ बर आवाज उठाईन. भिलाई, दल्ली राजहरा, उरला, कुम्हारी, टेड़ेसरा, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुन्द, बाग बाहरा, नगरी, धमतरी, पिथौरा, सराईपाली, बसना, भटगांव, कसडोल अंचल के मेहनतकश मन हा एमा पहुंचे रिहीन.

बड़े सवेरे से ही जगह-जगह से मजदूर-किसानों के जत्थे रायपुर पहुंचने लगे थे और गौस मेमोरियल फुटबाल ग्राउंड में एकत्रित होने लगे थे. दोपहर दो बजे के करीब मोती बाग से रैली प्रारंभ हुई और कोतवाली, जय स्तंभ चौक, शास्त्री चौक होते हुए अम्बेडकर चौक और वीर नारायण सिंह चौक के बीच के स्थल पहुंची. यहां पहुंच कर रैली आमसभा के रूप में परिवर्तित हुई. रैली के सामने लाल-हरा पोशाक पहने दल्ली राजहरा

पटेला ने संबोधित किया.

उनके अतिरिक्त पी. यू. सी. एल. के राजेन्द्र सायल, भोपाल गैस कांड पीड़ित महिला उद्योग संगठन के अब्दुल जब्बार, उत्तरप्रदेश से क्रांतिकारी साथी

गरीब जनता ला तंगात हावे. पांट-पीट के मारं देये घलो. ...हमर आव्हान हवे. झन पटाओ ये सरकार के कर्जा, जइसन होही. ओखर से निपटबोन!

छत्तीसगढ़ के जनता ऊपर

दबाव मा गड़ा नमक ऊपर प्रतिबंध लगाए हे."

शेख अंसार-

"अभी तो हमन रेल ला रोके हवन. जरूरत पड़ही तो हमन दिग्विजय सिंह के हवाई जहाज ला

शाह, विजय गुप्ता, लखपति-करोड़पति-अरबपति बनान हवे. ..."अऊ छत्तीसगढ़ के जनता ला काए मिलीस ? बेरोजगारी, अकाल, प्रदूषण ?"

अब्दुल जब्बार-

"आजकल अदालती सक्रियता की बहुत चर्चा हो रही है. लेकिन यह सक्रियता केवल राजनैतिक एवं प्रचारात्मक दिलचस्पी वाले मामलों में है. आम जनता के मामलों में विशेष रूप से उन मामलों में जहां हजारों-लाखों जनता का जीवन जुड़ा हुआ है

के साथ कदमताल करते हुए जा रहा था.

परम्परागत आदिवासी वेशभूषा में मांदर की ताल पर थिरकते साथी भी रैली के विशेष आकर्षण थे.

रैली में मजदूर-किसान जो नारे लगा रहे थे उनमें प्रमुख थे- **'नवां भारत बर नवां छत्तीसगढ़ बनाबोन', 'हम बनाबोन नवां पहचान, राज करही मजदूर-किसान', 'हमारे धीरज से दिग्गी ... नियोगी जी के हत्यारों को फांसी दो', 'शराब पीना छोड़ दो, शराब की बॉटल फोड़ दो.'**

आमसभा को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथी जनकलाल ठाकुर, गणेश राम चौधरी, शेख अंसार, मघदास वैष्णव, अनूप सिंह, विषेलाल निषाद और गन्नू ... चितरंजन एवं महिला आन्दोलन से सुश्री शशि सयाल और डा. इलिना सेन ने भी अपने विचार व्यक्त किए. सभा शाम ४.०० बजे से रात ८.३० बजे तक चली.

जनकवि साथी फागूराम यादव एवं कलादास डेहरिया ने गीत प्रस्तुत किए. सभा का संचालन साथी मानिक लाल एवं मूलचंद साहू ने किया.

झलकियां....

आम सभा में व्यक्त विचारों की कुछ झलकियां प्रस्तुत है -

जनक लाल ठाकुर-

"...कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अऊ पूर्व कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी हा ३ करोड़ रु. विदेशी चन्दा की कर चोरी के अपराधी हावे अऊ उही कांग्रेस पार्टी के सरकार प्रदेश मा हवे. जेकर मशीनरी वसूली के नाम मा अत्याचार के अंत हो चुके है. बरी आ गे हावे, कुर्बानी देबोन. पर छत्तीसगढ़ मा उद्योगपति अऊ पुलिस के दादागिरी नई चलन देन. अब छत्तीसगढ़ मा इंहा के मजदूर-किसान के बरपेली चलही.

गणेश राम चौधरी-

"नोन नमक पईसा के भाव मा मिलत रिहीस. आज ४ रुपिया ५ रुपिया किलो बिकत हावे. किसान मन हा अपन गाय-गरु ला आयोडीन नमक खवाए बर मजबूर हावे. इही नमक ऊपर टैक्स बढ़ाए के मुद्दा मा गांधी जी हा नमक सत्याग्रह छेड़े रिहीस. आज हमन करबोन नमक के सत्याग्रह ! ...कबार के धंधा रोग हा छत्तीसगढ़ अंचल के समस्या नो हे. ये समस्या हिमालय के तराई अऊ अमरकंटक के इलाका के हावे. लेकिन हमर भोंकवा सरकार विदेशी कंपनी के चला रोक के दिखा देबोन. ...

"छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन होए हे वीरनारायण सिंह के नाम-मा. गुरु घासीदास, शंकर गुहा नियोगी के नाम मा अऊ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संघर्ष अऊ निर्माण के काम हा... प्रदूषित कोड़िया. हत्यारा मूलचंद शाह, हवालिया बी.आर. जैन अऊ ओखर घूस खाने वाला वी.सी. शुक्ला, बोरा, नेताम, पांडे हा छत्तीसगढ़ के नांव ला बदनाम करीन हे."

अनूप सिंह-

"छत्तीसगढ़ के लोहा पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाईट, पानी अऊ जंगल के दोहन करे के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा हर बरस ४२०० करोड़ रु. के संपदा-निर्माण करे जाथे... उही ला हजम करके लोटा धर के छत्तीसगढ़ में आने वाला बी.आर. जैन, मूलचंद अदालती निष्क्रियता ही दिखाई पड़ती है. भिलाई के श्रमिकों का मामला ४ बरस से एवं भोपाल गैस कांड का मामला १० बरस से लंबित है.

राजेन्द्र सायल-

राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा धारा १५१ के दुरुपयोग पर चिंता जताए जाने के बाद एवं म.प्र. पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी अयोध्यानाथ पाठक द्वारा इस पर रोक के निर्देशों के बावजूद २० अप्रैल को दुर्ग पुलिस ने धारा १५१ का सरासर दुरुपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के ११४ महिला-पुरुष कार्यकर्ताओं को ९ दिनों तक अमानवीय परिस्थितियों में जेल में रखा. इस कार्यवाही से दुर्ग पुलिस प्रशासन ने अपनी ही 'उच्च अधिकारियों' की नाक काट दी."

सी.बी.आई. वकील त्रिवेदी -

"सिम्पलेक्स वाले एवं अन्य समान रुप से सहभागी- कड़ी से कड़ी सजा दी जाए !

दुर्ग के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी.के. झा की अदालत में विगत २१ अप्रैल से २४ अप्रैल तक अभियोजन सी.बी.आई. की ओर से वरिष्ठ वकील श्री आर.के. त्रिवेदी ने अंतिम बहस में अपने तर्क प्रस्तुत किए. तमाम परिस्थिति जन्य साक्ष्यों एवं दस्तावेजों को सिलसिलेवार रखते हुए सिद्ध किया कि सिम्पलेक्स उद्योग के व्यवस्थापकों ने ही अन्य सह- अभियुक्तों के साथ मिलकर नियोगीजी की हत्या की ... द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की मोटर सायकल भी जब्त की गई. साक्षी सत्यप्रकाश के बयान अनुसार पल्टन मल्लाह ने उसे बताया था

साक्षी स्वामी अग्निवेश के बयान से ज्ञात होता है कि नियोगी जी ने श्रमिकों की मांग के संबंध में दिल्ली में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया

एहतियात बरती? इसे प्रश्न पर श्री त्रिवेदी ने साक्षीगण अंजोरीराम एवं बाबूलाल का हवाला दिया एवं बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से

व्यक्त की थी. नियोगी जी की पुत्री क्रांति ने अपने साक्ष्य में बताया कि उसने अपने पिता को टेप-रिकार्डर में अपनी आवाज टेप करते देखा, सुना. उसने कैसेट में अपने पिता की आवाज होने की भी पुष्टि की.

नियोगी जी ने हत्या के पूर्व रात्रि में रायपुर में इंडिया टुडे के संवाददाता एन.के. सिंह एवं पी.यू.सी.एल. के राजेन्द्र सायल से चर्चा के दौरान भी हत्या की आशंका जताई थी.

षड्यंत्र रचा एवं पल्टन मल्लाह द्वारा उनकी हत्या करवाई. सभी अभियुक्त इस जघन्य अपराध में समान रूप से भागी हैं एवं उन्हें भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा ३०२ एवं धारा १२० बी. के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का चित्रण

२८ सितंबर ९१ को सुबह ३ बजे साक्षी बहालराम की नींद धमाके की आवाज सुनी एवं उसने नियोगी जी को खून में लथपथ. गिरे हुए पाया. पड़ौसी माटेगांवकर के साक्ष्य से इसकी पुष्टि हुई. पोस्टमार्टम करने वाले डा. मेश्राम के अनुसार नियोगी जी की हत्या आग्नेय शस्त्र द्वारा हुई है. बैलेस्टिक एक्सपर्ट डा. निगम के अनुसार दो फीट की दूरी से गोली चलाई गई एवं एल.जी. कारतूसों का इस्तेमाल किया गया. हत्या में प्रयुक्त आग्नेय शस्त्र देसी कट्टा था. यह कट्टा अभियुक्त पल्टन उसके ग्राम निबहीं में बरामद किया गया. उसके कि उसने ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं सिम्पलेक्स वालों के कहने पर नियोगी जी की हत्या की थी. पल्टन द्वारा अपनी बहन संवरीबाई के नाम से बैंक में पैसा जमा करने एवं मकान के लिए ईंटा खरीदने से पुष्टि होती है कि नियोगी जी की हत्या के बाद पल्टन के पास बहुत पैसा आया.

ग्राम निबहीं में उसे देसी कट्टा. कारतूस बेचने वाले अरविंद त्रिपाठी ने अपने साक्ष्य के दौरान अदालत में पल्टन को एवं देसी कट्टे को पहचाना. रायपुर के बंदूक विक्रेता नूरुद्दीन ने भी बी.के. सिंह के साथ आकर कारतूस खरीदने वाले पल्टन को साक्ष्य के दौरान अदालत में पहचाना. साक्षी विष्णु प्रसाद सोनी के साक्ष्य से सिद्ध हुआ कि सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग के प्रबंधक विनो शाह ने दुर्ग न्यायालय में दीवानी प्रकरण दाखिल करते हुए दावा किया था कि नियोगी जी के आंदोलन, श्रमिक हड़ताल से उन्हें प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है.

या एवं अपनी जान को खतरा के संबंध में अवगत कराया था. साक्षी बसंत साहू द्वारा नियोगी जी द्वारा लिखित डायरी में हस्तलिपि की पुष्टि होती है. बसंत साहू आरोपी अभय सिंह के घर उस डायरी जब्ती का भी साक्षी है जिसमें नियोगी जी द्वारा प्रयोग में लाई गई जीप एम.पी.आर. १४३८ का नंबर उल्लेखित है. जीप मालिक एवं साक्षी रवीन्द्र कुमार के बयान से जाहिर होता है कि उक्त जीप ३-४ दिनों के लिए नियोगी जी को दिया था. ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य आरोपियों द्वारा नियोगी जी का पीछा किए जाने की पुष्टि करते हैं. साक्षी सुधा भारद्वाज ने माईक्रो कैसेट में नियोगी जी की आवाज होने की पुष्टि की. उक्त कैसेट की जब्ती साक्षी डा. पुण्यव्रत गुन के सामने हुई. उसके समक्ष ही नियोगी जी को धमकी भरा अन्तर्देशीय पत्र की जब्ती हुआ.

नियोगी जी को मिल रही धमकियों एवं उनकी जान को खतरे को देखते हुए सुरक्षा के लिए क्या हुडको (भिलाई) निवास स्थान के दरवाजे-खिड़कियों की मरम्मत एवं जाली लगाने हेतु उन्हें लाया गया था. साक्षी श्रीमती आशागुहा नियोगी द्वारा दल्ली राजहरा में पुलिस को पत्र में भिलाई के उद्योपतियों पर हत्या का संदेह व्यक्त किया था. उनमें से सिम्पलेक्स वाले भी एक हैं.

साक्षी सुदामा प्रसाद ने बताया कि मजदूरों का मांग पत्र लेकर वह सिम्पलेक्स के मूलचंद शाह. अरविंद शाह से मिला था लेकिन उन्होंने मांग-पत्र लेने से इंकार कर दिया. साक्षी ने श्रमिकों की सभाओं में उद्योगपतियों द्वारा कराए गए हमलों का भी उल्लेख किया.

जी.एम. अंसार के साक्ष्य से पुष्टि हुई कि नियोगी जी ने डायरी में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें मारने के लिए हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं. उस डायरी में अभय सिंह और अवधेश का भी नाम है. साक्षी बहलराम ने कहा कि दिल्ली से आने के बाद नियोगी जी ने अपनी हत्या की आशंका उससे

बयानों एवं दस्तावेजों से पुष्टि होती है कि नियोगी जी की हत्या के बाद आरोपी ज्ञान प्रकाश मिश्रा एवम अभय सिंह पंचमढ़ी के नीलांबर होटल में रुके थे. साक्षी टीकमदास. जो उन्हें पंचमढ़ी लेकर गया था. उसके बयान में भी इसका समर्थन मिलता है. साक्षी बंदू मिस्त्री का कथन है कि उसने उक्त ओपियों को मारुति कार दिलवाई थी. आरोप चंद्रकांत शाह के व्यवसायिक पार्टनर रहे सूरजमल जैन ने बताया है कि उसने अपनी फिएट कार चंद्रकांत को उपयोग के लिए दी थी.

अंतिम बहस सुनवाई के दौरान छ.मु.मो. के कार्यकर्त्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे. छत्तीसगढ़ की २ करोड़ जनता एवं पूरे देश की जनता की नजर इस मुकदमें पर टिकी है. अदालत और अभियोजन सी.बी.आई. अपराधियों को तौलेंगे, जनता न्याय व्यवस्था को. न्याय कसौटी पर है.

'संघर्ष और निर्माण
नए भारत के लिए नया छत्तीसगढ़

– शहीद शंकर गुहा नियोगी

सहयोग राशि– १ रूपये.

मजदूर, किसान, महिला एवं पुरूष ने जुलूस निकाला

जाने-माने देशप्रेमी वैज्ञानिक डॉ. रिछारिया को छ.मु.मो. परिवार ने याद किया

भोपाल में गोष्ठी, सार्वजनिक सभा

दिनांक ९, १० एवं ११ मई १९९७ को भोपाल में छ.मु.मो. एवं सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा डा. रिछारिया की स्मृति में विचार गोष्ठी एवं सार्वजनिक सभा का आयोजन विषय- ''जैविक प्राकृतिक टिकाऊ खेती का विकास : डॉ. रिछारिया का योगदान.''

९ और १० मई को आयोजित विचार गोष्ठी में डॉ. वन्दना शिवा की प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थिति.

११ मई की सार्वजनिक सभा के मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध पत्रकार भरत डोगरा. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता साथी जनकलाल ठाकुर द्वारा.

डॉ. रिछारिया का योगदान

देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. आर.एच. रिछारिया का ११ मई को भोपाल में निधन हो गया वे ८४ वर्ष के थे.

डॉ. रिछारिया वर्षों तक कटक स्थित केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे. तत्पश्चात वे रायपुर कृषि विश्वविद्यालय से भी सम्बद्ध रहे.

लम्बे समय से डॉ. रिछारिया नियोगी जी एवं छ.मु.मो. के कार्यक्रमों से सम्बद्ध रहे हैं. पिछले ४ वर्षों से वे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कृषि अनुसंधान कार्यक्रमों को मार्गदर्शन देते रहे हैं. ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में धान की उपज बढ़ाने एवं सदियों से प्रचलित देशी प्रजातियों के विकास से संबंधित है. उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने डंकल-प्रस्ताव का विरोध भी किया है और विकल्प के लिए कृषि-अनुसंधान एवं शिक्षण के कार्यों को भी चलाया है. इन कार्यों में डॉ. रिछारिया का मार्गदर्शन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है.

२८ सितम्बर १९९३ को नियोगी जी के शहीद दिवस पर भिलाई में लाखों लोगों की सी को सम्बोधित करते हुए वयोवृद्ध वैज्ञानिक डॉ. रिछारिया ने यह मार्मिक आव्हान किया था'' भिलाई इस्पात नगरी है. आप लोग इस्पात का निर्माण करते हो. हर काम के लिए अपना बनाया इस्पात काम में आता है. धान पैदा करने के लिए भी इस्पात काम आता है. नागर, गैंती, हंसिया में भी आपका बनाया इस्पात काम आता है, लेकिन इस्पात के साथ साथ धान भी उतना ही जरूरी है. खाना खाओगे-तभी तो कमाओगे. छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़ में २० हजार से अधिक किस्मों का धान पाया जाता है. गुरूमटिया, लुचई, दुबराज, सफरी, अजान, बैंकुनी आदि २२ हजार मिस्में है यदि यहां के किसानों को सही व्यवस्था दी जाए तो अकेला छत्तीसगढ़ पूरे हिन्दुस्तान का पेट पाल सकता है. लेकिन आज विदेशी कंपनियां लालच भरी नजरों से छत्तीसगढ़ की ओर देख रही हैं. वे छत्तीसगढ़ के भिन्न-भिन्न किस्मों को नंगाना चाहती हैं. नियोगी जी का भी यही सपना था कि छत्तीसगढ़ के धान की सम्पदा की रक्षा की जाए एवं एक बार फिर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाया जाए''.

पानी समस्या का निवारण हो

साथी जनकलाल ठाकुर ने जिला प्रशासन को चेताया

डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के डौंडी विकासखंड एवं डौंडी लोहारा विकासखंड में बहुत सारा बांध की नाली एवं बांध अधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे उसकी मरम्मत करना अत्यंत आवश्यक है तथा कुछ कार्य निर्माण में रूप में अंधेरे है. अतः दोनों विकास खंडों के समस्या मूलक कार्यों का निदान करने की कृपा करेंगे.

-डौंडी लोहारा विकास खंड-

१. क्षतिग्रस्त बगईकोन्हा बांध मरम्मत एवं नाली विस्तार कार्य.

२. ग्राम भीमपूरी में स्टापडेम निर्माण कार्य.

३. ग्राम बंजारी में स्टापडेम निर्माण कार्य.

४. टेकापार बांध से कुरुभाट के लिए नाली विस्तार कार्य.

५. केरी जुगेरा बांध मरम्मत कार्य.

६. गोंदली जलाशय से चिल्हाटी के लिए नाली निर्माण कार्य.

-डौंडी ब्लाक-

१. ग्राम पटेली के क्षतिग्रस्त बांध का मरम्मत कार्य.

२. ग्राम भर्रीटोला व्यवर्तन का नाली मरम्मत एवं पुलिया निर्माण कार्य.

३. ग्राम कुसीटिकुर उर्फ जनकीहड़ा बांध का उलट एवं नाली मरम्मत कार्य.

४. भोइरटोला जलाशय में मेन नाली का मरम्मत एवं विस्तार कार्य.

५. बकलीटोला जलाशय का मरम्मत कार्य (क्षतिग्रस्त).

६. मरकाटोला उर्फ सुरडोंगर में श्रमदान द्वारा बनाया गया नाली का मरम्मत एवं स्टापडेम निर्माण कार्य.

छोटी-छोटी नदियां मिलकर महानदी बनती है
अनेक कल-कारखानों के मजदूर मिलकर महातीर्थ बनता है
एकता की पुकार लेकर
आओ । हम, नया भिलाई बनायें ।

साथियों,

भिलाई के पूरे उद्योगों में खलबली मची हुई है और सिम्पलेक्स बी. ई. सी., केडिया, बी. के. बी. को, भिलाई वायर्स, जनरल फेब्रीकेटर्स, गोलछा, केमिकल, ज्ञान रिरोलींग मिल्स जसवंगल स्टील इन्टरप्राईजेज भिलाई आक्सीजनरी, इन्डस्ट्रीज विश्व विशाल, पूज स्टार ए. सी. सी. सभी उद्योगों में मजदूर हिम्मत के साथ हरा झंडा अपनाकर अधिकार की बात कर रहे है ।

भिलाई के मेहनतकश मजदूरों ने एक के लिए सब, सबके लिए एक यह विचार के तहत मजदूरों में अटूट एकता कायम हो सकता हैं, यह पहले कभी नहीं सोचा था ।

आज भिलाई के उद्योगपतियों की धड़कन बढ़ चुकी है । वे चमचों को इकट्ठा कर रहे हैं, बेईमानों को हराम का खाना खाने का पर्याप्त सुविधा प्रदान कर रहे हैं । कुल मिलाकर मालिक फिकर में पड़े है । उन्हें मालूम हो गया है कि इस एकता के सामने उनकी शोषण की व्यवस्था नहीं चलेगी ।

मजदूर एकता बनाकर, एकता का गाना गाते हुए, एकता का हथियार से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये कदम-कदम आगे बढ़ रहे हैं ।

मजदूर नारा लगा रहे है,
हमें न्याय चाहिये,
हमें मुक्ति चाहिये,
हमें इज्जत चाहिये,
हमें निश्चित भविष्य चाहिये ।

आईये, विश्वकर्मा पूजा के पावन दिवस पर एकता का बांध बनाकर नये भिलाई का निर्माण करें ।

मजदूर एकता जिंदाबाद
लाल-हरा झंडा जिंदाबाद
शहीद साथी अमर रहे ।

पूनम बामनकर	**जनकलाल ठाकुर**	**एन.आर. घोषाल**
प्रगतिशील ट्रान्सपोर्ट श्रमिक संघ	अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	महामंत्री इस्पात श्रमिक संघ, भिलाई

दिनांक १७-९-९० दिन सोमवार को इंडस्ट्रीयल स्टेट मैदान में (एम.पी.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड के पास) आमसभा में भाग लीजिए । हर कारखाना से जुलुस लेकर सभा स्थल पर आना है । समय - दोपहर १ बजे

बजाज प्रिंटर्स, राजहरा

...ों और भाइयों पर कैलाशपति केड़िया गुण्डों के जरिए प्राण घा... ...मला करवा रहा है ।

यहां 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण' प्राप्त नहीं है ।

इस्पात मजदूर साथी, क्या आप अब भी चुप रहना पसन्द करेंगे ?

दोस्तों,

दिन सोमवार, १९-८-९१, शाम को ५.३० बजे प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष श्री उमाशंकर राय, सेक्टर १ स्थित अपने घर जाने की तैयारी में थे । अचानक कैलाशपति केडिया के ठेकेदार एवम् गुण्डा संतोष गुप्ता का भाई मनोज गुप्ता, बबली आत्मज गोना चौधरी व एक अन्य व्यक्ति प्रिया स्कूटर से आकर बिना किसी कारण श्री उमाशंकर राय को चाकू एवम् राड से मारकर अधमरा कर दिया ।

श्री उमाशंकर राय के पिता श्री जे. राय, भिलाई इस्पात संयंत्र के वायर राड मिल में कार्यरत है इनके दो पुत्र श्री उमाशंकर, सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग में व दूसरे श्री अरविन्द राय केड़िया डिस्टीलरी में कार्य करते है । लाल-हरा की नई युनियन बनने पर ये दोनों भाई इस यूनियन के सदस्य बने ।

वायर राड मिल में कार्यरत श्री जे. राय के जेष्ठ पुत्र श्री उमाशंकर को चाकू से मार कर प्राण घातक हमला किया गया । ... कोई नई घटना नहीं है । इससे पूर्व में भी दर्जनों मजदूर एवं मजदूर नेताओं पर इस प्रकार प्राण-घातक हमला किया जा चुका है । जब श्री उमाशंकर चाकू की मार सहते रहे उस समय जामुल थाना के टी. आई. शिवलाल सलाम, वहीं पर खड़े-खड़े देख रहे थे । हकीकत तो यह है कि कैलाशपति केड़िया ने अपने लाड़ले गुंडों की सुरक्षा के लिए ही टी. आई. सलाम की वहां ड्यूटी लगाई थी । उद्योगपतियों की इस प्रकार के शर्मनाक करतूतों को पुलिस एवं जिला प्रशासन पूर्ण रुप से संरक्षण दे रहा है । उद्योगपतियों को मदद करने के लिए ही जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी को २ महीने तक जेल में बंद करके रखा, उन पर जिलाबदर की कार्यवाही चलाई गई और अब भूखे मजदूरों पर बारी-बारी प्राण घातक हमले करवा कर उद्योगपति अपने लूट के साम्राज्य को बनाए रखना चाहते है ।

गत १० महीनों से भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर स्थायीकरण एवं जीने लायक वेतन के लिए संघर्षरत है । बेरोजगारी की समस्या इतनी खतरनाक बन चुकी है कि इस्पात मजदूरों के बेटे अगर सिम्पलेक्स, केड़िया, बी. के., बी. ई. सी, आदि उद्योगों में ...हीं नौकरी करते है, वहां उन पर अमानवीय शोषण होता है और नहीं तो इन उद्योगपतियों के, विशेष रुप से कैलाशपति केड़िया या मूलचंद शाह व बी. आर. जैन या बी. के. कम्पनी वालों के रखैल गुंडा सरदारों के गैंग में शामिल हो उनकी चक्कू, कट्टा वाहिनी के सदस्य बन कर अपना जीवन बरबाद कर देते है ।

मजदूरों के संगठन बनाने के अधिकार को वे, येन-केन प्रकरेण छीनते हैं ।

मजदूर एवं भिलाई के आम नागरिकों के जान और माल की रक्षा भी इन पूंजीपतियों के चलते नहीं हो पा रही है ।

हमारे ऊपर अनेकों हमले हुए है, कल और खतरनाक हमलों के दौर से हमें गुजरना होगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर अपनी मांग पूरी किये बिना नहीं रुकेंगे । इसलिए ऐसी भी घटना हमारे ऊपर हो सकती है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएगें । उस दिन साथियों उठ खड़े होना, अगर वह भी संभव न हो फिर हमारी कुरबानी को याद कर दो बूंद आंसू टपका देना ।

लाल जोहार !

लाल-हरा झंडा जिन्दाबाद ! **शहीद साथी अमर रहे !**

आपका

जनकलाल ठाकुर
(अध्यक्ष, छ. मु. मो.)

शंकर गुहा नियोगी
(संगठन मंत्री, सी. एम. एस. एस.)

अनूप सिंह
(...तिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ)

सुधा भारद्वाज
(सचिव, छ. मु. मो.)

भीमराव बागड़े
(अध्यक्ष, सी. बी. एम. एम. एस.)

बजाज प्रिन्टर्स, राजहरा

छत्तीसगढ़ न्यायाग्रह बर 9 दिसम्बर के बिलासपुर म प्रदर्शन

कतको गंभीर मुद्दा के ऊपर हमर न्याय के आग्रह हे, हमन चाहत हन के न्यायिक समुदाय म एखर चर्चा हो। फेर बिलासपुर हाईकोर्ट के पिछला दो बछर के हालात अइसन हे कि एक धन पांच (1+5) के हाईकोर्ट म लगातार तीन या चार जज मन के सीट खाली है। प्राय- सब्बो प्रकरण म लगातार विलंब होवत हे, जेन ह जज मन के नियुक्ति के अभाव की Structural Situation (ढांचागत स्थिति) के सेती होए हे।

अऊ जैसा कि कहावत है - Justice Delayed is Justice Denied. (न्याय म देरी न्याय से वंचित रखे बराबर हैं) हमन तो अपन न्याय के मांग ल उचाए बर बिलासपुर प्रदर्शन करबो कहत रहेन - फेर हाईकोर्ट के हालात ल देख के, सबले पहिली तो इहीच मांग उचाए ल पड़त हे -

Appoint Judges at Bilaspur High Court Without Further Delay

and thus,

Rectify the Structural Situation of Denial of Justice.

(बिलासपुर हाईकोर्ट म तत्काल जज मन के नियुक्ति करो! न्याय वचन के ढांचागत स्थिति ल सुधार करो !!)

छत्तीसगढ़ न्यायाग्रह के प्रमुख बिन्दु :

(1) नौजवान मन ल रोजगार दो।

(2) भिलाई आन्दोलन के श्रमिक मन ल न्याय दो ॥

(3) अपराधी - पुलिस सांठगांठ से न्याय ल मुक्ति कराए के रास्ता खोजना। (To think of the way out the very prevelent situation of criminal-prosecution nexus which renders judiciery helpless on so many occasions.)

(1) ''बेरोजगारी दूर कर रोजगार देना संवैधानिक जिम्मेदारी''

Art. 39 - The state shall in particular, direct its policy towards securing -

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

(c) that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;

Art. 41) The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance incases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

संविधान के Art. 21 (जिए के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के कई न्याय दृष्टांत के अनुसार जेमा जीवन यापन के अधिकार घलो शामिल हे) Art. 39 (b), 39 (c), & 41 के संग पढ़े म स्पष्ट हे कि बेरोजगारी दूर कर रोजगार देना सरकार के संवैधानिक जिम्मेदारी हे।

हमर संविधान लागू होए के बहुत पहिली, वर्ष 1898 म राजनांदगांव के राजा बलराम दास ह अकाल क्षेत्र के जनता ल रोजगार देए बर, कपड़ा मिल के स्थापना करे रिहीस।

फेर आज के शासक संविधान के नीति निर्देशन के अवहेलना करत बी.एन.सी. मिल ल बन्द करत हें। कतीक शर्म के बात हे !

ऐखरे सेती, हमर न्यायाग्रह हे,

- नगरनार के प्रस्तावित स्टील प्लांट म 4000 स्थानीय नौजवान मन ल रोजगार दो।
- दल्ली राजहरा अऊ रावघाट के लोहा खदान म अर्धमशीनीकरण के नीति अपना कर हजारों नौजवान मन ल रोजगार दो।
- ग्राम जंजगिरी के भूमि अधिग्रहित 73 किसान परिवार के नौजवान मन ल रोजगार दो।
- छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग राजनांदगांव बी.एन.सी. मिल ल चालू करो। नौजवानो को रोजगार दो।

(2) भिलाई आन्दोलन के श्रमिक मन ल न्याय दो।

क्या भिलाई के मालिक - उद्योगपति सहानुभूति के पात्र है ?

शहीद शंकर गुहा नियोगी के सिपाही, भिलाई आन्दोलन के श्रमिक 12 बछर ले संघर्ष के मैदान म डटे हे। अदालत म घलो इंडस्ट्रीयल कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 18 जज मन के फैसला ऊंखर पक्ष म आए हे।

मेरिट म मजदूर मन के बर्खास्तगी अवैध साबित होए हे।

अईसन स्थिति म देशके कानून स्पष्ट हे, न्याय दृष्टांत म बताए गए हे कि अइसन स्थिति म पूरे बकाया वेतन सहित पुनः स्थापना ही नियम है. अऊ आधार बताए हे कि -

<u>1978 Vol. II LLJ Page 474 S.C.</u>

<u>Hindustan Tin Works Vs Its Employees</u>

"Speaking realistically, where termination of service is questioned as invalid or illegal and the workman has to go through the grant of litigation, his capacity to sustain himself throughout the protracted litigation is such an awesome factor that he may not survive to see the day when relief is granted."

अऊ एक न्याय, दृष्टांत म

legendry jurist Justice Krishna Iyer has observed :

"......... We cannot sympatize with a party who gambles in litigation to put off the evil day and when that day arrives prays to be saved from his own gamble. .... The logistics of litigation for indigent workmen is a burden the management tried to use to a covert blackmail through the judicial process. ....

<u>(1980 Vol. II, L.L.J. Page 124 S.C.)</u>

भिलाई के उद्योगपति देश के कानून अऊ अदालत के अवमानना बतौर दिनचर्या करथैं।

जब भिलाई के उद्योगपतियों ने जस्टिस दीपक वर्मा को घूस देने का प्रयास कर म.प्र. हाईकोर्ट की घोर अवमानना की

2 सितम्बर 96 खुली अदालत म उद्योगपतिमन के वकील श्री ए.एम. माथुर के के आघू म फाईलें पटकत जस्टिस दीपक वर्मा ह किहीस कि अपन क्लाएंट ल समझाऐ, कल 4 लोगों ने आकर ओला रिश्वत देए के प्रयास करे के हिमाकत करीस।

जस्टिस दीपक वर्मा ह मुख्य-न्यायाधीश ल अपन ऐदे नाराजगी ल सूचित करत सुनवाई ले स्वयं ल अलग कर लीस।

छ.मु.मो. ह इन्दौर के तोकोगंज थाना म रिपोर्ट दर्ज करवाईस अऊ मांग करीस कि प्रकरण के अनुसंधान कर अतीक बड़े कन्टेम्प्ट के दोषी व्यक्ति मन ला सजा दिलाया जाए।

भिलाई के उद्योगपतियों द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय के घोर अवमानना : स्वयं मुख्य-न्यायाधीश ह स्वीकार करे हे

'सुप्रीम कोर्ट नें आज खुलासा किया कि हवाला मामले में उन पर जबरदस्त बाहरी दबाव है...... न्यायाधीश ने कहा कि मामले से हाथ खींचने के लिए काफी समय से दबाव पड़ रहा है।.... श्री वर्मा ने खुलासा किया कि एक व्यक्ति ने उनसे मिलने की कोशिश की। फिर वहीं व्यक्ति एस.सी.सेन से मिला (सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश) वे चिंतित थे। श्री वर्मा ने बताया कि आज उन्होंने न्यायमूर्ति भरूचा से संपर्क किया।' (जनसत्ता । 5 जुलाई 97)

अब बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा न्याय प्रदानता के प्रयास के घलो ये उद्योगपति मन धज्जियां उड़ाईन हें।

जेन हजारों मजदूर मन के बर्खास्ती अवैध साबित होए हे - वो मन ल पुनः स्थापना के एवज म एक मुश्त राशि के आदेश औद्योगिक न्यायालय द्वारा करे गे हावे। फेर ट्रायल कोर्ट द्वारा मरिट म जीत के बावजूद उद्योगपति मन बिना कोई स्टे आर्डर के मजदूर मन ल रिलीफ ले महरूम रखीस।

बिलासपुर हाईकोर्ट ह श्रमिक मन के अन्तरिम राहत के आवेदन के ऊपर अऊ उद्योगपति मन के सहानुभूति राहत के आवेदन के ऊपर एक मुश्त मुआवजा राशि के ब्याज भुगतान करे के आदेश करीस।

तभो ले आज भी सैकड़ों मजदूर मन के तो एक ओ पइसा ब्याज राशि ये उद्योगपति जमा नहीं करीन हे।

जबकि ये मजदूर मन शपथ पत्र जमा कर चुके ह वे।

इहीच उद्योगपति मन जो स्वयं अपन कम्पनी ले 14% वार्षिक के दर से ब्याज प्राप्त करथे, फेर मजदूर मन ल 4% वार्षिक के दर से ब्याज दे के अन्तरिम राहत के हाईकोर्ट के आदेश के मजाक उड़ावत हे।

शासन तन्त्र, अपराधी नेक्सस आज राज करत हे -

कुछ उदाहरण

Frontline dated 29 March 2002 के अनुसार :

★ High Court judge Justice Akbar Divecha's house was burned down

and

★ another high court judge Justice M.F. Kadri had to be evocuated after his house was attacked.

★ उही मन संवैधानिक ऑथोरिटी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जे.एस. वर्मा अऊ चुनाव आयोग के अध्यक्ष श्री लिंगदोह ल भी निशाना बनाईन।

What is striking is that these ar very forces which have been illegally and forcibly looting and exploiting common people, workers and peasants as a routine.

★ हमर छत्तीसगढ़ म मन्त्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश म जौन तरीके से अपराधी पुलिस सांठगांठ उजागर होए हे, तेन ह अभूतपूर्व हे, जेला सैकड़ो निरपराध, गरीब, किसान अऊ महिला तको ला भुगताए ज...

★ नियोगी जी के हत्यारा उद्योगपति मन की प्रभावशालिता।

ये सब के छत्तीसगढ़ न्यायाग्रह के चर्चा शीघ्र अगामी दौर म।

Legendry Jurist Justice V.R. Krishna Iyer's reflections on Chhattisgarh Nyayagraha...

28 सितम्बर 92 को दिल्ली के जस्टिस कृष्ण अय्यर के भाषण के अंश अंग्रेजी में और उसका छत्तीसगढ़ अनुवाद)

'संविधान के उद्देशिका मा लिखाए गए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के राष्ट्र मन ल नियोगी गजब गंभीरता से सोचे रिहीस अउ अपन जम्मो जीवन अउ जम्मा मृत्यु म भारत के लोग मन ल हर तरीका मा स्वतंत्र करे बर अइसन योगदान करे हे, जेला कभू नई भुलाई जा सकय।

गुंडा पालने वाला शोषक माफिया के खिलाफ म अउ राज्य के भ्रष्ट पुलिस अउ राजनेता मन के खिलाफ लड़ाई म मजदूर वर्ग ल शंकर गुहा नियोगी के रूप म अइसन नेता मिलीस जेखर दृष्टिकोण हमेश सामाजिक न्याय रिहीस अउ जउन हा मैनेजमेंट आतंकवाद, ठेका प्रथा के गुलामी अऊ सरकारी मिलीभगत के तहत कानून गैर-परिपालन के खिलाफ संघर्ष के संकल्प करे रिहीस।''.....

'छत्तीसगढ़ के आन्दोलन ह आज के संवैधानिक-न्यायिक न्यायपालिका व्यवस्था के ऊपर मा जीता-जागता टिप्पणी हरे - का ये दे व्यवस्था मात्र भ्रष्ट हे या फिर ये हा स्वयं दमन के औजार बनत जात हे ?

शासन तन्त्र अऊ कतको निहित स्वार्थ समूह के सांठगांठ जनता के संवैधानिक अऊ लोकतांत्रिक अइधकार से ज्यादा मजबूत दिखथै।

"Niyogi took the diction in the Preamble to the Constitution Justice, Social, Economic and Political, seriously and devoted his whole life and his whole death to the immortal cause of making Indians free in every dimension of existence. The workingclass and its struggle against the exploitative mafia who hired lumpen hirelings and corrupted the State Police and politicians found Shankar Guha leader with a passion, whose vision was always set on social justice and whose mission was liberation of labour in a do or die definace of Management terrorism, 'contract labour' serfdom and state-connived stratagem of law non enforcement....."

"The Chattisgarh movements are a continuing commmnt also on the prevailing constitutional legal judicial system. Is this system merely inefective or is it becoming an instrument of oppression ?

The nexus between the state machinery and diverse vested interests is stronger than its concern for the constitutional and democratic rights of the people."

विनीत - छत्तीसगढ़ प्रगतिशील युवा संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

जिस थाली में खाते हैं- उसी में छेद करते हैं !

भिलाई के ये पांच पूंजीपति लोटा धर के छत्तीसगढ़ में आये थे. कैलाशपति केड़िया, साईकल पर टीना धरके शराब बेचता था. हीरा भाई शाह ने एक लेथ मशीन के साथ बोरिया गेट के सामने छप्पर में वर्कशॉप शुरू किया था. बी.एस.पी. के पब्लिक माल को प्राइवेट बना-बनाकर उसने औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया है. छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास, भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ जुड़ा है. सिम्पलेक्स बी.के., बी.ई.सी. आदि भी कच्चे माल एवं आर्डर के लिए बी.एस.पी. पर निर्भर हैं. आज ब.रा.क. ने बी.एस.पी. एवं भारत के अन्य बड़े उद्योगों के विनाश की योजना बनाई है. ये नव धनाढ्य हवाला आदि के माध्यम से ब.रा.क. के भाड़े के टट्टू बनकर उस साजिश के हिस्सेदार बन गए हैं, जो छत्तीसगढ़ और भारत के आत्मनिर्भर विकास की संभावना को चकनाचूर करने के लिए बनाई गई है. अपने तुच्छ निजी स्वार्थों के लिए ये देशद्रोही पूरे छत्तीसगढ़ अंचल को हिंसा-आतंकवाद की आग में झोंकने से भी नहीं हिचकेंगे मगर छत्तीसगढ़ के मेहनतकश भी इन्हें सबक सिखाने की ठान चुके हैं.

शहीदों की खून-सींचे कुर्बानी की राह पर चलकर....

नियोगी जी के सच्चे सिपाही बनकर अटूट मनोबल, कुर्बानी का रास्ता और देश प्रेम से नया इतिहास रच रहा है भूखा मजदूर. ***नये भारत के लिए नया छत्तीसगढ़*** हेतु स्वतंत्रता संग्राम संचालित कर रहा है.

चल मजदूर चल किसान, देश के हो महान
तोर संग-संग मा चलहि बनिहार
जुर-मिल के सबो झन, शोषण ला टारबो
छत्तीसगढ़ दाई के हावे रे गुहार!

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

न्याय के तकादा हवे छत्तीसगढ़ के

* नियोगी जी के हत्यारे पूंजीपति मन ला धारा १०९/३०२ मा फांसी दो।
* पूंजीपति के निजी सेना ऊपर प्रतिबंध लगाओ।
* छत्तीसगढ़ मा आतंकवाद के बीज बोने वाला कैलाशपति केडिया ला रासुका तहत गिरफ्तार करो।

- यदि सबकी नजरों के सामने डेढ वर्ष तक फरार रहे हत्यारे चन्द्रकान्त शाह को सजा से बरी कर दिया गया तो क्या छत्तीसगढ में किसी भी गरीब इन्सान की अपराधियों से सुरक्षा हो पाएगी ?
- दिग्विजय सिंह, चन्द्रकान्त शाह की फरारी के लिए जिम्मेदार फासिस्ट पटवा पर १०९/२२१ का मुकदमा क्यों नहीं चला रहे हैं?

▪ देश प्रेमी विकास ▪ रोजी-रोटी का अधिकार, चाहिए

- काम से वंचित समस्त औद्योगिक श्रमिकों को वापस लो. जीने के लायक वेतन दो.
- छत्तीसगढ के तमाम उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो.
- भिलाई इस्पात संयंत्र के अंधाधुंध मशीनीकरण पर रोक लगाओ. मशीन नहीं मानव के आधार पर उत्पादन वृद्धि हेतु कम से कम ३० हजार मजदूरों की नई भर्ती की जाये.
- उद्योगों में रोजाना दुर्घटनाओं पर रोक लगाओ, जिम्मेदार मैनेजरों, उद्योगपतियों को गिरफ्तार करो.
- गंगाबाई के हत्यारों पर कार्यवाही करो.
- भिलाई एवं कुम्हारी में केडिया के प्रदुषण पर रोक लगाओ.
- भूमिहीनों को जमीन दो, कब्जाधारी को पट्टा दो. राजाराम गुप्ता, धरमपाल गुप्ता, दिलीप सिंह जुदेव, वासुदेव चंद्राकर आदि सीलिंग से सैकड़ों एकड़ अधिक बेनामी जमीन रखने वाले धनपतियों पर सीलिंग एक्ट के तहत कार्यवाही हो.
- वन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों के अत्याचारों पर रोक लगाओ.
- सभी स्कूलों को पर्याप्त शिक्षक एवं अस्पतालों में डॉक्टर-दवा उपलब्ध कराओ.
- ब.रा.क. के इशारे पर सिचांई, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि में सबसिडी में कटौती बंद करो.
- छत्तीसगढ में पूर्ण शराब-बंदी लागू करो. दूरदर्शन, फिल्मों, पत्रिकाओं में अश्लील प्रसारणों पर रोक लगाओ.

ऐ जालिमों देखेगें हम कितनों को तुम मारोगे
जीत हमारी निश्चित है हम जीतेगें तुम हारोगे

शोषण से मुक्ति पाना है, एकता बना लो बड़ा महान...
जागो दुनिया के मेहनतकशों साथी-मजदूर और किसान
शोषित-पीड़ित जनता के लिए है बलिदान नियोगी का
मार सकते हैं दुश्मन उसे पर कटे न विचार नियोगी का।
एक नियोगी के शहीद होने से और नियोगी पैदा हुए
एक जुलाई सन् ९२ को सोलह और बलिदान दिए,
ये कुर्बानी होती रहेगी, जब तक न मिटे शोषण का राज।
एक शहीद के हो जाने से सौ-सौ पैदा होएंगे,
सौ से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़ पैदा होंगे
ऐ जालिमों देखेंगें हम कितनों को तुम मारोगे।
जीत हमारी निश्चित है हम जीतेगें तुम हारोगे॥
कितनी चलाओगे गोली-हर व्यक्ति का सीना तन जायेगा,
मेहनतकश का हर बच्चा फिर, फिर गुहा नियोगी बन जायेगा।
गूंज जाएगी ये धरती में इंकलाब की उठे आवाज।

जन कवि फागूराम यादव

शहीद मन के लहू कभू फोकट नई होए,
न कभू होइस।
जौन भूईयां मा शहीद मन के लहू गिरे हे,
वो माटी हा चन्दन बन गे हे॥

हमर किसान-मजदूर संगवारी मन ला झारा-झारा नेवता।

वीर नारायण सिंह अऊ शहीद शंकर गुहा नियोगी के रद्दा मा चल के कुर्बानी देने वाला छत्तीसगढ़ के हमर बहादुर शहीद मन के जीवन ले प्रेरणा लेए १ जुलाई १९९३ के दिन भिलाई मा सकलाहू अऊ छत्तीसगढ़ के किसान-मजदूर महासम्मेलन ला सफल बनाहू।

लाल जोहार!

लीला बाई
अध्यक्षा, महिला मुक्ति मोर्चा

आशा गुहा नियोगी
महिला मुक्ति मोर्चा

जनकलाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

मुद्रक – विजय प्रिंटिंग प्रेस, बालोद

छत्तीसगढ़ की राजनीति

भिलाई इस्पात संयंत्र के आसपास के उद्योगपतियों की जेब में है।

छत्तीसगढ़ की जनता ने भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए तमाम संसाधन दिए। लेकिन उसका फायदा केवल बी. आर. जैन, विजय गुप्ता, हीराभाई शाह जैसे नवधनाड्यों और उसके हमजोली तकनीकशाहों कृष्णामूर्ति व शेखर ने उठाया और हजारपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बनते गए। प्रेमप्रकाश पांडे, कैलाश शर्मा, चन्दूलाल चंद्राकर, रवि आर्या, मोतीलाल वोरा, वी. सी. शुक्ला और बृजमोहन अग्रवाल आदि तमाम राजनेता और सेन्ट्रल ट्रेड युनियन नेता चुनावी फंड के लिए इस होड़ में लगे हैं कि कौन ज्यादा वफादार हैं ?

अब सवाल है कि—

(१) १९८९ में जब उद्योगपति मनोज जायसवाल के निजी गुंडों ने व पुलिस ने ग्राम अंजोरा के ग्रामवासियों पर अत्याचार ढहाए थे तो राजनेताओं की क्या भूमिका थी ?

(२) ग्राम कुथरेल में बी. आर. जैन के गुंडे सेक्यूरिटी गार्डों ने ग्रामवासियों को चाकू-बिछवा दिखाया था और ग्रामवासी आन्दोलित हुए थे, तब तमाम राजनेताओं की क्या भूमिका थी ?

(३) प्रदूषण से सैकड़ों गांवों के जीवन को नरक बनाने वाले जिस कैलाशपति केडिया के पहलवान व गुंडे लगातार छतीसगढ़ के ग्रामवासियों पर कातिलाना हमले करते जा रहे हैं, उसके दरबार में सभी राजनेता हाजिरी लगाने क्यों जाते हैं ?

(४) क्या लाखों जनता की आंख के तारे शहीद शंकर गुहा नियोगी की हत्या, छत्तीसगढ़ के मासूम बच्चों, महिलाओं पर गोली चालन और गरीब जनता के लिए कुर्बानी देने वाले मजदूर नेताओं का० शेख अंसार, का० एन. आर. घोषाल और का० मेघदास वैष्णव को ११ महीनों तक जेल की काल-कोठरी में रखने के लिए सभी राजनेताओं की उद्योगपति के साथ मिली-भगत नहीं है ? क्या चन्द्रकान्त शाह की फरारी भी इन सबकी भागीदारी नहीं है ?

(५) गोलीकांड की जांच की घोषणा के बाद भी कांग्रेस व भा. ज. पा. ने अभी तक जांच क्यों नहीं करवाई है ?

(६) क्या नव-धनाड्यों की जेब में बैठने वाले राजनेता छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए कुछ कर पाएगें ?

हम इन दलाल राजनेताओं का भरोसा नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आव्हान करता है कि गांव-गांव में, मजदूर, किसान, नौजवान, महिला अपना संगठन बनाएं और रोजी-रोटी के अधिकार के लिए, इज्जतदार जीवन के लिए, और छत्तीसगढ़ के सही विकास के लिए चर्चा चलाएं और मीठा-मीठा सपना दिखाने वाले राजनेताओं को अपने गांवों में नहीं घुसने दें।

शहीद शंकर गुहा नियोगी अमर रहे.... २८ सितं. शहीद दिवस भिलाई चलो...

नियोगी भैया, तुमने तूफान में दिया जलाना सिखाया है

तुंहर नाव के दिया ला जलाबों !

छत्तीसगढ़ के लुटईया मन ला सबक सिखाबों !

ये नवधनाढ्य छत्तीसगढ़ की आवाज को कुचलना चाहते हैं –

गांधी जी के सत्याग्रह के तर्ज पर नियोगी जी के सिपाही छत्तीसगढ़ में न्यायाग्रह करेंगे.

शहीद शंकर गुहा नियोगी का हत्यारा चन्द्रकांत शाह डी.के. अस्पताल से फरार हो जाता है. रायपुर का सी.जे.एम. पुलिस द्वारा अभियोजन ठीक पेश नहीं करने का हवाला देकर बरी करता है. हजारों जनता के बार-बार मांग करने पर भी सुन्दरलाल पटवा, तत्कालिन उद्योगमंत्री कैलाश जोशी को गोलीकाण्ड जांच आयोग के समक्ष बुलाया नहीं जाना. भिलाई, कुम्हारी, उरला, टेडेसरा, का मजदूर संविधान का पालन हो सके इसलिए लालहरा झण्डा लेकर लाठी-गोली जेल व भूख प्यास हर मुसीबत को पार कर आगे बढ़ते जा रहे हैं.

आज सिर पटक रहे हो ! कल नाक भी रगड़ोगे :– हवालिया बी.आर. जैन, हत्यारा मूलचंद, शैतान केडिया, कुलदीप गुप्ता जैसे नवधनाढ्यों को बहुत घमंड था, ये कहते थे.... भिलाई से दिल्ली तक नोट बिछा देंगे. इसी तर्ज पर ये चारों फटीचर एक सितम्बर ९६ की रात माननीय न्यायाधीश दीपक वर्मा को घूस देने का कुप्रयास किया. दिनांक २ सितम्बर ९६ को जस्टिस दीपक वर्मा ने भरी अदालत में इन चारों के वकील माथुर को लताड़ा. हर कुकर्म करने के बाद भी वे असफल हो रहे हैं. भूखा मजदूर उद्योगपतियों के षड़यंत्र, नापाक मनसूबों को ध्वस्त करते हुए एक-एक कदम आघु बढ़ रहे हैं.

अमीर देश की गरीब जनता :– छत्तीसगढ़ में इतनी सम्पदा की भरमार है- दल्ली-राजहरा में लोहा पत्थर, चिरीमरी (बिलासपुर) में कोयला, नंदिनी में चूना पत्थर, हिर्री व कोदवा में डोलोमाईट है. शिवनाथ, अरपा, महानदी, इन्द्रावती, पैरी, खारून नदियों का पानी है, घने जंगल है, उपजाऊ जमीन है. इतने साधन हैं कि यहां के तमाम एक करोड़ सत्तर लाख जनता सुख और खुशहाली का जीवन बिता सकती है. तो यह भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, पलायन क्यों ?

तान्दुला का पानी जहां अंग्रेजी काल में पहुंचता था, आज वे खेत सुखे हैं. हमने भिलाई इस्पात संयंत्र की प्यास बुझाने के अपने तान्दुला, खरखरा, गोंदली, गंगरेल बांधों का पानी दिया. मगर भिलाई इस्पात संयंत्र, बी.के., बी.ई.सी., सिम्पलेक्स जैसे लालची उद्योगपतियों का चारागाह बनकर रह गया.

जब वक्त पड़ा गुलिस्तां को खून हमने दिया,
जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं !

दलालों का रास्ता :– उद्योगपति हवालियों के काले धन के बल पर चुनाव लड़ने वाले दलबदलु, भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी व अय्यासी की कीचड़ में फंसे तमाम राजनैतिक दलों के कर्णधार, हमारी गंभीर समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे. जब-जब किसानों ने पानी मांगा तब-तब सरकार ने (भाजपा हो या कांग्रेस) लाठियां ही बरसाई, मजदूरों ने न्याय के लिए आवाज उठाई, काम बेदखल किये गये, गोलियों से भून दिये गये.

शहीदों का रास्ता :– इस अंधेरगर्दी में शहीदों के बनाये जन संगठन और जन आंदोलन के रास्ते पर चलकर ही हम छत्तीसगढ़ को लूट व शोषण से मुक्त कराकर एक सुन्दर शोषण हीन छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकते हैं. शहीद शंकर गुहा नियोगी ने यही रास्ता दिखाया था. आओ शहीद शंकर गुहा नियोगी के बताये रास्ते पर चलें, नये भारत के लिए नया छत्तीसगढ़ की सोच लेकर अपना गांव बनायें, अपना देश बनाये.

नवा छत्तीसगढ़ राज्य बनाए बर

१. छत्तीसगढ़ ले ठेकेदारी प्रथा बंद.
२. स्थाई उद्योगों में स्थाई मजदूर अऊ जीए के लाईक वेतन बर श्रम कानूनों के पालन कराए बर.
३. शराब-विहीन छत्तीसगढ़ बनाए बर.
४. अंधाधुंध मशीनीकरण उपर रोक अऊ बी.एस.पी. अऊ खदान मन में नौजवान मन ला रोजगार बर.
५. छोटे-छोटे सिंचाई योजना से छत्तीसगढ़ के समस्त कृषि-भूमि मां सिंचाई बर.
६. किसान मन ला भूमि के पट्टा बर उद्योगपति, मालगुजार मन द्वारा जमीन हड़पने ऊपर रोक लगाए बर.
७. किसान मन ला उपज के वाजिब दाम बर.
८. छत्तीसगढ़ बहुमूल्य धान के बीज के रक्षा बर.
९. डंकल प्रस्ताव रद्द करे बर.
१०. पंचायती राज के तहत विभिन्न टेक्स समाप्त करे बर.
११. गड़ा नमक के बिक्री ऊपर प्रतिबंध हटाए बर अऊ गांव मा सस्ता नमक उपलब्ध कराए बर.
१२. हमर छत्तीसगढ़ के स्वस्थ संस्कृति के विकास करे बर औ बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा प्रायोजित भोगवादी बलात्कारी संस्कृति उपर रोक लगाये बर.
१३. छत्तीसगढ़ी गोंडी, हल्बी आदि मातृभाषाओं मा प्राथमिक शिक्षा चालू करे बर.
१४. हवाला के उद्योगपति जैन, केडिया, शाह गुप्ता आदि के निजी सेना के ऊपर रोक लगाना.
१५. नियोगी जी के हत्यारा उद्योगपति मन ला फांसी देवाना. अऊ हर तरह के अन्याय ला समाप्त करे बर.

नया छत्तीसगढ़ राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है // हवाला के गद्दारों की जागीर नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा है.

गणेशराम चौधरी	**भीमराव बागड़े**	**शेख अन्सार**	**मेघदास वैष्णव**
प्रेमनारायण वर्मा	**अंजोर सिंह ठाकुर**	**लीलाबाई**	**बिसेलाल निषाद**

जनकलाल ठाकुर
(विधायक), अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

प्रकाशक :- जनकलाल ठाकुर, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा.

दि० १५/११/९९ रविवार - नवम्बर

आवश्यक-सूचना

* औद्योगिक न्यायालय, रायपुर के 16.10.99 के फैसले में हमारे मजदूर आन्दोलन की ऐतिहासिक जीत हुई है।

* इस विषय के साथ ही दल्ली-राजहरा, भिलाई, उरला, कुम्हारी, टेडेसरा,राजनांदगांव, महासमुन्द, पिथौरा, धमतरी,बिलासपुर-बाराद्वार, डौंडी लोहारा, गुरुर के मुखिया साथियों ने शहीद नियोगी जी के अस्थि कलश के विसर्जन का निर्णय लिया है।

* शहीद कामरेड नियोगी जी की अस्थिकलश विसर्जन की यात्रा का प्रारंभ काम से निकाले गये समस्त 4200 मजदूर साथियों के कर-कमलों से होना है। अतः काम से बैठे सभी साथी इस काम के लिए तैयारी-उपस्थिति भिलाई, उरला, कुम्हारी एवं टेडेसरा के स्थानीय कार्यालय में अवश्य करवा लेंगे।

* शहीद नियोगी जी के अस्थि विसर्जन की शहीद ज्योति यात्रा गांव-गांव से होते हुए जाएगी।

ज्योति से ज्योति जलाते चलो।
शहीदों का रास्ता अपनाते चलो॥
नियोगी भैया तुमने
तूफान में दिया जलाना सिखाया है
तुंहर नांव के दिया ला जलाबो

* यह यात्रा हर उस गांव में जाएगी, जहां छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के विचार को मानने वाले साथी शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने को उत्सुक होंगे।

* अतः सभी साथी जो चाहते हैं कि शहीद यात्रा उनके गांव में आए, वे तत्काल स्थानीय छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यालय में संपर्क करें। यह जानकारी 18 नवंबर तक मिल जानी चाहिए। क्योंकि 20 नवंबर को समस्त छत्तीसगढ़ के प्रमुख साथियों की बैठक में इस कार्यक्रम को अंतिम रुप दिया जाएगा।

विनीत

जनकलाल ठाकुर

अध्यक्ष- छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

केड़िया स्टाइल में, जैन द्वारा निजी सेना का गठन !

केड़िया के अपराधों की फेहरिस्त इतनी लम्बी है जो हमारे पर्चे में नहीं आ पायी, किन्तु हम एक ही घटना जो दिनांक ११.११.९५ को उनके निजी सेना द्वारा अंजाम दिया गया. उसे उद्धृत कर रहे..... जो वुलवर्थ मैनेजमेंट के आज के षड़यंत्र से मेल खाते हैं.

घटना दिनांक को केड़िया के फैक्टरी में पल रहे निजी सेना के गुण्डे अंधाधुंध गोली चलाकर श्रमिक संजय चौधरी की हत्या किए एवं अटारी गांव (रायपुर) के १९ नौजवानों को घायल किया. केड़िया के इन गुण्डों को दुर्ग की अदालत ने २०-२० साल की सजा सुनाई इन गुण्डों में रामपाल नामक गुण्डे को सेक्शन १०९ में सिर्फ इसलिये सजा मिली क्योंकि इन गुण्डों को बम्बई से लेकर आया था.

ये जालिमों देखेंगे कितने को तुम मारोगे ।
जीत हमारी निश्चित है, हम जीतेंगे तुम हारोगे ।।

बी.एल. जैन १५० अपराधिक तत्वों को किस "आपरेशन" के लिये वुलवर्थ परिसर में अस्थाई बैरक बनाकर रखे हुए हैं ? जिसकी तहकीकात किसी भी समय की जा सकती है.
-बी.एल. जैन को रासूका में गिरफ्तार करो.

न्याय की अवमानना

दिनांक ३ अगस्त १९९६ को सहायक श्रमायुक्त रायपुर श्री गायकवाड़ श्रम पदाधिकारी श्री एस. के. रायचौधरी, थाना प्रभारी श्री जागृत के संयुक्त निरीक्षण दल ने डिप्टी कलेक्टर श्री उमेश अग्रवाल के निर्देशन में वुलवर्थ में सघन निरीक्षण किया. निरीक्षण दल ने फैक्टरी एक्ट १९४८, म.प्र. कारखाना नियम १९६२ एवम् मानक स्थायी आदेश में प्रतिपादित किए विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाकर वुलवर्थ मैनेजमेंट को चेतावनी देते हुए दर्जनों प्रकरण न्यायालय में प्रासीकूट किया.

पहली जनवरी "९७" को ऑपरेटर साथी, वुलवर्थ मैनेजमेन्ट के अनुचित श्रम प्रयोग (अनफेयर लेबर प्रेक्टिस) में रोक लगाने हेतु संविधान के अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत अपनी युनियन बनाए, साथियों के इस संवैधानिक कदम से बौखलाकर मैनेजमेन्ट युनियन प्रमुखों को दुर्भावना से विधि विरुद्ध स्थानान्तरण करना चाहा, जिसे माननीय श्रम न्यायालय, रायपुर ने अपने आदेश दिनांक १ फरवरी "९७" में स्थगित किया है.

३ अगस्त "९६" के जांच एवम् दिनांक १ फरवरी "९७" के न्यायालय के आदेश के बाद वुलवर्थ प्रबंधक का संविधान विरोधी कारनामा जग जाहिर हो गया, फिर भी अहंकार में डुबा हुआ है.

इतिहास गवाह है, अहंकार के कारण ही रावण की हार हुई थी. जीत हमारी निश्चित है क्योंकि ऑपरेटर साथियों के पीछे वुलवर्थ के विभीषण शनैः शनैः लाल-हरा झण्डा धर रहे है.

बड-बढ़ुई बहल जायें, गधा कहे कथा. ॥

यह बात हम दावा के साथ कह सकते हैं कि सिम्पलेक्स, बी.ई.सी. मैनेजमेन्ट की तुलना में वुलवर्थ मैनेजमेन्ट अव्वल दर्जे के बुड़बक है. सिम्पलेक्स, बी.ई.सी., भिलाई वायर्स, केडिया डिस्टलरी वर्ष ९०-९१ में मजदूरों को बिना कारण बताये, बिना नोटिस, चार्जशीट जारी किये काम से वंचित किया था. आथिक रुप से बर्बाद हुए, मार्केट में बदनाम हुए और अब कानूनी डंडा से तिलमिला रहे हैं. उनसे सबक न लेकर वुलवर्थ मैनेजमेन्ट उनकी गलतियों को दोहरा रहा है. वुलवर्थ मैनेजमेन्ट को अपने अवैधानिक कृत्य का खामियाजा इन उद्योगपतियों की तरह भुगतना पड़ेगा.

अंत में हम वुलवर्थ मैनेजमेन्ट से इतना ही कहना चाहेंगे कि पूर्वाग्रह को त्यागकर परिपक्व प्रबंधक की तरह ऑपरेटर साथियों की युनियन से वार्ता कर समाधान की दिशा में आगे बढ़े.

वर्ना......... **संघर्ष या समझौता, हम तैयार है ।**

- **निकाले गए साथियों को काम में वापस लो**
- **असामाजिक तत्वों द्वारा डराने-धमकाने की दुष्कृत पर रोक लगाओ.**
- **लाल-हरा झण्डा जिंदाबाद**
- **छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ जिंदाबाद**
- **शहीद साथी अमर रहे**

भवदीय- जी.पी. स्वाई, घनश्याम राने, गुलाब देवांगन, ललित कुमार, दिलीप वर्मा, एस.के. सिंह, शेख अन्सार, नकुल साहू, हलधर नरुण

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

भिलाई इस्पात नगरी के फौलादी मजदूर साथियों से अपील

भिलाई इस्पात नगरी के मजदूर साथियो,

भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के हजारों मजदूर पिछले ६ महीनो से लाल- हरा झंडा लहराते हुए अपने जायज मांगों के लिये संघर्षरत हैं। पूंजीपतियों से चंदा लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री पटवा और उनके स्थानीय चमचे- मजदूरों की समस्याओं को अनदेखा कर - मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिये एड़ी- चोटी का जोर लगा रहे हैं। केडिया डिस्टिलरी के मालिक कैलाशपति केडिया देवरिया के हैं। उनके सभी विश्वस्त चौकीदार भी देवरिया के हैं। दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी देवरिया के होने के नाते ही मंत्री बनाये गये ताकि केडिया एवम् भिलाई के अन्य पूंजीपतियों के तहखानों की सही हिफाजत हो।

इसी के तहत कायरता पूर्वक नियोगी की गिरफ्तारी की गई। न्याय- पालिका भाजपा की कौरवी सेना की रक्षा के लिये शिखण्डी रूपी ढाल बन गई है। दुख इस बात का है कि न्यायपालिका इस पर लज्जित होने की जगह गौरव अनुभव कर रही है।

केडिया डिस्टिलरी के १०० महिला मजदूरों को केडिया जीने नौकरी से निकाला क्योकि वे जुलूस में गई थीं। जुबेर नामक निगरानी शुदा बदमाश को चाकू के जोर पर मजदूरों को आतंकित करने के लिये केडिया जी ने रखा। अपने मालिक के प्रति वफादर जुबेर का गैंग कई प्राणघातक हमले करने के बावजूद बेखौफ घूम फिर रहा है और यह जानकर भी पुलिस अनजान बनी बैठी है।

भिलाई में मजदूर आंदोलनो को तोड़ना ज्ञानप्रकाश मिश्रा का पेशा है। इस काम के लिये उन्होंने भिलाई के कुछ बेरोजगारों को फंसा रखा है। अमनपुर गोलीकांड के पहले भी इसी गैंग को लगाया गया था मजदूरों को आतंकित करने के लिये । अब ज्ञान प्रकाश और - प्रेमप्रकाश के गैंग ने एक साथ मिलकर सिम्पलेक्स के मालिक मूलचंद और चंद्रकांत के इशारों पर मारपीट, गुंडागर्दी के जोर पर डराना- धमकाना बेरोकटोक शुरू कर दिया है।

केडिया और शाह परिवार मानते हैं कि उन्हें छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लूटने की आजीवन छूट (लीज़) मिली है। वे समझते हैं कि अपने पैसों के बल पर वे पुलिस और प्रशासन को खरीदकर उनकी मदद से हिंसा की राजनीति चलाकर मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचल देंगे। पैसों की ताकत पर घमंड करने वाले अब अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। उद्योग पतियों की इस साजिश ने पुलिस और गुंडे के बीच का फर्क समाप्त कर दिया है। इसके विरुद्ध अपनी जागरुकता और एकता का परिचय देने के लिये भिलाई के हजारों फौलादी मजदूरों के साथ लाखों किसान भी जेलभरों आन्दोलन चलायेंगे, अपनी नयी पहचान बनायेंगे । इस पर भी यदि बाज न आये तो छत्तीसगढ़ के इन लुटेरों को इस धरती से बाहर किया जायेगा। चौकीदार प्रेमप्रकाश पांडे के साथ केडिया को भी देवरिया या राजस्थान जाना होगा क्योकि

सेठ बनियों की जागीर नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा है।

भिलाई औद्योगिक क्षेत्र मे जो ज्वाला उठी है उसकी धधक भिलाई इस्पात का मजदूर भी महसूस कर रहा है। भिलाई इस्पात नगरी और भिलाई का औद्योगिक क्षेत्र एक घर के दो कमरे हैं। एक कमरे में आग लगने पर उसकी गर्मी और धुंए से दूसरे कमरे के रहने वालों में घुटन और बेचैनी होना स्वाभाविक है। भिलाई इस्पात का फौलादी श्रमिक भी अब सिर पर हाथ रखकर बैठने की बजाय अपनी बेचैनी और मजदूर एकता को सिद्ध करने हेतु तत्पर है।

यदि तुम्हारे घर के
एक कमरे में आग लगी हो
तो, क्या तुम
दूसरे कमरे में सो सकते हो?

यदि, तुम्हारे घर के
एक कमरे में लाश पड़ी हो
तो क्या तुम
दूसरे कमरे में गा सकते हो?

यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में
लाशें सड़ रही हों
तो क्या तुम
दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो?

यदि हाँ
तो मुझे तुमसे
कुछ नहीं कहना है।

– सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

आपकी इस बेचैनी को अनुभव करते हुए हमारी, आपसे अपील है कि आप अपने आन्दोलनरत श्रमिक भाइयों को एक रुपये की सांकेतिक मदद दें। आपका यह सहयोग भिलाई के मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात करेगा। भाई चारे को प्रदर्शित करने हेतु दिया गया यह एक रुपया हमारे पारंपरिक होली और रमजान के त्यौहार को गरिमा मय बनायेगा। हाल ही में रायपुर के दौरे पर म. प्र. के श्रमायुक्त ने भी भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के शोषण को स्वीकर किया है और श्री रवि आर्या ने भी इस क्षेत्र के शोषण को मिटाने हेतु आंदोलनरत मजदूरों की मांगो को समर्थन दिया है। रमजान के पवित्र मौके पर भिलाई इस्पात नगरी के मजदूर भी आंदोलनरत मजदूरों के प्रति एकजुटता दिखाकर होली के उल्लास को और बढ़ायेंगे इसी विश्वास के साथ,

क्रांतिकारी अभिवादन। लाल जोहार।

संघर्ष में आपके साथी,

नीलरतन घोषाल   जनक लाल ठाकुर   रवीन्द्र शुक्ला

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा- जिन्दाबाद

लाल हरा झंडा- जिंदाबाद

भिलाई में
लगातार ट्रेड यूनियन संघर्ष
के 10 साल

वर्ष 1990 एवं 1991

23 जुलाई 1990		सीधी कार्यवाही के तहत नियोगी जी द्वारा ए.सी.सी. जामुल के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल
		ए.सी.सी. मैनेजमेंट के गुण्डों द्वारा जान ले॰ । हमला विफल अंततः ए.सी.सी. के 77 ठेकेदारी मजदूरों के पक्ष में फैसला
जुलाई, अगस्त, सितम्बर	-	भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर एकता की लहर उमड़ी हजारों मजदूरों ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का लाल हरा झण्डा पकड़कर संगठित हुए।
17 सितंवर 1990	-	औद्योगिक क्षेत्र में छ.मु.मो. युनियन का पहला जुलूस
	-	सिम्पलेक्स केडिया की गुण्डा सेनाओं के हमले विफल
	-	पहली आम सभा के साथ भिलाई में जनशक्ति साधारण रुप से प्रतिष्ठित हुई यह एक गुणात्मक परिवर्तन था
		गुण्डों द्वारा छ.मु.मो. कार्यकर्ता पर जनलेवा हमलों का सिलसिला चलाया गया लेकिन लोकतांत्रित आन्दोलन के उभार के समक्ष उनका प्रभाव गौण रहा।
5 अक्टूवर 1990	-	छ.मु.मो. द्वारा विभिन्न मैनेजमेंटों को एवं सहायक श्रमायुक्त को मांगपत्र सौंपें।
फरवरी 1991	-	फर्जी पुराने केसों के आधार पर नियोगी जी को गिरफ्तार कर दुर्ग जेल भेजा गया।
3 अप्रैल 1991	-	नियोगी जी की रिहाई
25 जून 1991	-	भिलाई में पुलिस द्वारा बरवर लाठी चार्ज 600 कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंसा
जुलाई-अगस्त	-	नियोगी जी को जिला बदर करने का प्रयास विफल रहा।
		गुण्डों द्वारा जानलेवा हमलों में तेजी।
12 सितम्वर 1991	-	मजदूर प्रतिनिधि मंडल के साथ नियोगी जी ने दिल्ली में राष्ट्रपति आर.वेंटकरमन, प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव, लालकृष्ण आडवाणी, वी.पी. सिंह आदि को छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों की निजी सेनाओं से जीने के अधिकार को खतरे के वारे में अगाह किया।
28 सितम्वर 1991	-	भिलाई में उद्योगपतियों द्वारा नियोगी जी की हत्या।
	-	विरोध स्वरुप जबर्दस्त आन्दोलन

वर्ष 1992

25 जनवरी 1992 - धारा 144 तोड़ते हुए भिलाई में जबर्दस्त प्रदर्शन

राष्ट्रीय राजमार्ग का चक्का जाम

साथी जनक लाल ठाकुर द्वारा खुर्सीपार गेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरु

27 जनवरी 1992 - भिलाई के उद्योगपतियों द्वारा छ.मु.मो. के खिलाफ जुलूस

यह एक अद्भुत नजारा था जब बड़े-बड़े उद्योगपतियों हवाला कांड के वी.आर. जैन, सुरेन्द्र जैन, इंडिया नंबर 1 ब्राण्ड के शराब निर्माता कैलाशपति केडिया, सिम्पलेक्स उद्योग समूह का डायरेक्टर मूलचन्द शाह आदि अपने स्टाफ-चमचों को साथ में लेकर, दोनों हाथों से अपनी पतलूनों को सम्हालते, पसीना पोंछते हांफते हांफते जुलूस निकाले थे। उनका दुराग्रह था कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आतंकवाद पर रोक लगाओ।

25 मई 1992 - भिलाई में जबर्दस्त प्रदर्शन - पुलिस के घुसपैठियों द्वारा विस्फोट एवं भारी गोली चालन दमन के षड़यंत्र की भनक लगी। छमुमो द्वारा जुलूस के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को परिवर्तित कर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया।

25 मई से 1 जुलाई 92 - 4,000 ~~हजार~~ से अधिक मजदूरों महिलाओं, बच्चों द्वारा भीषण गर्मी एवं मानसून के प्रारंभिक भारी बौछारों के बीच खुले आसमान के नीचेअद्भुत पड़ाव सत्याग्रह।

1 जुलाई 1992 - रेल रोको सत्याग्रह

- पुलिस द्वारा बर्बर गोली चलान 16 साथी शहीद हुए, 250 से अधिक साथी पुलिस की गोलियों से घायल हुए

जुलाई से दिसम्वर - भीषण दमन, आतंक का दौर

- कर्फ्यू , धारा 144

नेताओं पर फर्जी मुकदमें

सैकड़ों मजदूरों को जेल में ठूंसा गया

कर्फ्य, धारा 144 के बावजूद या उसके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहे

30 नवंवर से 5 दिसंबर - भाजपा-संघ परिवार के फूट परस्त इरादों को भांपते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में एकता, भाई चारा रैलियां

7-8-9 दिसम्वर - भाजपा के मुख्यमंत्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा घोषित धारा 144 को तोड़ते हुए एकता, भाईचारा रैलियां

वर्ष 1993

4 जुलाई 1993	- दुर्ग के न्यायालय लॉकअप में हथकड़ी लगे कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठी चार्ज
6 जनवरी 1993	- उक्त लाठी चार्ज के विरोध में जबर्दस्त प्रदर्शन
जनवरी 1993	- दर्जनों मजदूर नेता 6 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए
26 फरवरी 1993	- मध्यप्रदेश शासन द्वारा भिलाई आन्दोलन के औद्योगिक विवाद को पंच निर्णयार्थ औद्योगिक न्यायालय रायपुर को रेफरेन्स किया ।
दिसम्बर 1993	- साथी शेख अंसार, मेघदास वैष्णव आदि 17 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए

वर्ष 1994

3 मार्च 1994	- विभिन्न जनसंगठनों के साथ मिलकर डंकल कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन । महिला मुक्ति मोर्चा के अध्यक्षा कामरेड लीलाबाई ने लाल किला के सामने डंकल प्रस्ताव की पुस्तक को जलाया।
24 जुलाई 1994	- रायपुर में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जेड सिक्यूरिटी का घेरा तोड़ कर घेराव किया गया।
1 एवं 2 दिसम्बर 1994	- 23 नवंबर को नागपुर में आदिवासियों पर बर्बर गोली चालन हत्याकांड के विरोध में आन्दोलन।दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर में हजारों मजदूर किसानों को जेल में ठूंसा गया।

वर्ष 1995

15 सितम्बर 1995 - साडा कार्यालय भिलाई में दिग्विजय सिंह का घेराव

12 अक्टूबर 1995 - औद्योगिक न्यायालय रायपुर द्वारा भिलाई आन्दोलन के मजदूरों को वतौर अंतरिम राहत कार्य पर पुनःस्थापना, पब्लिक वेतन का आदेश।

11 नवंबर 1995 - केडिया समूह की कुम्हारी डिस्टलरी में उनके निजी सुरक्षा गार्डो द्वारा फैक्ट्री में मजदूरों पर एवं भागने के प्रयास में किसानों पर गोलियां चलायी। 1मजदूर संजय चौधरी की मृत्यु हुई

13 नवंबर 1995 - केडिया के निजी सुरक्षा गार्डों द्वारा गोली चालन के विरोध में भिलाई में जवर्दस्त औद्योगिक हड़ताल

भिलाई आन्दोलन के मजदूरों ने अँतरिम राहत प्राप्त करने के अपने आर्थिक मुद्दे को पीछे रखते हुए उद्योगपतियों की खूंखार निजी सेनाओं के विरोध में हड़ताल कर वर्ग चेतना का उदाहरण प्रस्तुत किया।

- इंटक, एटक, सीटू, बीएमएस आदि झंडों के नाम पर भिलाई के उद्योगपतियों की प्रभाव में चलने वाले नामधारी मजदूर नेताओं ने उक्त हड़ताल के विरोध में दलाल एकता का प्रदर्शन किया।

11 दिसम्बर 1995 - एसीसी फैक्टरी जामुल में अभूतपूर्व औद्योगिक हड़ताल, गेट जाम सफल।

वर्ष 1996

19 जनवरी 1996 - हत्यारा उद्योगपति चन्द्रकांत शाह जमानत पर रिहा।

1 फरवरी 1996 - नियोगी जी हत्याकांड के मुकदमें में गवाही देने आये दिनेश बालोनी पर उद्योगपतियों के निजी सेना द्वारा दुर्ग रेल्वे स्टेशन पर हमला।

9 फरवरी 1996 - राष्ट्रीय राजमार्ग अम्बेडकर चौक भिलाई पर 4 घंटे तक चक्का जाम।

22 फरवरी 1996 - भिलाई गोलीकांड जांच आयोग के समक्ष पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंग की झूठी गवाही के विरोध में भिलाई गोली कांड पीड़ित बाल मोर्चा का बैनर लेकर सैकड़ों बच्चों ने जिलाधीश कार्यालय में घुसकर प्रदर्शन किया।

8 जुलाई से 27 सितंबर - पावर हाउस भिलाई में धरना

22 नवंबर से 28 नवंबर - भिलाई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमेन बी.आर. जैन (हवाला कांड में चर्चित) के उद्योग समूह बीसो ग्रुप की आर्थिक नाकेवंदी।

- 28 नवंबर दोपहर 2.30 बजे 700 मजदूर आन्दोलकारियों को गिरफ्तार कर जेल में ठूंसा गया।

28 नवंबर से 9 दिसंबर - दुर्ग जेल में आन्दोलनकारियों द्वारा भूख हड़ताल। 11 दिन के भूख हड़ताल के बाद आन्दोलकारियों को रिहा किया गया।

वर्ष 1997

20 अप्रैल 1997 - बंबई हावड़ा रेलमार्ग पर एक बार फिर रेल रोको सत्याग्रह कुम्हारी में 4 घंटे तक रेल रोको आन्दोलन चला। सैंकड़ों आन्दोलनकारी गिरफ्तार, जिसके खिलाफ व्यापक आन्दोलन रेल्वे मजिस्ट्रेट ने जेल में मजदूरों से रुबरू होकर अपनी अदालती कार्यवाही सम्पन्न की।

23 जून 1997 - अतिरिक्त सेशन जज माननीय टी.के. झा ने नियोगी जी के हत्यारों को सजा सुनाई

वर्ष 1998

26 जून 1998 - जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.के. दुबे एवं न्यायाधीश उषा शुक्ला द्वारा हत्यारे उद्योगपतियों और उनके गुण्डों को बरी किया। काला धन के प्रभाव से हाईकोर्ट की गरिमा पर कालिख पुती।

1 जुलाई 1998 - 1 जुलाई शहीद दिवस के अवसर पर भिलाई के प्रदर्शन में हजारों मजदूर किसानों ने हाईकोर्ट के जजों द्वारा पैसा खाकर हत्यारों उद्योगपतियों को बरी करने के खिलाफ जंगी प्रदर्शन।

26 जुलाई 1998 - जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा नियोगी जी के हत्यारों को बरी करने के काले फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश के विभिन्न जनसंगठनों के साथ छमुमो के द्वारा जबलपुर में प्रदर्शन।

13 अगस्त 1998 - गुरुर में किसानों द्वारा आन्दोलन, 18 गांव के किसानों को गिरफ्तार किया गया।

15 अगस्त 1998 - किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में भिलाई के सैंकड़ों मजदूरों भिलाई में चक्का जाम किया, भूख हड़ताल की - दुर्ग जेल में गिरफ्तार किसानों और मजदूरों ने मिलकर आन्दोलन, भूख हड़ताल चलायें उसके पश्चात उनकी रिहाई हुई।

17 सितंबर 1998 - विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ जाफिब द्वारा दिल्ली में विशाल प्रदर्शन में भाग लेने छत्तीसगढ़ के 5000 हजार मजदूर किसान पहुंचे।

18 सितंबर 1998 - छत्तीसगढ़ के प्रदर्शनकारियों के 512 लोगों के जत्थे को वापसी के समय झांसी में गिरफ्तार किया गया।

- छत्तीसगढ़ के मजदूरों, किसानों, महिलाओं ने झांसी की जेल को इंकलाब के नारों से गुंजाया और झांसी की रानी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की।

वर्ष 1999

9-10 जनवरी 1999 - देश भर के अनेक संघर्षशील संगठनों द्वारा गठित संयुक्त मंच जाफिम की रायपुर बैठक की मेजवानी छमुमो. ने की।

विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ प्रदर्शन में जाफिम के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ-साथ भारतीय किसान युनियन उत्तरप्रदेश, हरियाणा, कीर्ति किसान युनियन पंजाव, कर्नाटक राज्य रैयत संघ, ए.आई.पी.आर.एफ. के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।इनमें ए.आई.पी.आर. एफ. के श्री दर्शन पाल सिंह एवं जी.एन. सांईबाबा , बी.के.यू., श्री महेन्द्र सिंह टिकैत (उत्तर प्रदेश), चौधरी घासीराम नैन (हरियाणा), सरदार हरदेव सिंह सन्धु (कीर्ति किसान युनियन पंजाव), कर्नाटक राज्य रैयत संघ के श्री शेषा रेड्डी आदि शामिल थे।

10 मई 1999 - 6 अप्रैल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट वेंच इन्दौर में फूल वेंच के आदेश के अनुरुप औद्योगिक न्यायालय रायपुर में मजदूरों की मामलों की सुनवाई शुरु।

- ट्रेड यूनियन आन्दोलन के 10वें वर्ष में हजारों मजदूरों ने उपस्थित रहकर एक अभूतपूर्व मिसाल प्रतिष्ठित की है।

10 सितम्बर 1999 - औद्योगिक न्यायालय रायपुर पर भिलाई उद्योगपतियों के काले धन के काले प्रभाव के खिलाफ छमुमो द्वारा रेल रोको आन्दोलन की घोषणा।

5अक्टूबर 1999 - भिलाई, उरला, कुम्हारी, टेडेसरा में जवर्दस्त मशाल जुलूस

10 अक्टूबर 1999 - हजारों महिलाओं द्वारा भिलाई में जंगी प्रदर्शन। पुलिस की रूकावटों को तोड़ते हुए पावर हाउस भिलाई में चक्का जाम, आम सभा की।

16 अक्टूबर 1999 - औद्योगिक न्यायालय रायपुर में भिलाई आन्दोलन के मजदूरे के पक्ष ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

SEMI-STARVED WORKERS - PARTIAL IDENTITY OF BHILAI WORKERS. IDENTITY OF BHILAI WORKERS IN TOTALITY-

"SEMI - STARVED WORKERS, WHO ARE READY TO STAKE THERE LIVES IN STRUGGLE AGAINST EVERY KIND OF INJUSTICE AND EXPLOITATION."
BHILAI WORKERS EMERGE AS NATURAL LEADERS OF STRUGGLES OF PEASANTRY-

शहीद नियोगी जो हा बता के गे हे. बड़े-बड़े मन के ताकत, पूंजीपति दलाल मन के कुर्सी, पइसा, गुण्डा के फौज-पुलिस के कोर्ट कचहरी के.टी.वी. अऊ अखबार के ताकत हे. जेकर अधार मा एमन किसान, मजदूर, जनता ला लूटत हे।

मेहनत करइया किसान अऊ मजदूर के ताकत के अधार संगठन हावे। जब ले मजदूर अऊ किसान के संगठन छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा के गठन होय हे. छत्तीसगढ के मजदूर अउ किसान अड़बड़ संघर्ष करिन हे. कुवांरो दिन हे. जनता के दुश्मन बड़ा-बड़ा बदमाश मन ला. उद्योगपति, नेता, अफसर मन ला ठिकाना लगाइंन हे. अउ मजदूर किसान के बड़े-बड़े काम ला बनाइंन हे।

ग्राम खुटेरी

ग्रामवासी मन कमल साल्वेंट फेक्ट्री के मालिक दामोदर दास मुंदडा के प्रदूषण के खिलाफ मा प्रदर्शन करीन. जेकर बाद 16 झन किसान मनला 62 हजार रुपये मुआवजा के भुगतान करेगिस।

ग्राम-बफरा, मड़ौदा

गांव के किसान मन छत्तीसगढ किसान युनियन के गठन करीन जेखर बाद सड़क निकले के मुआवजा जेकर भुगतान कई साल ले नई होवत रहिस अउ करीब डेढ लाख रुपया के मुआवजा भुगतान होईस।

ग्राम-कपरमेटा

ग्राम वासी के मजदूरी के भुगतान सिंचाई विभाग द्वारा पांच महिना ले नई करे गे रिहिस 4 अगस्त 99 के दिन छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा. छत्तीसगढ किसान युनियन के संगवारी मन गुरूर मा चक्का जाम करीन ओखर बाद अधिकारी मन एक लाख अस्सी हजार बकाया वेतन के भुगतान उही दिन बरसत पानी मा करीन।

ग्राम घटियाकला

नागपुर निको. जयसवाल इंटरप्राइजेस के मालिक बड़े जन उद्योगपति मनो ल जयसवाल द्वा गांव के करीब 36 एकड चरागान जमीन ला जबरवाली कब्जा करे रीहिस। जेकर फेनसिंग के खम्भा गड़ा दे रिहीस. तार खींच डारे रिहीस ओखर बाद छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा के साथी मन आन्दोलन करीन उद्योगपति के गुण्डा मनला कुदाइंन अऊ गांव के जमीन ला छुड़वाइंन।

बोड़ेगांव, रवेलीडीह

हवाला काण्ड के सूत्रधार. बी.ई.सी. कम्पनी के मालिक सुरेन्द्र जैन, बी.आर. जैन गांव के सैकड़ों एकड़ चरागान जमीन ला कब्जा कर डारे रिहीस गांव के मन छत्तीसगढ मु[illegible] मोर्चा के आफिस मा खबर करीन जेकर बताय रद्दा में चलके जम्मों गांववासी मन कंपनी के अधिकारी मन के घेराव कर दिन अऊ अपन गांव के जमीन ला छुड़वाइंन

नेवनारा

उद्योगपति प्रहलाद अग्रवाल द्वारा ग्राम के धरसा सहित दस एकड ले उपराहा जमीन ला कब्जा के विरोध मा ग्रामवासी मन संघर्ष करीन हे एक बंच ओकर कब्जा ले जमीन ला छुड़वाइंन हे अउ आगे लड़ई चलतेच हे। वासी के खबंया छत्तीसगढ के किसान के आगू म पूंजीपति के दलाल मन नई टिक सकत हे।

कचान्दुर

ग्राम के महिला गंगाबाई बंछोर के हत्यारा ला बचाने वाले राजनेता- प्रशासन मन के खिलाफ मा अड़बड लडाइ लड़ीन। तमाम महिला. बच्चे मन जुलुस निकालिन. चक्का जाम करीन जेकर बाद नरवा के रपटा. पुल के निर्माण करे गिस।

आन्दोलन के दौरान गांव के छत्तीसगढ किसान युनियन के तीन झन सियान मनला गिरफ्तार करवार प्रशासन हा दस-दस झन पुलिस भेजे रीहिस। तमाम ग्राम-वासी मन के एकता अऊ संघर्ष के आगू मा पुलिस झन मनला खाली हाथ लहुट बर परीस।

ढौर

उद्योगपति केडिया ह अपन गुण्डा मनके ताकत मा ग्राम-ढौर के किसान मन के जमीन के ऊपर अपन प्लाट तक ले सड़क बनाय के काम शुरु करवा दिस। बिना किसान मन ल पूछे. एकदम जबरवाली। गांव के नवजवान मन एकता बनाइंन अऊ उद्योगपति केडिया के आदमी मन ला कुदाइंन। ग्राम ढौर के नवजवान संगवारी मन गांव मा अवैध शराब. अउ पटवारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मा घलो संघर्ष करत आवत हे।

कुसुमकसा

11-10-98 के दिन व विभाग वाले मन ग्राम चिपरा के किसान ला बेहद पीटे रीहीन। छ.मु.मो. के साथी मन आन्दोलन करीन। सब झन के आघू मा वन विभाग के अधिकारी ला माफी मंगवइंन. इलाज-पानी के पइसा दिलवइंन।

वोही दिन. 11 अगस्त 98 के दिन छ.मु.मो. के साथी मन वन विभाग द्वारा चोरी के पांच गोला सगौन के लकड़ी ला पकडे रहीन।

ग्राम- बंजारी

खरखरा बांध मा जम्मो किसान मन के जमीन निकल गे रिहीस उकर बाद जिये खाये बर कही कोइ ठिकाना नहीं मिलीस। शासन ल कतको अर्जी आवेदन करे गिस कहीं कोनो सुनवाइ नई होइस।

1986 मा ग्रामवासी मन लाल-हरा झंडा ल धरके संघर्ष करीन। नियोगी जी ह ओमन ल रस्ता बताईस जम्मो ग्रामवासी मन जंगल के 350 एकड जमीन ल धरीन अउ उही जमीन म खेती शुरु करीन। 1986 से आज तक ले जम्मो ग्रामवासी मन एक मनता सामूहिक खेती करते चले आवत हे।

जमीन आन्दोलन

पिथौरा. बसना. कसडोल. सराइपाली क्षेत्र मा करीब 500 गांव के 8000 (आठ हजार) गरीब किसान भाई-बहिनी मन शासन के परिया जमीन धर के खेती करत आवत हे।

एकर दरम्यान ये संगवारी जमीन दो या जेल दो आन्दोलन चलाय हे अऊ एकर संघर्ष जारी हे।

छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा की ओर से साथी जनकलाल ठाकुर द्वारा प्रकाशित संपादक - अनूपसिंह ,

जैसे किसी को चलने के लिये
दो पैरों की जरूरत है
हमारे लिये वो पैर हैं
संघर्ष और निर्माण

निर्माण के कार्य

* 1994 में दल्लीराजहरा से लगे आदिवासी ग्राम कोण्डेकसा में, शहीद शंकर गुहा नियोगी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल की शुरुवात की गई। 1997 में छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ एवं ग्रामवासियों के एकजुट प्रयासों से शाला के सुन्दर भवन का निर्माण सम्पन्न हुआ।

* वर्ष 1993 में ग्राम नर्राटोला में छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ एवं ग्रामवासियों द्वारा बांध और सिंचाई नाली का निर्माण।

  उक्त स्थान पर वहां वर्ष 1987-88 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के युवा कार्यकर्ताओं ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर बी.एस.पी. के डैम साइड से निकले नाले पर एक कच्चे बांध का निर्माण किया था जिसे 1993 में पक्के बांध कर दिया गया।

* शहीद नगर का निर्माण - रायपुर के समीप उरला औद्योगिक क्षेत्र के बीरगांव में छमुमो के आन्दोलनकारी साथियों ने सार्वजनिक जमीन पर वैध कब्जा कर एक योजनाबद्ध नक्शे के साथ झोपड़ियों का निर्माण कर सुन्दर शहीद नगर को बसाया।

* इसी शहीद नगर बस्ती में मजदूरों द्वारा प्राथमिक शाला शहीद स्कूल के सुन्दर भवन का निर्माण किया एवं स्कूल को चला रहे है।

* इसी शहीद नगर में मजदूरों द्वारा डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही है।

* उरला औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर साथियों ने ग्राम सरोरा की सीमा में वुलवर्थ उद्योग समूह द्वारा जमीन के अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष किया। और उस जमीन पर वैध कब्जा कर मजदूर नगर बसाया है।

Wasn't the Nuclear Explosion dated 11th May 98 and subsequent hysteria a smoke screen to divert attention from abject surrender at W.T.O. darbar, Generva dated 18 to 20 May'98 by the pseudo-nationalist B.J.P. Govt.

(Anti-Dunkel being it's main "nationalist" programme of its election campaign only some time back.)

C.M.M. took Loud, Clear and Effective public stand in the open streets .

प्रधान मन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम छ.मु.मो. अध्यक्ष का खुला पत्र

परमाणु गौरवगान या डंकल दरबार में आत्म समर्पण की खबर दबाने का शोर

There are only three species, which are happy at the prospect of a war, the kites, the valtures and the American arms dealers.

क्यूं खुदकशी कर रहे देश के सैकड़ों
किसान - अन्नदाता,
नवजवान अशोक नायक आत्महत्या पर
मजबूर क्यूं हो जाता ?
पनिया अंकाल से मची छत्तीसगढ़ में हाहाकारी,
सुनसान हो रहे गांव, पलायन भारी,
जान देनी पड़ रही है पानेको
अपनेको, पीने का पानी
गवाही रायगढ़ में वहन सत्यभामा की कुरबानी,
भूख हड़ताल में जिन्दल उद्योग के समक्ष
दिन 26 जनवरी 98 गवां दी अपनी जिन्दगानी
इस हाल पर हम जश्न
कैसे मना ले वाजपेयी जी ?
करोड़ों जनता के समक्ष, रोजी-रोटी का सवाल,
खोजते खोजते जवाब,
व्यवस्था की घोर उपेक्षा लेलेती उनके प्राण
उस व्यवस्था द्वारा,
परमाणु, बम का गुणगान
है नीरो की बांसुरी के समान,
विकास की सीढ़ी पर, दुनिया में 134 वां स्थान
भूख, गरीबी, बेरोजगारी के नाम,
फोड़ कर एक परमाणु बम,
नहीं हो जाएगा उन्नति में छठवां स्थान
आप कहते है, जश्म मना लो,
गा लो गौरव गान,
व्यवस्था के इस हाल पर हम जश्न,
कैसे मना लें बाजपेयी जी ?
हम तो करते हैं धिक्कार,
अपनी हिंसक उपेक्षा से जनताओं को,
मौत के मुंह में धकेलने वालों को,

क्रय-शक्ति तुलनात्मकता में
डालर 2 रुपये समान,
पर डालर दलालों के बदौलत
आज 40 रुपया उसका दाम,
आने वाले बरस में हो जाए 400 रुपया भी,
तो मत होना हैरान-
हालत-ए-रुस, इंडोनेसिया, मैक्सिको
इसके प्रमाण ------------ ।
विदेशी कम्पनियों की लूट बड़ी,
देश के उद्योग और कृषि पर
अभूतपूर्व संकट की घड़ी
दोहराया जा रहा है फिर से,
ईस्ट इंडिया कम्पनी का इतिहास,
तलवार और तोप नहीं,
दुश्मन तो आता है अब,
लेकर व्यापार का प्रस्ताव ------- ।
टीपू और मराठों को
सिखों और अफगानों को
लड़ा भिड़ा कर अंग्रेजों को
हिन्दुस्तान फतह पाया था
पड़ौसियों से भारत को लड़ाने का तरीका
अमरीका ने पाया है, --- ।
भारत को,
उसके पड़ोसी देशों को
और सैंकड़ों गरीब देशों को
देखो, आ रहा है जीतने
डंकल बम और डालर बम के साथ
तीन ही प्रजातियां हैं जो
जश्न मनाती है युद्ध की संभावना में,
चील, गीधऔर अमरीकी शस्त्र व्यापारी
भारत-पाकिस्तान की लड़ाईयों-तनावों में शस्त्र
व्यापारियों ने हजारों करोड़ कमाए हैं,
अब पक्षेपास्त्र पृथ्वी और गौरी की,
परमाणु-क्षमताओं, हथियारों की दौड़ में
लाखों करोड़ कमाने के टारगेट बनाए हैं ---- ।
रूपयासीमा के इस पार
और उस पार
बुरी तरह पिट रहा
डालर की भारी मार ----------- ।
कोशिश यह भी है कि 18-20 मई की
जेनेवा बैठक में, डंकल कानून पर
भाजपा सरकार की सील की खबर,
परमाणु विस्फोट के शोर में दब जाए .. ।

तू इधर-उधर की बात न कर,
बता, ये काफिला लुटा तो लुटा कैसे

इसलिए महोदय जी,
छत्तीसगढ़ के किसानों की दो ठोस मांगे

1) डंकल कानून अर्थात, विश्व व्यापार संगठ कानून के पुनर्विचार हेतु जेनेवा बैठक (18-20 म 98) में भारत सरकार डंकल-कानून अर्थात विश व्यापारी संगठन कानून से नाता तोड़े ,

2) आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुन्दरलाल पटव द्वारा भोपाल में भूख-हड़ताल के दौरान उठाई मां के अनुसार केन्द्र सरकार से २००० करोड़ रुपये व आर्थिक सहयोग पनियां अकाल पीड़ित किसा हेतु जारी करें।

भिलाई
17-5-98

भवदीय
जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

देश की सुरक्षा को गंभीरतम खतरा ।

16 से 19जुलाई फौजी भर्ती के दौरान बेरोजगार नौजवानोंकी भारी भीड़ उमड़ी , अफरा तफरी , गोली चालन से जयपुर में 1, भरतपुर में 2, छपरा में 3, एवं दरभंगा में 23 नौजवानों की मृत्यु

देश की सुरक्षा को गंभीरतम खतरा

हमारे ही 29 नौजवान बेरोजगार
मारे गए,
सिपाहियों द्वारा
वे नहीं है सिर्फ 29
उन 29 के पीछे
20 करोड़ नौजवान बेरोजागर
भी हुए है शिकार
दोनों हाथ काट देने वाली बेरोजगारी के ।
20 करोड़ नौजवानों के हाथ
देश की पूरी युवा पीढ़ी के हाथ
देश का भविष्य संभालने वाले हाथ
काटे गए 40करोड़ हाथ ।
इस अथाह दुख पर,

दिल से निकले जो आंसू तो
हिन्द महासागर छोटा पड़ जाए
उन आंसू को बनाकर अंगार
जब घूर के देखें
इस व्यवस्था सड़ी-गली को
पोखरण परमाणु बम भी छोटा पड़ जाए ।
दाने-दाने को भटकता किसान अन्नदाता
डंकल डालर की दलाली में मस्त राजनेता
विदेशी घुसपैठ उद्योग और कृषि में
उद्योगपति वर्ग विचार शून्य है बैठा
20 करोड़ नौजवानों के
40 करोड़ हाथ काट देने वाली बेरोजगारी
देश की सुरक्षा को गंभीरतम खतरा ।

CHHATTISGARH WORKERS REPLY TO KARGIL JINGOISM !

प्रति,

श्रीमान् प्रबंधक,
जामुल सिमेंट वर्क्स,
ए.सी.सी. जामुल, भिलाई ।

विषय : कारगिल युद्ध के मद्देनजर आर्थिक सहयोग देने बाबत् ।

महोदय जी,

कंपनी के अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा तमाम श्रमिकों पर दबाव डाला जा रहा है, कि वे उपरोक्त बाबत् एक दिन का वेतन जमा करें । उक्त मुद्दे पर हमारी यूनियन से सम्बद्ध समस्त श्रमिक एक दिन के बजाय दो दिन का वेतन देने को स्वेच्छा से तैयार हैं । इसी के साथ-साथ व्यवस्था के अधिकारियों से पारदर्शिता [transparency] एवं जवाबदेही [accountability] के तकाजे के तहत निम्न मुद्दों के विषय में स्पष्ट जानकारी चाहते हैं, ताकि हमारी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई के दुरुपयोग पर हम नजर रख सकें :—

[1] आम जनता की सहयोग राशि प्रधानमंत्री के कोष में जमा हो रही है । दूसरी ओर, केन्द्र सरकार के 4,500 करोड़ रुपये उस समय लुटवा दिये गये जब प्रधानमंत्री ने विदेशी टेलीफोन कंपनियों पर लाइसेन्स फीस के बकाया हजारों करोड़ की सालाना किश्त को माफ कर दिया । केन्द्र सरकार को कुल हानि एवम् विदेशी टेलीफोन कंपनियों को कुल लाभ 4500 करोड़ से कम नहीं है । प्रधानमंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की सलाह को भी नामंजूर कर दिया । अब हम ऐसे प्रधानमंत्री के कोष में अपने खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को क्यों और कैसे जमा करें । जो कि जनता की गाढ़ी कमाई विदेशी टेलीफोन कंपनियों को लुटवाता हो ?

[2] देश का करीब दो लाख करोड़ रुपया अरे बतौर कालाधन, नवधनाढ्यों द्वारा विदेश बैंकों में जमा है । युद्ध के मद्देनजर आर्थिक संकट की स्थिति में इस अपार राशि का कितना हिस्सा देश एवं सरकार में लाया गया है ? जानकारी से उत्साहवर्धक होगा ।

...2 पर

// 2 //

Regd. No. 4050

क्रमांक ____________ दिनांक ____________

[3] तमाम फिल्मी सितारों द्वारा युद्ध के मद्देनजर आर्थिक सहयोग का आह्वान आम जनता को किया जा रहा है । इन्कम टैक्स सहित इन्हीं तमाम फिल्मी सितारों पर करोड़ों - करोड़ रुपया आयकर बकाया है । दान न भी करें, सरकार की बकाया राशि का सरकार को भुगतान करें ऐसी आज की आर्थिक स्थिति में बहुत उपयोगी होता है । इन फिल्मी सितारों द्वारा सरकार की बकाया राशि भुगतान की जानकारी उत्साहवर्धक होगी ।

[4] मात्र सुरेन्द्र जैन, वी.आर. जैन पर सरकार का करीब 200 करोड़ रुपया आयकर बकाया है । मजदूरों - कर्मचारियों के वेतन से एकत्रित 2 लाख रुपये की राशि जमा करने की आड़ में युद्ध स्थिति के आर्थिक संकट की पूर्ति में भी सरकार के आयकर के बकाया 200 करोड़ रुपये दबाकर रखने वाले जैन बंधुओं के कृत्य को प्रशंसनीय कहेंगे या निन्दनीय ?

[5] सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि देश के विकास में जीवन-संचार करने वाली हृदय-स्थली के समान है । देश की इस हृदय स्थली पर विदेशी कंपनियों की घुसपैठ विश्व व्यापार संगठन के ट्रिम्स [TRIMS: Trade Related Investment measures] द्वारा कराई जा रही है । देश की व्यापक जनता इस आर्थिक गुलामी के खिलाफ आन्दोलन कर उद्योगों की रक्षा करना चाहती है, लेकिन शासक राजनैतिक वर्ग इस सबसे विनाशकारी विदेशी घुसपैठ के, का विरोध करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति हीन सिद्ध हो रहे हैं । जबकि हर किसी देश के औद्योगिक विकास की रक्षा उसके शासक राजनैतिक वर्ग द्वारा किया जाना 19 वीं. एवम् 20 वीं सदी का सबसे बड़ी ऐतिहासिक शिक्षा है । इक्कीसवीं सदी की आगमन बेला में भी अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होते हुये भी स्वदेशी कानून एवं हित को घोषित रूप से बरकरार रखकर इसी ऐतिहासिक सिद्धांत की पुष्टि की है । हमारे देश की हृदय-स्थली सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग उद्योग में विदेशी घुसपैठ के समक्ष आत्म समर्पण करने वाले राजनेताओं के कोष में चंदा जमा करने से हम उनके छद्म राष्ट्रवाद की छवि को पुष्ट करते हुये इस वर्गीय आत्म-समर्पणवादियों के गंभीर देशद्रोह पर पर्दा डालने के भागी तो नहीं बन रहे हैं ?

...3 पर

[6] क्या पूरे कारगिल प्रकरण में सबसे गंभीर घुसपैठ क्षेत्र में अमेरिका की थानेदारी की स्थापना नहीं है ? यह अमेरिका जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य गढ़ है । एवं जिसकी दादागिरी में राहुल बजाज जैसे उद्योगपति को भी नौकर जैसे महसूस होता है ।

[7] कारगिल युद्ध में मरने वाले जवान चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के मजदूर और किसान के बेटे ही तो हैं । भारत के या पाकिस्तान के किसी भी राजनेता या उद्योगपति का बेटा, भाई, भतीजा युद्ध में नहीं मरा है । यदि आपकी जानकारी में कोई है, तो बताईयेगा ।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही के तकाजे के तहत इन मुद्दों पर साफ तौर की जानकारियों एवं संतुष्टि के होने पर हमारी यूनियन के श्रमिक एक नहीं, बल्कि दो-दो दिन का वेतन देने के लिए तत्पर हैं ।

// धन्यवाद //

दिनांक : 21/08/99

भवदीय

[signature]

[जनक सिंह]
महासचिव

ACC CEMENT WORKS RECEIVED 21 AUG 1999 Jamul Cement Works

When the management was pressurizing workers to donate one day salary for Prime Minster's Fund, We asked them to first account for the following.

- 4500 crores rupees sqandered to the telecommunication MNCs.!
- 2 Lakhs crores of black money, much of which in foreign banks and what fraction of this is brought in for war-efforts !
- Have the film stars, staging endless fund-raising shows, paid up the income tax due on them which adds upto thousands of crores ! Even a fraction of this !
- Most serious is the attacks on our industrial establishment through T.R.I.M.S. and isn't this pseudo partiotism a smoke screen for their abject surrender before aggression of Dollar & W.T.O.
- All the blood which is shed on both side of the boarder is ofthe sons of workers and peasants. If any relative of Industrialist or politician has died in war, the same be brought to our knowledge.

On being satisfied on above accounts workers of our union shall be ready to donate even 2 days salaries.

DOCUMENTARY PROOF OF SANGH - BJP DOUBLE SPEAK

" भाजपा डंकल प्रस्तावों को स्वीकार्य नहीं मानती "

लालकृष्ण आडवाणी, रायपुर में जनादेश यात्रा के दौरान अमृतसंदेश 29.9.93

" डंकल के लागू होने से कृषक गुलाम हो जाएंगे "

बृजमोहन अग्रवाल डोंगरगांव में 2.10.94 धमतरी में 14.3.94

" डंकल प्रस्ताव की मंजूरी से हम गुलाम हो जाएंगे "

प्रेम प्रकाश पांडे दल्ली राजहरा में नव भारत 10.9.93

" डंकल के विरोध में आन्दोलन "

राजेन्द्र सिंह (आर.एस.एस. प्रमुख) नव भारत 6.4.94

" डंकल प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने वाले पुनः दासता की जंजीरों में जकड़वाने के अपराधी होंगे। "

के.सी. सुदर्शन (आर.एस.एस. के दिग्गज नेता) अमृत संदेश 7.9.93

" डंकल किसानों को बंधुआ मजदूर बना देगा "

डा.रमन सिंह विधायक कवर्धा एवम् महेश बघेल पूर्व विधायक, केसकाल नव भारत 25.3.94

" डंकल पूरी तरह देशहित के विरुद्ध "

जसवंत सिंह 29 मार्च 1994, लोकसभा में

" डंकल-प्रस्ताव के विरोध में 6 अप्रेल 1994 को भाजपा द्वारा संसद घेराव एवम् रैली में भाग लेने छत्तीसगढ़ से जत्थे रवाना। "

चन्द्रशेखर साहू, रमेश बैस, श्याम बैस, अशोक बजाज, नव भारत 5.4.94

डंकल पर अटल की सील

डंकल डालर दरबार में घुटना टेका, किसानों से गद्दारी

छ.मु.मो. ने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि डंकल कानून अर्थात विश्व व्यापार संगठन कानून की पुनर्विचार बैठक (जेनेवा 18 से 20 मई) में भारत सरकार इस कानून से नाता तोड़े लेकिन परमाणु गौरवगान की आड़ में वाणिज्य मंत्री हेगड़े डंकल कानून पर भारत सरकार की स्वीकृति सील लगा कर अमरीकी राज दरबार में घुटने टेक आए है। 1994 में डंकल कानून के विरोध में संसद घेराव करने वाले इन भाजपाइयों को दोगला नहीं तो और क्या कहेंगे ?

6 अप्रैल 94 को भाजपा का संसद घेराव- क्योंकि डंकल किसानों को गुलाम बना देगा

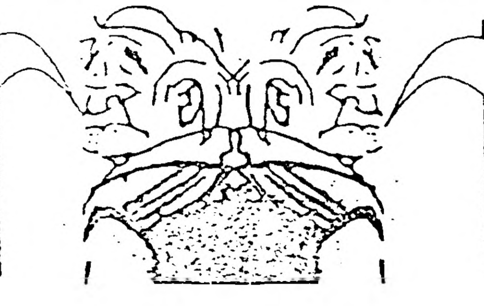

18 मई 1998 डंकल कानून पर भाजपा सरकार की स्वीकृति सील

THE TYPICAL CHARACTERISTIC OF FACSIM IS - DOUBLE SPEAK.

While acting as stooge of imperialism talking of nationalism. Thus, it is the first choice of America and International Monopoly Capital

Indian delegation at Seattle WTO meet consisting of Murasoli Maran of ruling alliance, Mr. Kamal Nath of Congress & Com. Biplab Das Gupta of CPM meekly submitted to the Americal line. Can you fight fascism while surrendering to international monopoly capital?

छत्तीसगढ़ प्रवास के अवसर पर

श्रीमती सोनिया गांधी के नाम
छत्तीसगढ़ के शहीद परिवारों का पैगाम

महोदया,

छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आपका आगमन हुआ है, स्वागत है। व्यक्तिगत रूप से आपको जो घाव मिले हैं, उनके प्रति हमारी हमदर्दी है। हमने दुख पाया है बहुत, इसीलिए दूसरे के दर्द भी समझते हैं। क्रूर व्यवस्था ने हमारे परिवार के मुखिया कामरेड शंकर गुहा नियोगी की हत्या की, कितने मजदूर साथियों को गोलियों से भूना है।

हम छत्तीसगढ़वासी इन अत्याचारों का प्रतिरोध कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि नियोगी जी एवम् मजदूरों के हत्यारे- षड्यंत्रकारी उद्योगपतियों को फांसी की सजा मिले। छत्तीसगढ़-न्यायाग्रह के तहत हम इस क्रूर व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए और 'नये भारत के लिए नये छत्तीसगढ़' के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं।

स्व. राजीवगांधी के हत्यारों के विषय में हमें महसूस होता है कि आपकी पूरी पार्टी को ज्ञात है कि हत्या षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार कौन हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवक्ता आर.एन. मित्तल ने गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकत कर रंगराजन की सुरक्षा कड़ी करने की मांग की थी। ज्ञातव्य है कि रंगराजन की फांसी की सजा से विमुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। जेल से छूटने के बाद रंगराजन ने बयान दिया था कि इस हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार चन्द्रास्वामी है। उसने यह भी बताया कि उसने जैन आयोग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस षड्यंत्र का पूरा खुलासा किया था और आज भी वह सब जानकारी देना चाहता है।

जैन आयोग ने इस तथ्य को दर्ज किया है कि राजीव गांधी की हत्या के समय चन्द्रास्वामी और सुब्रमण्यम स्वामी चेन्नई मे थे। जैन आयोग के समक्ष यह तथ्य भी दर्ज किया है कि सी.बी.आई. की वह फाईल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई जिसमें चन्द्रास्वामी और सुब्रमण्यम स्वामी को दो विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा भेजे गए वायरलेस संदेश के दस्तावेज थे। इस पर यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि सी.बी.आई. हत्या षड्यंत्र के सूत्रधारों तक पहुंचने की कोशिश में लगी थी या उन्हें पहुंच से बाहर करने के लिये साक्ष्यों को मिटाने बनाने में?

ये सभी तथ्य सार्वजनिक जानकारियां है, आपकी पार्टी के लोगों से भी छिपे नहीं हैं। अर्जुन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता तो बहुत कुछ जानते हैं। पिछले दिनों पूरी कांग्रेस पार्टी ने आपके प्रति जबरदस्त प्रेम और आस्था का इजहार किया था, जब वे आप से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रहे थे। हम हैरान हैं कि आपके पति एवं अपने दिवंगत नेता स्व. राजीव गांधी की हत्या के जाने पहचाने षड्यंत्रकारियों की जांच एवं सजा के लिए आपके पार्टीजन उसी आस्था व प्रेम के साथ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं?

आपके पति स्व. राजीव गांधी के हत्या षड्यंत्र में चन्द्रास्वामी और सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका जग जाहिर है। इनके गॉड फादर खशोगी जैसे शस्त्र-व्यापारी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यह भी जगजाहिर है चन्द्रास्वामी और नरसिम्हा राव की रहस्यमयी घनिष्टता की षड्यंत्रकारी रंगत भी सबको दिखाई देती है- (विशेषकर सी.बी.आई. की अति महत्वपूर्ण फाइलें गायब होती रही हों) *'बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्लज्ज स्वरूप'* और *'दुनिया में सत्ता पर वही बैठेगा जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहेंगी'* की परिस्थिति को यदि घटनाक्रम से जोड़ कर देखें तो स्पष्ट है कि आपके पति 'इन्हीं' द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के शिकार हुए हैं।

उन चुनावों के पहले दौर में स्पष्ट हो चुका था की तमाम बाहरी मदद के बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों [illegible] सत्ता में नहीं आने वाली। दूसरी ओर राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के तहत उनकी मनमानी इच्छा के अनुरूप डालर के बेरोकटोक प्रवेश में दिक्कत होती। (ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय मुख्यधारा अर्थशास्त्रियों में मुख्य बहस का मुद्दा यह था कि तथा कथित *'आर्थिक सुधारों'* की गति धीमी हो या तेज हो।) *'नरसिम्हाराव-मनमोहन सिंह द्वय'* के नेतृत्व वाली कांग्रेस के राज में जिस प्रकार डालर की बेरोकटोक मनमानी चली है, उससे पुष्टि हुई है कि स्व. राजीव गांधी को हटाने का 'उनका' कृत्य उद्देश्यपूर्ण था।

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सभी मुख्यधारा पार्टियां मानों इस तथ्य के समक्ष समर्पण कर चुकी है कि *'सत्ता पर वही बैठेगा जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहेंगी'* और उनसे आशीर्वाद पाने की होड़ में लगी है।

नतीजे सामने है। विश्व व्यापार संगठन का राज कायम हो गया है. उद्योग और कृषि में विदेशी घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इसके बावजूद *'भारतीय उद्योग को कैसे बचायें'* के विषय में भारत का उद्योगपति वर्ग विचार शून्य बना हुआ है। यशवंत सिन्हा द्वारा [illegible] के सर्वसम्मति से पारित कर देना कांग्रेस, सी.पी.आई., सी.पी.एम. की मजबूरी एक ट्रेजिक कॉमेडी का चित्र ही प्रस्तुत करती है।

हम सीधे-साधे छत्तीसगढ़वासी है, मेहनत करके खाने वाले मजदूर और किसान हैं। दुनिया भर की राजनीति को जितना आप जानती है हम उसका आधा भी नहीं जानते होंगे। लेकिन एक मोटी बात जो हमें समझ में आती है वह यह है कि आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसके दिवंगत नेता स्व.राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्रकारी जनता की नजरों के सामने हैं, जिसे आपकी पार्टीजन भी जानते हैं - इसके बावजूद आपकी पार्टी की ओर से हत्या के षड्यंत्रकारियों की जांच एवं सजा के लिए कोई आवाज नहीं, कोई आन्दोलन नहीं? जो पार्टी अपने दिवंगत नेता के हत्या के षडयंत्रकारियों का पर्दाफाश करने की नहीं हिम्मत नहीं जुटा सकती हो, वह करोड़ों करोड़ जनता के हितों की रक्षा कैसे [illegible] अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारीवादी पूंजी एवम् उसकी पहली पसंद फासिस्ट पार्टियों के हमले से देशवासियों की रक्षाकर सकती है?

हम तो जानते हैं कि *'अन्याय कहीं भी हो न्याय के लिये हर जगह खतरा है'*। इसलिए हम शहीद नियोगी जी के हत्यारे उद्योगपतियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो साथ ही हम स्व. राजीव गांधी के हत्यारे षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करने में भी जुटे हैं। हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के पावन धरती के प्रवास के पश्चात् आप इन सवालों पर गंभीरता से विचार करेंगी।

भवदीय

दल्लीराजहरा — जनक लाल ठ

25-7-99 — अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ मु

Joint Action Forum of Indian People against WTO and anti-people policies (JAFIP)

✓

डब्ल्यू.टी.ओ. और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनताओं का संयुक्त कार्यवाही मंच (जाफिप) 9-10 जनवरी, छत्तीसगढ़ (रायपुर) सम्मेलन

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की मेजबानी में 9-10 जनवरी 1999 को जाफिप का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में भाग लेने वालों में, जी.एन. साईबाबा, डा. दर्शनपाल (ए.आई.पी.आर.एफ.), शेषा रेड्डी (उपाध्यक्ष, कर्नाटक राज्य रैयत संघ), चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत, हरपाल सिंह (भारतीय किसान यूनियन, उत्तरप्रदेश), चौधरी घासीराम नैण, चौधरी हरिकेश मलिक, चौधरी रामफल कंडेला (भारतीय किसान यूनियन, हरियाना), सरदार हरदेव सिंहसंधु (कीर्ति किसान यूनियन, पंजाब) और छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा के जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, शेख अंसार आदि शामिल थे। प्रस्तुत है चर्चा के बाद जारी किया गया प्रेस वक्तव्य :

अमर शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद शंकर गुहा नियोगी के लहू से सिंचित छत्तीसगढ की पावन धरती पर देश भर से आये संघर्षशील किसान, मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा स्वागत करता है।

जेल से रिहा होकर सीधा छत्तीसगढ की धरती पर आयोजित इस ऐतिहासिक किसान मजदूर सम्मेलन में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा के अध्यक्ष घासीराम नैण का स्वागत हम इस नारे के साथ करते हैं कि "जेल का ताला टूट गया हमारा साथी छूट गया।"

* डब्ल्यू.टी.ओ. उर्फ डंकल कानून और सत्ता की जन विरोधी नीतियों के विरोध में भारतीय जनता की संयुक्त कार्यवाही मंच जाफिप द्वारा 9-10 जनवरी को छत्तीसगढ के रायपुर नगर में हुए सम्मेलन में हम ऐलान करते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. भारत छोडो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत छोडो। डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्देशों के तहत हमारे देश के पेटेंट कानून, बीमा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, शहरी हदबंदी कानून, बदलने का, निजीकरण का हम विरोध करते हैं।

* छत्तीसगढ के और देश के किसानों की, एक के बाद एक तीसरी फसल, अकाल एवं पनिया अकाल की मार से बरबाद हो गई है। उन किसानों का कर्जा माफ करना होगा, पिछले वर्ष का बकाया एवं इस वर्ष का क्षतिपूर्ति मुआवजा देना होगा।

* नियोगी जी के हत्यारों को सजा दिया जाए

* 1 जुलाई 1992 के दिन भिलाई में बर्बर गोली चालन में 17 आंदोलनकारियों को गोलियों से भूनने के बाद उल्टे छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा के साथी जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, शेख अंसार, मेघदास वैष्णव सहित 23 नेताओं पर हत्या का फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। यदि मुकदमों के नाम पर छमुमो संगठन को कुचलने के प्रयासों को यदि नहीं रोका गया तो देश भर के किसान और मजदूर संगठन आंदोलन में कूद पडेंगे।

* चार-चार अदालतों के फैसले के बावजूद नौकरी से निकाले गये भिलाई क्षेत्र के 4200 श्रमिकों के बहाली में आनाकानी कर न्याय और कानून की धज्जियां उडाई जा रही है। इस मुद्दे पर छमुमो के न्यायाग्रह आंदोलन को जाफिप पूरे समर्थन की घोषणा करता है।

* हरियाणा के किसान नेता घासीराम नैण पर, छत्तीसगढ के नेता जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, शेख अंसार, मेघदास वैष्णव आदि पर, मुलताई के किसान कार्यकर्ताओं पर, आदिवासी मुक्ति संगठन, खरगोन के कार्यकर्ताओं पर और कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के नेता हरदेव संधू पर फर्जी हत्या के मुकदमों को वापस लिया जाए।

* आंध्रप्रदेश, दंडकारण्य और बिहार में पुलिस वालों द्वारा फर्जी मुठभेडों में सैकडों नौजवानों की बर्बर हत्या एवं इज्जत अधिकार के लिये आवाज उठाने वालों पर, हर किस्म के आंदोलनों पर अभूतपूर्व दमनचक्र का हम विरोध करते हैं।

* मुलताई के अमर किसान शहीदों को नमन करते हुए मुलताई के अमर शहीदों जुग-जुग जियों और 12 जनवरी शहीद दिवस अमर रहे के नारों को बुलंद करते हुए मुलताई के संघर्षशील किसानों को देश भर के किसानों-मजदूरों का पूरा-पूरा समर्थन देते हैं।

* हम मांग करते हैं कि किसानों को उसकी फसलों का वाजिब मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित कर दिया जाए। मंडी में खरीदी के समय किसानों को परेशान करने पर तत्काल रोक लगाई जाए।

* सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान-मजदूर कर्जे में दबा है। दूसरी ओर बडे-बडे उद्योगपति, राजनेता, हजारों करोड रुपया दबाकर अय्याशी कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि किसानों की जमीन कुर्की पर रोक लगाकर राजनेता, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, मजदूरों को एक समान दर्जा देकर वसूली नीति अपनाई जाए।

* 2 अक्टूबर 1989 को केन्द्र सरकार की घोषणानुसार कर्जा माफी के बावजूद की जा रही जबरन वसूली को रोका जाए।

* भारत सरकार राष्ट्रीय बीज निगम को प्रदत्त बीज राशि दस करोड रुपये से बढाकर सौ करोड रुपये करें ताकि हमारा देश का यह संस्थान मोनसेंटो महिको जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिक सके एवं किसानों को उचित बीज मिल सके।

* सम्मेलन में जाफिप ने आगामी 12 मार्च को बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत छोडो नारे के साथ दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता एवं बंगलोर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष प्रदर्शन का निर्णय लिया है।

सांस्कृतिक फासिस्टों- भाजपा, आर.एस.एस., विहिप, शिवसेना, बजरंग दल द्वारा हिन्दुत्व के नाम पर अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की हम निंदा करते हैं।

* अमरीका की सैनिक गुंडागर्दी और इराक पर हमले की निंदा करते हैं।

विनीत
संयोजन समिति जाफिप

बेरोजगारी से मारा-मारी

विगत 23 फरवरी 99 को रायपुर पुलिस लाईन में पुलिस में भरती के लिये आवेदकों को बुलाया गया था। 68 पदों के लिये 6,540 आवेदक पहुंचे थे। जाहिर है 6,540-68 = 6,472 आवेदक खाली हाथ वापस जायेंगे।

वापस जाने वालों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी तरह के नौजवान शामिल है। इससे स्पष्ट है कि बेरोजगारी का कारण आरक्षण नहीं लेकिन सत्ताधारियों की गलत नीतियां है।

पुलिस के अलावा आजकल किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार, भरती की खबर नहीं आती। लगता है डंकल कानून के तहत सरकार के पास जनता पर डंडा चलाने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा।

Anticipating assault on minorities after carrying out a campaign of pamphleteering from 30th November, unity solidarity meetings were held on 5th December 1992 in nearly 30 towns and cities of Chhattisgarh.

On 7th Dec. BJP state government clamped section144 all over M.P.

मंदिर मस्जिद तो एक बहाना है।
इरादा छंटनी मंहगाई से ध्यान हटाना है

साथियों,

पिछले दिनों से अखबार, रेडियो, टी. वी. या संसद, सब जगह अयोध्या का मुद्दा ऐसा छाया हुआ है कि करोड़ों बेरोजगारों, बढ़ती मंहगाई या किसानों की लूट के बारे में और देशप्रेमी विकास के बारे में सोच सकें।

१९८९ से विदेशी कंपनियों द्वारा हमारे प्यारे देश में चौतरफा लूट तेज कर दी है, १९८९ से ही अयोध्या के मुद्दे ने भी तेजी पकड़ी है। अगर धर्म के नाम पर जनता में फूट डालने के पीछे विदेशी कंपनियों की साजिश भी है, ये तो चाहती है कि भारत की जनता आपस में लड़ती रहे और उनकी लूट का धंधा चलता रहे।

ऐ देश के राज नेताओं,
जनता को गुमराह करना बंद करो

- देश की जनता को आपस में मत लड़वाओ,
- लुटेरे काले-अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आगे आओ,
- देशद्रोही आधुनिकीकरण और छंटनी मत करवाओ
  देशप्रेमी आधुनिकीकरण द्वारा सबके रोजगार की योजना बनाओ।
- मंदिर-मस्जिद की नहीं अयोध्या की नहीं,
  भिलाई का मुद्दा, रोजी-रोटी का अधिकार की बात करो।

छत्तीसगढ़ में काले-अंग्रेजों की फूट डालो-राज करो नीति नहीं चलेगी,
५ दिसम्बर को हम एकता और भाई-चारा दिवस मनाएंगे

इंकलाब का नारा लगाते चलो साथियों
नियोगी जी का रास्ता अपनाते चलो साथियों।
हिन्दू और मुसलमान, सिख और ईसाई,
एक मां के बेटे हैं, मत करो लड़ाई।।

अपील

तमाम जनता से अनुरोध है कि धर्म के नाम पर दंगा करने वालों से सावधान रहें और जनता में फूट डालने की हर कोशिश को नाकाम करें। भाजपा और कांग्रेस, जनता दल सहित तमाम राजनैतिक पार्टियों में मौजूद तमाम ईमानदार व देशप्रेमी कार्यकर्ता से भी अपील करते हैं कि दल गत राजनीति से ऊपर उठकर ५ दिसम्बर को "एकता और भाई-चारा दिवस" सफल बनाने में सहभागी बनें।

आपके साथी,

जनकराम साहू अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ दल्ली राजहरा	पोखनसिंह ठाकुर अध्यक्ष के. एन. पावर मिल्स कर्मचारी संघ, महासमुन्द	एस. के. सिंह उपाध्यक्ष प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, टाटा, रायपुर	लखनलाल सचिव प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, टेडेसरा
रूपनाथ राय सचिव प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई	मंथीर साहू सचिव प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई	कुंजलाल यादव सचिव प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ भिलाई	ईश्वर चन्द्र वर्मा अध्यक्ष प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ जमोदा मांढर
प्रेमनारायण वर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कपड़ा मजदूर संघ	गणेशराम छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ शोभाराम, राजनांदगाव	पन्नू पटेल छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ, कुम्हारी	राजकुमार तिवारी छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ हिर्री माइंस बिलासपुर
चितेलाल निषाद इंजीनियरिंग श्रमिक संघ भिलाई	सुखीलाल साहू महामंत्री छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ, दल्ली राजहरा	गणेशराम चौधरी उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	जनकलाल ठाकुर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

★ नवाब प्रिन्टर्स, राजहरा ★

Defying section 144 Mohalla committees of Bhilai workers to out unity-solidarity rallies on 7, 8 & 9th December in dozens of localities.

Bhilai-Durg city of 6 lakh population responded to our call and that was the first time we felt that working leadership over society in general ,was visible.

Chhattisgarh was totally riot-free and because of our programmes even communal tension was not felt.

In the protest demonstra -tion against Police killing of Adiwasis at Nagpur, thousands of works and peasants were arrested at Durg, Bhilai, Raipur, Rajnandgaon.

नागपुर में आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार

इस शताब्दी की बर्बरतम पुलिसिया कार्यवाही

प्रत्यक्षदर्शी श्री राजू निगम ने बताया *"अपनी मांगे मंजूर कराने के लिये पहुंची अनेक महिलाओं के दूधमुहे बच्चे उनकी आंखों के सामने ही कुचल दिये गये... गलियों में भी जवानों को तैनात कर रखा था इसलिए लोगों को कहीं से भागने का मौका नहीं मिला... हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक बच्चे, बूढ़े, जवान मरते गये."* (नवभारत २७.११.९४, पृष्ठ-३)

अपने ही देश में शरणार्थी हैं आदिवासी?

नर्मदा परियोजना में ३३००० लोगों को उजाड़ा जायेगा. इनमें से २७००० आदिवासी हैं. बस्तर को योधघाट एवं मोंगरा बांध परियोजनाओं में ५०,००० से अधिक आदिवासियों को उजाड़ा जायेगा. रायपुर जिला के देवभोग हीरा खदान क्षेत्र एवं चिरमिरी कोयला खदान क्षेत्रों से भी लाखों आदिवासियों को उजाड़ने की योजनाएं बनाई जा रही है.

लगता है सरकार ने जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है

२३ नवंबर को - कांग्रेस सरकार द्वारा नागपूर में सामूहिक नरसंहार

२४ नवंबर को - भाजपा सरकार ने दिल्ली में हजारों मकानों पर बुलडोजर चलाया. फिर बेघर हुए लोगों पर पुलिस गोली चालन से मानवों का वध.

२५ नवंबर को - कन्नूर (केरल) में पुलिस गोली चालन में ५ छात्रों का वध.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों (बराक) को खुश करने के लिये जनताओं की आवाज को पुलिसिया बूट से कुचलने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

इस हत्यारी व्यवस्था के खिलाफ [illegible] लहू टपकता रहेगा?

[illegible] भोपाल में विशाल प्रदर्शन [illegible] राज्यपाल को [illegible]

आदिवासी शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जायेगा.
जनता को मारोगे बन्दूक से ये बात भूल जाओ.

शहीद साथी अमर रहे.
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद.

[illegible]

CLASS STRUGGLE AND HISTORY

23 फरवरी 1946 जनक्रान्ति दिवस

जब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष में एक ही दिन में बम्बई में 228 मजदूर शहीद हुए थे ।

"आओ इतिहास के इस उजले उदाहरण से शिक्षा लें भविष्य को घनघोर अन्धेरे से बचाकर उसमें उजाला लायें"

8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा की। 9 अगस्त को गांधी जी एवं अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिये गये। देश की जनता ने अंग्रेजी राज के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी।

5 मई 1944 को स्वास्थ्य के आधार पर गांधी जी को जेल से रिहाकर दिया गया। जुलाई 1944 में गांधी जी ने राजगोपालाचारी सूत्र के आधार पर जिन्ना से चर्चा वार्तालाप शुरु की। अंतरिम सरकार की गठन के लिए जून-जुलाई 1945 में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अंग्रेजी सरकार आदि के बीच में शिमला सम्मेलन वार्ता का दौर चला।1945 के अन्त और 1946 के शुरुआत महीनों में कांग्रेस की समस्त शक्तियां चुनाव लड़ने पर केन्द्रित थी,इस प्रकार भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 से शुरु होकर 1945 तक समाप्त हो चुका था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सत्ताधारियों से सौदेबाजियों में व्यस्त थे। आर.एस.एस. की धारा के लोग तो हमेशा अंग्रेजी शासकों के पिछलग्गू बने रहे थे, उनके प्रमुख नेता डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी तो लगातार अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कठपुतली सरकार में मंत्री पद सम्हाले हुए थे।

1942 से 1945 के पश्चात् क्या भारत की जनता ने अंग्रेजी शासकों को भगाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी ? यदि लड़ी तो उसका गौरवशाली इतिहास जनता के बीच क्यों नहीं है ?

☆ क्या आप जानते हैं कि 18 फरवरी 1946 के दिन मुम्बई, करांची सहित अनेक शहरों में अंग्रेजी सेना- नौसेना और एयरफोर्स के 30 हजार भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था।

☆ क्या आप जानते हैं कि 22-23 फरवरी के दिन विद्रोहियों की समर्थन में और अंग्रेजी शासन के खिलाफ बम्बई के 3 लाख से भी अधिक मजदूरों एवं दीगर नागरिकों ने बम्बई की सड़कों पर संघर्ष का मोर्चा सम्हाला था ?

☆ क्या आप जानते हैं, इस 22 और 23 फरवरी 1946 के दिन अंग्रेजी पुलिस फोर्स से टक्कर लेते हुए बम्बई में 228 भारतीय मजदूर शहीद हुए थे, 1046 घायल हुए थे

☆ क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासकों को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा और अंतिम धक्का इस गौरवशाली संघर्ष ने दिया था।

☆ तो फिर हजारों मजदूरों की कुर्बानी भरा यह इतिहास जनता से छिपाया क्यों जा रहा है ?

☆ प्राथमिक विद्यालयों, उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यलयों की पाठ्य पुस्तकों में इस संघर्ष का उल्लेख क्यों नहीं है ?

छत्तीसगढ़ के अमर सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह के गौरवशाली इतिहास को सत्ताधारियों ने दबा डाला था - उसे शहीद का. शंकर गुहा नियोगी ने उजागर किया था।

आज भी छत्तीसगढ़ के मेहनतकशों ने 23 फरवरी 1946 को स्वतंत्रता संग्राम जनक्रांति दिवस को अपने संघर्षों को सींचे लहू की स्याही से प्रकाशित करने का संकल्प लिया है।

CLASS STRUGGLE AND HISTORY

8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मजदूर वर्ग की कुर्बानी और संघर्ष का इतिहास

मजदूर वर्ग की कुर्बानी और संघर्ष का इतिहास है
हमारे लिए एक उदाहरण है,
एक रास्ता है, जिस राह पर चलकर
1857 में न्यूयार्क गारमेन्ट महिला श्रमिकों के
कुर्बानी भरे संघर्ष की राह,
1908 में महिला श्रमिकों द्वारा
8 घंटे कार्यावधिका संघर्ष
खदान मजदूर शहीद अनुसुईया की राह,
रायगढ़ की बहन शहीद सत्यभामा की राह
छत्तीसगढ़ में
लाल-हरा का संघर्ष का इतिहास बताता है
जब-जब मेहनतकशों ने
शोषण,लूट, अत्याचार की,
व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ा है
महिलाओं का दल
मजदूर आन्दोलन का सबसे मजबूत किला,
सबसे अग्रगामी दस्ता रहा है।
मशीनीकरण के खिलाफ
और शराब-माफिया के खिलाफ
दल्ली राजहरा में,
पिथौरा, बसना, सरायपाली क्षेत्र के
जमीन दो या जेल दो आन्दोलन में
राजनांदगांव, टेक्सटाईल श्रमिकों के संघर्ष में
9 वर्ष में भिलाई में जारी महालड़ाई में
लहू की स्याही में लिखा
छत्तीसगढ़ आन्दोलन का इतिहास
1 मई के शिकागो के शहीदों से लेकर
8 मार्च संघर्ष की महिला श्रमिकों का इतिहास
शहीद का. शंकर गुहा नियोगी की
कुर्बानी का इतिहास
वह रास्ता है,
जिस पर चलकर कदम-दर-कदम
तोड़ देंगे सब जंजीरें गुलामी की,
आओ, चले चलो, बढ़े चलो
मुक्ति की इस राह पर
शहीदों की इस राह पर
एकता के सुर में संघर्ष के गीत गाते चलो
आव्हान है सब महिलाओं को,
मजदूरों को, किसानों को,
बनाएंगें हम शोषण विहीन छत्तीसगढ़
नए भारत के लिए नया छत्तीसगढ़
अमरीकी कंपनी खूनी कार्बाइड के
हमले के खिलाफ न्यायाग्रह में डटी
भोपाल की बहनों के साथ
देश के कोने कोने से आई बहनों के साथ
कदम ताल कर हम,
विदेशी कंपनियों के दलाल के खिलाफ
डंकल-डालर के हमले से सत्ताधारियों के खिला
बढ़ती मंहगाई, छटनी, निजीकरण के खिलाफ
हमारा एक जुटता प्रदर्शन है।

छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद-जिन्दाबाद

विनीत : लीलाबाई, बसनीन बाई, सुधा बाई (दल्ली राजहरा) चन्द्रकला बाई, श्यामवती बाई, आरती बाई (भिलाई)
कमलाबाई (बीरगांव-रायपुर) शेख अंसार, अनूप सिंह, गणेश राम चौधरी, जनकलाल ठाकुर

C.M.M. has been working t) present a scientific techno economi model for development of Chhattis arh. Basic features of which are prese ited in this advertisment.

सब हाथ ला काम, सब खेत मा पानी

संभव

रोजगार

(1) बी.एस.पी. में अंधाधुंध मशीनीकरण पर रोक लगाकर 30 हजार नये मजदूरों की भर्ती एवं दल्लीराजहरा में मशीनीकरण के जगह 3000 नए मजदूरों की भर्ती कर खदानों को विकसित किया जाए रावघाट खदान में अर्द्धमशीनीकरण खनन-नीति अपनाकर 12,000 नवजवानों को रोजगार दिया जाए.

(2) छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित 25,000 करोड़ पूंजी निवेश में जरूरत के आधार पर स्वदेशी तकनीक का विकास हो जिससे प्रति 1 करोड़ रु. पूंजी निवेश कम से कम 200 लोगों को रोजगार मिलें 100 से कम रोजगार उत्पन्नता प्रति करोड़ रु. पूंजी निवेश वाले तकनीकि विकल्पों को देशद्रोही घोषित किया जाए।

िंचाई

(1) शिवनाथ ी पर 10 स्टाप डैम की श्रृंखला बनाक िलाई अपने जरूरत का पानी प्राप्त करें खरा, गोंदली, गंगरेल, तांदुला बांधों के ानी से 45 लाख एकड़ कृषि भूमि में सिं ाई हो।

(2) कृषि व उ ग में संतुलन बनाने के लिए, प्रस्तावित 25 हजार करोड़ रुपये में से प्रति रु. 10 प सिंचाई पर खर्च किया जाय।इससे प्राप्त . हजार 500 करोड़ रुपये से 10-10 ला रुपये की 25 हजार योजनाएं बन सकती हैं और हर दो गांव के बीच एक बांध, हन, तालाब या नलकूप का निर्माण संभ है, इससे गांव के लोगों को गांव में र गार मिलेगा, पलायन रुकेगा।

छत्तीसगढ़ मुक्ति ोर्चा

छत्तीसगढ़ उद्योग बचाओ आन्दोलन के तहत विचार गोष्ठी में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का दस्तावेज

श्रम बाहुल्य तकनीक को आधार बना कर ही हमारे उद्योग बच सकते हैं, बढ़ सकते हैं

औद्योगिक संकट,

कारण : मैनेजमेंट व सरकार की अदूरदर्शिता एवं दलाली

छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थिति बहुत खराब चल रही है। सीमेन्ट उद्योग भारी मंदी की मार से गुजर रहा है। खबर पढ़ने को मिली है कि सोनाडीह स्थित टाटा इस्पात के सीमेंट कारखाने को फ्रांस की लाफार्ज कम्पनी को बेच दिया गया है। इस्पात उद्योग की स्थिति तो उससे भी खराब है। रायपुर के इर्द-गिर्द तीन प्रसिद्ध इस्पात उद्योग थे – एलाइड स्टील, रायपुर एलाइज एवं सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स। आज ये तीनों कारखाने वीरान हैं। बड़े ताम झाम एवं करोड़ों रुपया की सरकारी सहायता के साथ रायपुर सिलतरा में राजेन्द्रा स्टील का इस्पात कारखाना लगाया गया था। यह कारखाना 6 वर्ष के भीतर ही बंद हो गया एवं खबर है कि उसका मालिक 660 करोड़ रुपया सरकारी एवं निजी कर्ज को छोड़कर विदेश भाग गया है। बोरई में जब एच.ई.जी. का स्पन्ज आयरन स्टील प्लांट लगा तब इस उद्योग के सुनहरे भविष्य का बेहद प्रचार हुआ था। दो वर्ष के भीतर जब इस्पात के स्क्रैप पर आयात ड्यूटी हटा ली गई तो इस उद्योग को जिन्दा रह पाना मुश्किल हो रहा है। उरला औद्योगिक क्षेत्र के लगभग सभी फेरो एलॉयज उद्योग बंद पड़े हैं। कुल 50 से अधिक उद्योग बंद हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रिपीटीटिव आयटमों की निविदाएं बाहर भेजने एवं संयंत्र द्वारा भुगतान में दिक्कत से 166 सहायक उद्योगों का आर्थिक संतुलन डांवाडोल है।

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन कारखानों में से एक भी कारखाना मजदूर की गलती के कारण नहीं बल्कि सभी मैनेजमेंट और सरकार की गलत नीतियों के कारण विनाश की स्थिति में आकर खड़े हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन के डंडे तले 800 से अधिक वस्तुओं के आयात के प्रतिबंध हटाने एवं आयात शुल्क में भारी कमी करने से स्थिति और गंभीर हो गई है। इस्पात के आयात शुल्क कम करने से कोरिया, जापान और ब्रिटिश स्टील हमारे मार्केट में छा गया है एवम् हमारे देश के इस्पात उद्योग गंभीर हालात में पहुंच गए हैं। कोयले पर से आयात शुल्क हटाने के कारण आस्ट्रेलिया का कोयला हमारे मार्केट में छा गया है एवं देश का कोयला उद्योग संकट में है।

विचार शून्य उद्योगपति वर्ग का विधवा विलाप

के.के. झा, अध्यक्ष, बी.एस.पी. एंसीलरी इंडस्ट्रीज एसोसियेशन "अधिकांश उद्योग चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र, धीरे धीरे निश्चित मौत की तरफ बढ़ रहे हैं।"

26 फरवरी 1999, दैनिक भास्कर

गिरीश बंसल, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज "सरकार देश के उद्योगों को बढ़ावा देने की बजाए आयात को बढ़ावा दे रही है ..."

26 फरवरी 1999 दैनिक भास्कर

महेश कक्कड़, अध्यक्ष, उरला इंडस्ट्रीज एसोसियेशन " देशी उद्योग को मरने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी जाने वाली सुविधाएं तत्काल बंद करें"।

25 मई 1999, देशबंधु

एच.के. शाह चेयरमैन, सिम्प्लेक्स उद्योग समूह "ऐसी नीतियां बना दी गई है कि उद्योग करीब बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकार को विश्व व्यापार संगठन के दबाव में नहीं आते हुए यहां के हित में सोचना चाहिए"।

24 फरवरी 1999, दैनिक भास्कर

राहुल बजाज, भारतीय उद्योग परिसंघ, सी.आई.आई. के वर्तमान अध्यक्ष " बहुकेन्द्री विश्व व्यवस्था दरअसल में अमरीका की दादागिरी व एककेन्द्री विश्व व्यवस्था का दूसरा नाम है। मैं एक स्वाभिमानी भारतीय हूं लेकिन इस विश्व व्यवस्था में मुझे नौकर जैसा लगता है"

18 अगस्त 1997, इंडिया टुडे

जबकि अब विलाप करने वाले सिम्प्लेक्स समूह के मालिकों और भिलाई के उद्योगपतियों ने ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष में जनता के अमर सेनापति कामरेड शंकर गुहा नियोगी की हत्या करवाई थी।

जबकि विदेशी कंपनियों की दलाली करने वाले भाजपा और कांग्रेसी नेताओं को करोड़ों करोड़ रुपया चन्दा व घूस यही उद्योगपति देते हैं और अपने कारखाने के मुनाफा, कमाई कामगारों का वैधानिक हिस्सा, काम देने में उनकी नानी मरती है।

जबकि, जिस समय छत्तीसगढ़ का मजदूर वर्ग 10 वर्ष पूर्व से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्र खतरे को भांप कर उनसे संघर्ष के मैदान में डटा था, उस समय ये उद्योगपति, अदूरदर्शी उनके आगमन का ताली पीट पीट कर स्वागत कर रहे थे। "हमें नया नया विदेशी तकनीक चाहिए" "हमें विदेशी पूंजी निवेश चाहिए"।

अब, जब विदेशी कंपनी वाले कहा हमारी पूंजी, हमारी तकनीक है तो स्वामित्व भी हमारा है, तब जाकर हमारे देश के उद्योगपतियों ने हाय-तौबा शुरु किया।

अब इसीलिए इसे विधवा विलाप नहीं तो क्या कहेंगे ?

श्रम बाहुल्य तकनीकी विकल्प : हमारी ताकत, पूंजी बाहुल्य तकनीकी विकल्प : हमारे गले में पत्थर

भिलाई इस्पात संयंत्र सहित पूरे सेल पर करीब 21 हजार करोड़ रुपये का बोझ उसके गले में सबसे बड़ा पत्थर बताया जा रहा है। इस कर्ज का बड़ा हिस्सा 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्जा सेल के पूर्व चेयरमेन कृष्णामूर्ति के समय में अंधाधुंध मशीनीकरण में लगाई गई पूंजी है। शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में भिलाई

कृ.पृ.प...2

इस्पात संयंत्र में कृष्णामूर्ति की अंधाधुंध मशीनीकरण के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष चलाया गया। दल्ली राजहरा की खदानों में अर्धमशीनीकरण की वैकल्पिक नीति को कार्यरूप दिया।

80 के दशक में सेल ने लगातार अनेक वर्षों तक विश्व के इस्पात उद्योग में अग्रणी स्थान रखा। मोर्गन स्टेनली द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार श्रम वेतन अंश कम होने के कारण ही "सेल" अन्य देशों के मुकाबले मजबूत स्थिति में रहा। उस अध्ययन के अनुसार सेल में श्रम वेतन अंश मात्र 14% था, जबकि जापान, कोरिया में श्रम वेतन अंश 26% एवं अमरीका में श्रम वेतन अंश 31% है। इसका अर्थ यह है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में 55 हजार मजदूरों का श्रम वेतन अंश कोरिया, जापान के 6 हजार मजदूरों से कम है।

अभी एक अन्य अध्ययन के अनुसार एक टन इस्पात की उत्पादन लागत में जापान में श्रम घंटा की दर 1000 रुपये, कोरिया में 850 रुपये एवं भारत में मात्र 50 रुपये है। अर्थात मजदूर की संख्या ज्यादा होते हुए भी वेतन अंश बहुत कम है।

अगर हम निर्यात क्षेत्र को भी देखें तो स्पष्ट है कि श्रम बाहुल्य तकनीक के क्षेत्रों में हम प्रतिस्पर्धा में हैं। इस प्रकार तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि श्रम बाहुल्य तकनीकी विकल्प हमारी ताकत है एवं पूंजी बाहुल्यता तकनीकी विकल्प हमारे गले का फंदा है।

आज, अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी पूंजी से खतरा मिलने के बाद जहां, बचाओ, बचाओं तो चिल्ला रहा है, लेकिन उद्योग के प्रश्न पर, तकनीक के सवाल पर अपनी विचार शून्यता को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। इस विचार शून्यता एवं अदूरदर्शिता का बड़ा सटीक और कॉमिक अभिव्यक्ति के रूप में रिलायंस के पूर्व चेयरमेन उद्योगपति श्री मोदी की टिप्पणी ने बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका में छपी है कि – *"हमने सोचा था कि हमारे पीछे में एक लात पड़ेगी तो वह हमें कुछ फायदा पहुंचायेगा लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने यदि हमें संरक्षण नहीं दिया तो उद्योग चौपट हो जायेंगे।"* इस विचार शून्यता की स्थिति में उद्योगपति वर्ग के दिमाग में अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी पूंजी (International Monopoly Capital) के प्रचार तंत्र द्वारा यह बात फीडिंग की गई है कि – मजदूर कम कर दें तो शायद हमारा उद्योग बच जायेगा। जबकि वास्तव में जैसा कि ऊपर के अध्ययन से स्पष्ट है कि विदेशी कंपनियों के मुकाबले सस्ती श्रम शक्ति के कारण श्रम बाहुल्य तकनीक ही हमारी ताकत का आधार है।

आर्थिक मंदी बनाम अंधाधुंध मशीनीकरण

रोजगार बढ़ेगा तो क्रय क्षमता बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास की गति मिलेगी

1954 में भिलाई इस्पात संयंत्र में 96000 श्रमिक थे। आज यह संख्या घटकर 42000 रह गई है। मशीनीकरण के दलालों का सपना है कि इतना बड़ा संयंत्र मात्र 6000 मजदूरों से चलाएं। मजदूरों की संख्या में भारी कमी के कारण भिलाई के बाजार में कितनी मंदी आई है। यदि यह संख्या 6000 हो जाएगी तो भिलाई के हजारों दुकानदारों व्यापारियों का क्या होगा।

उद्योग बचाओ आन्दोलन के प्रवक्ता, राजीव दीक्षित के अनुसार पिछले 10 वर्षों के तथाकथित आर्थिक सुधारों के कारण 2 लाख 62 हजार से अधिक कारखाने बंद हो गए हैं। यदि एक कारखाने में 20 मजदूरों की औसत पकड़ें तो भी 52 लाख से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए। 52 लाख मजदूरों के साथ दो करोड़ परिवार की क्रय क्षमता (बाजार से सामान खरीदने की क्षमता) समाप्त हो गई। इस प्रकार बाजार में मांग को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को गति देने के लिए अधिकतम जनता को रोजगार आवश्यक है।

हमारी अपनी पूंजी, हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी तकनीकी एवं अपने बाजार की ताकत के आधार पर जनता की क्रय क्षमता में वृद्धि द्वारा ही आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। नियोगी जी ने इसी आर्थिक सिद्धांत की दृष्टि से दल्ली राजहरा में अंधाधुंध मशीनीकरण के विरोध में अर्धमशीनीकरण की वैकल्पिक नीति स्थापित की थी। आज भी छ.मु.मो. उस आर्थिक सिद्धांत के अनुसार तकनीकि के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके अनुसार छ.मु.मो. 100 से कम ई. आई. सी.सी. सूचकांक (रोजगार उत्पन्नता प्रति करोड़ निवेश) वाले तकनीकी पैकेज को राष्ट्रद्रोही पैकेज घोषित करते हुए अस्वीकार करने की मांग करता है।

ऐसा नहीं कि हमारे शासनकर्ता वर्ग इस सिद्धांत से परिचित नहीं है. विश्व व्यापार संगठन और अमरीका के दरबार में इसी आर्थिक सिद्धांत की दुहाई देकर गिड़गिड़ाते हैं। विश्व व्यापार संगठन के तहत वर्ष 1999 में कृषि में समझौता (AOA) होना है। इस सिलसिले में वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। उसमें भारत सरकार ने जनवरी १९९९ में दिये अपने प्रस्ताव 'Food Security An Important Non-Trade Concern (AIE/44)' में कहा है – "कृषि उदारीकरण से विकासशील कृषि प्रधान देशों की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं का हल नहीं होगा। अपितु, विकासशील कृषि प्रधान देश में जी.डी.पी. की वृद्धि के लिये कृषि की आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होगा क्योंकि अच्छा कृषि उत्पादन, जनसंख्या के बड़े बहुमत की क्रय-क्षमता को बढ़ाता है, जो फिर औद्योगिक वृद्धि को तेजी प्रदान करता है....।

... खाद्य-सुरक्षा की चुनौती का सामना करने के लिये एवं ग्रामीण रोजगार की संभावना बनाए रखने के लिए इन देशों को अपने कृषि क्षेत्र को पर्याप्त सहयोग देने की अनुमति देने की आवश्यकता है।"

लेकिन हमारा संघर्ष, इसी मूलभूत आर्थिक सिद्धांत को आधार बना कर संघर्ष में आगे बढ़ते जा रहा है कि "जनसंख्या के बड़े बहुमत की क्रय-क्षमता को बढ़ाता है, जो फिर औद्योगिक वृद्धि को तेजी प्रदान करता है.....।" उस पर शासक हमसे फिर जाते हैं। जाहिर है विदेशी आर्थिक हमले के समक्ष भारत के उद्योगपति वर्ग के नहीं टिक पाने का कारण यह है कि उद्योगपति वर्ग विचार शून्यता की स्थिति से नहीं उबर पाया है एवं विचार शून्यता की स्थिति में ऐसी नीतियों को बढ़ावा दे जाते हैं जो कि उनके स्वयं के हितों के लिए घातक हो सकता है।

अगर छ.मु.मो. के ट्रेड यूनियन ने उत्पादन उत्पादकता को भी महत्व देती है और इसके साथ बी.एस.पी. में, खदानों में, बी.एन.सी. टेक्सटाइल मिल, राजनांदगांव में, एच.एस.सी.एल., बी.आर.पी. इंजीनियरिंग उद्योग, केमीकल उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, बिजली, बैंक, बीमा आदि समस्त उद्योगों में अंधाधुंध मशीनीकरण का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ के करोड़ों जनता को उत्पादक रोजगार के आधार पर औद्योगिक विकास की नीति के लिए लड़ाई जारी रखेगा।

भिलाई के उद्योगपतियों, विदेशी कंपनियों के हमले के समक्ष, विधवा-विलाप बन्द करो, यह प्रभावी कदम उठाओ –

★ विदेशी कंपनियों की दलाली करने वाली भाजपा एवं कांग्रेस पार्टी को एक पैसा चुनावी चन्दा मत दो। ★ सभी राशि में मजदूरों का बकाया अंतरिम राहत का भुगतान करो। ★ यानि भ्रष्टाचारी विदेशी दलालों को मत पालो, उत्पादन करने वाले हाथों को उनका अधिकार उनकी मांग दो।

मजदूर काम करेगा, उद्योग बचेगा

Rigorous studies regarding industrial and agricultural techno-economic options serve a dual purpose.

On one hand, it exposes the total 'vichar-shoonya' state of the ruling classes and on the other hand it provides people a vision of 'A New Chhattisgarh' to fight for, with all their toil and sacrifices.

भिलाई की सभा में प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का कथन-

''वे जब सत्ता में आए तो देखा कि कारखाने बंद हो रहे हैं, स्टील का संयंत्र खतरे में है, सार्वजनिक उद्योगों पर ताले लग रहे हैं, मजदूरों को 6-6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अगर प्रबंध ठीक नहीं होगा और प्रतियोगिता में वह टिक नहीं सकेगा तो कठिनाईयां पैदा होगी। मजदूर का दोष नहीं अगर कारखाना बंद होता है। जरूरत से ज्यादा लोग अगर लिए जाते है तो इसके लिए मजदूर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।'' -

-देशबंधु, दिनांक 22 सितम्बर 1999

1984 में भिलाई इस्पात संयंत्र में
मजदूर संख्या - 96 हजार
आज 1999 में भिलाई इस्पात संयंत्र में
मजदूर संख्या - 49 हजार

इसके बावजूद 21 सितम्बर की भिलाई आमसभा में प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने कहा कि इस्पात संयंत्र डूब रहे है, उनमें जरूरत से ज्यादा मजदूर है।

बी.एस.पी. के एम.डी. विक्रान्त गुजराल का भी यह कहना है कि बी.एस.पी. में जरूरत से ज्यादा मजदूर है

क्या प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी और एम.डी. विक्रान्त गुजराल का कथन सही है कि-'' इस्पात संयंत्र में जरूरत से ज्यादा मजदूर है।''

हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के एम.डी. विक्रान्त गुजराल से पूछते हैं ?

क्या यह सत्य नहीं है कि भिलाई इस्पात संयंत्र पर 4000 करोड़ रु. से अधिक का कर्जा लदा है, जिसका ब्याज 34 करोड़ प्रति माह देना पड़ रहा है।

क्या यह सत्य नहीं है कि यह 4000 करोड़ रुपया कर्जा सेल के चेयरमेन कृष्णामूर्ति के जमाने में किए गए अंधाधुंध मशीनीकरण खरीदी के कारण हुआ है। जिसका तार्किक विरोध शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में छ.मु.मो. ने किया था एवं आज भी करते आ रहा है।

क्या यह सत्य नहीं है कि अंधाधुंध मशीनीकरण के कर्जे का ब्याज पटाने की 34 करोड़ रुपये की यह मासिक किश्त राशि, 49 हजार मजदूरों के मासिक वेतन से भी अधिक है?

जबकि यह कर्जा अंधाधुंध मशीनीकरण के कारण है तो सजा हमारे नौजवानों को क्यों, जिनके रोजगार की जगह को छीना जा रहा है।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं एम.डी. विक्रांत गुजराल हमारे इस्पात अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए कोरिया भेजते है और कोरिया का उदाहरण बताते है कि वहां इतने बड़े संयंत्र को मात्र 6000 मजदूर चलाते है, भिलाई में मजदूर जरूरत से ज्यादा है

प्रधानमंत्री एवं एम.डी. महोदय को हम बताना चाहते हैं कि अंधाधुंध मशीनीकरण के कारण कोरियो के इस्पात संयंत्र भारी कर्जे के बोझ में दम तोड़ रहे हैं। कोरिया की प्रमुख कंपनी *''हैनबो आयरन एण्ड स्टील कम्पनी''* पर 5 बिलियन डालर यानि करीब 22 हजार करोड़ रुपया कर्जा अंधाधुंध मशीनीकरण खरीदी के कारण हो गया, जनवरी 1997 से दीवालिया होगई और विगत 13 जुलाई 1999 को अमरीकी कंपनियों के कंसोर्टियम ने उसे हथिया लिया है।

इस्पात उद्योग के जानकार यह अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन उर्फ डंकल कानून के ट्रिम्स (TRIMS : Trade Related Investment Measures) प्रावधानों के तहत विदेशी इस्पात के लिए दरवाजे खोलने के कारण हमारे इस्पात उद्योग पर सबसे गंभीर संकट आया है। इसके बावजूद भिलाई की सभा में जब अटल बिहारी बाजपेयी कहते है कि'' प्रतियोगिता में वह टिक नहीं सकेगा तो कठिनाईयां पैदा होगी।का अर्थ यही है कि यदि विदेशी उद्योग हमारे उद्योग को बरबाद भी कर दें तो हम कुछ नहीं कर सकते।

भिलाई की सभा में अटल जी ने कहा दोष मजदूर का नहीं प्रबंधन का है। अभी 6 महीने पहले अटल सरकार ने मोहन कमेटी के नाम पर मैनेजरों का वेतन एकदम दोगुना कर दिया और मजदूरों को काम छोड़ने के दबाव दिया जा रहा है।दोषी को पुरस्कार, निर्दोष को सजा, वाह रे अटल !

- मजदूर संख्या कम करने के लिए बी.एस.पी.के रेगुलर मजदूरों पर जबरवाली रिटायरमेंट के लिए दबाव।
- एच.एस.सी.एल.की स्थिति जर्जर, 6-6 महीनों का बकाया वेतन मांगने पर पुलिसिया दमन की सौगात।
- 3 अक्टूबर को बी.एस.पी. के ठेकेदारी मजदूरों पर बर्बर लाठीचार्ज
- बी.आर.पी. एवं बी.एन.सी. मिल राजनांदगांव की स्थिति जर्जर, उत्पादन एवं रोजगार खतरे में।
- टाटाराव कमेटी की सिफारिश के नाम पर एम.पी.ई.बी.का विखंडन एवं भारी छटनी, सभी राजनैतिक पार्टियों की भूमिका संदिग्ध, म.प्र. [illegible] कर्मचारी जनता यूनियन द्वारा संघर्ष।
- बैंकिंग उद्योग एवं कर्मचारी विरोधी वर्मा कमेटी रिपोर्ट 45 हजार करोड़ रुपये डूबत खातों के बारे में [illegible], कर्मियों के लिए छटनी की तलवार
- अमरीका की राजधानी में बैठकर भाजपा वित्त [illegible] द्वारा बीमा क्षेत्र को तीन दिन के भीतर विदेशी कंपनियों हेतु खोलने की घोषणा।

THE FIRST CITIZEN OF DALLIRAJHARA IS FROM WORKERS FAMILY.

म.प्र. में जगह-जगह धनवानों का बोलबाला लेकिन....

दल्लीराजहरा नगर की प्रथम नागरिक मजदूर परिवार से

नगर पालिका परिषद के लिये सम्पन्न चुनावों में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी श्रीमती पुरोबी वर्मा भारी मतो से विजयी हुई। श्रीमती पुरोबी वर्मा को 6439 वोट मिले। जबकि दूसरे स्थान पर आई कांग्रेस की प्रभा सोनछत्रा को 3962 वोट ही मिले। ज्ञातव्य है कि श्रीमती पुरोबी वर्मा मजदूर परिवार से हैं, उनके पति - राजेन्द्र वर्मा, बी.एस.पी. में श्रमिक हैं। पार्षद पदों के लिए भी छ.मु.मो. के प्रत्याशियों को अच्छी खासी सफलता मिली। छ.मु.मो.के 11 प्रत्याशी विजयी हुए, जबकि कांग्रेस के मात्र 5 प्रत्याशी और भाजपा के मात्र 3 लोग ही पार्षद पदों के लिए चुने गये।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथी- बिहारी लाल ठाकुर न.पा. परिषद के उपाध्यक्ष एवं सभापति निर्वाचित हुए हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अन्य सभी जो कि पार्षद पदों पर चुने गये हैं, वे इस प्रकार है -

वार्ड वीरनारायण सिंह 10 से	-	राजकुमार बोरकर
वार्ड बजरंग 11 से	-	बिहारीलाल ठाकुर
वार्ड दुर्गावती 12 से	-	दीनानाथ
वार्ड घोड़ा मंदिर -13 से	-	सुखवन्तिन बाई
वार्ड सुदामा नगर -14 से	-	भगवती बाई
वार्ड नियोगी नगर-15 से	-	आशा नियोगी
वार्ड भगतसिंह 16 से	-	हीरालाल
वार्ड झमितकुंवर वार्ड 17 से	-	मथुरा बाई
वार्ड दन्तेश्वरी 18 से	-	मुरली रावटे
वार्ड डा. अम्बेडकर 19 से	-	राजू डहारे
वार्ड नेहरू नगर 26 से	-	श्री निवास

शराब बांटने वाले सांसद प्रतिनिधि को जनता ने धर- दबोचा

चुनाव के दिन शराब बांटने वालों को रोकने के लिये दल्लीराजहरा के हरपारा मोहल्ला में छ.मु.मो. के साथी तैनात थे। रात के डेढ़ बजे भाजपा के सांसद प्रतिनिधि सुरेश सिंग को एक बिना नंबर की मारूति वेन में शराब बांटते हुए वीरनारायण सिंह चौक पर पकड़ लिया। सुबह 4 बजे तक उसे घेर कर रखा गया और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया।

पूरे म.प्र. में नगरपालिका चुनाव में शराब, पैसा और गुण्डागर्दी का जोर रहा।

एकमात्र दल्ली राजहरा ऐसा शहर है, जहां शराब, पैसा और गुण्डागर्दी को चलने नहीं दिया गया। लोकतंत्र के दर्शन तो वास्तव में एकमात्र दल्ली राजहरा में ही हुए हैं।

करोड़पति सेठों को जनता ने धूल चटाई

इस बार के चुनाव में शहर के दो बड़े सेठ शांतिलाल जैन, कांग्रेस की ओर से पंजा छाप में और मोहनलाल अग्रवाल, भाजपा की ओर से फूल छाप में पार्षद के लिये खड़े थे। ज्ञातव्य है कि शांतिलालजैन राजहरा व्यापारी संघ का अध्यक्ष है और मोहनलाल अग्रवाल राजहरा खदान का एक करोड़पति ठेकेदार है

लेकिन राजहरा की जागरूक जनता ने इन दोनों सेठों को बुरी तरह से हराया।

"When a witness named industrialists Keida and Moolchand, their co-accused goons (their doggies) went beserk"

A Day's proceedings in Com.Neogi murder trial at Durg captures the high pitched battle between the private army of industrialists and the democratic force of workers organisation.

In the beginning CBI and the accused industrialists had colluded tohave an 'in-camera trial'

But we oppsed it and got the proceedings to be conducted in an open Court. This was the most difficult thing

An interesting anecdote : Session Court has observed inthe proceedings that the accused Chandrakant Shah and Gyan Prakash Mishra insisted that the Court should take cognizance of the phamplete"Mitan' which called them to be the pet dogs of industrialists and that they should be protected from defamation. Session Judge concluded the controversy by advising them to approach the appropriate forum for redressal of their grievances.

अदालत में गवाह द्वारा केडिया-मूलचन्द का नाम लेते ही उद्योगपतियों के कुकुर पगला गए

न्यायाधीश महोदय के निर्देशों का मखौल उड़ाया

प्रिय साथियों,

दिनांक ३० अक्टूबर ९५ को नियोगी जी हत्याकांड में हत्यारे उद्योगपतियों के खिलाफ मुकदमें की सुनवाई के दौरान ड्राईवर बहलराम साहू एवं रायपुर के पूर्व सहायक श्रमायुक्त श्री आर.जी. पाण्डे की गवाही हुई..

उनकी गवाही के दौरान साथी बहलराम ने बताया कि उनकी हत्या से कुछ दिन पूर्व नियोगी जी ने उसे मूलचंद शाह एवं केडिया के गुण्डों द्वारा जानलेवा हमले की संभावना व्यक्त की थी. इतना सुनना था कि अभियुक्तों का वकील अशोक दादर उछल पड़ा एवं साक्षी के बयान में व्यवधान डालने का प्रयास करने लगा.

बाद में प्रभुनाथ मिश्रा एवं एक अन्य व्यक्ति नाम नामालूम, जो अदालत परिसर के भीतर कई बार साक्षियों एवं छ.मु.मो. कार्यकर्ताओं पर फोटो-कैमरा फ्लेश चमकाने लगे. उनके हाव-भाव से स्पष्ट था कि वे गवाहों को आतंकित करने एवं उत्तेजना फैलाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे.

साथियों एवं छ.मु.मो. कार्यकर्ताओं के निवेदन के अनुसार उनके वकील के माध्यम से न्यायाधीश महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया. न्यायाधीश माननीय टी.के. झा ने स्पष्ट शब्दों में अदालत परिसर के भीतर इस प्रकार फोटो नहीं खींचने के निर्देश दिए.

उसी समय मूलचन्द शाह के इशारे पर प्रभुनाथ मिश्रा अदालत के कमरे से बाहर निकला. बरामदे में उसे दादागिरी-भरे शब्दों में यूं कहते सुना गया- "हम खींचेंगे फोटो। देखते हैं, कौन माई का लाल रोकता है?"

कुछ समय बाद, लम्बी गवाही के बाद जब बहलराम बीड़ी पीने के लिए कमरे से बाहर निकला तो ए.सी.एम. की जीप के समक्ष खड़े प्रभुनाथ मिश्रा एवं दूसरे व्यक्ति ने बारी-बारी से बहलराम पर दो-तीन बार फ्लेश चमकाया. इस पर साक्षी बहलराम ने उस समय कैमरा हाथ में लिए दूसरे व्यक्ति की बांह पकड़ी और उसे अदालत के भीतर लाकर उसकी ओर न्यायाधीश महोदय का ध्यान आकर्षित कराया. इस पर न्यायाधीश महोदय ने उनकी मनाही के बावजूद कैमरा चमकाने वाले व्यक्ति को डांट पिलाई।

सुबह के दौर में एक समय अदालत में बड़ी हास्यास्पद स्थिति निर्मित हुई. हत्या आरोपियों के लिए जन-साधारण से अलग लगाए बेंच पर बैठने की व्यवस्था की गई थी. प्रभुनाथ मिश्रा जन-साधारण के लिए नियत जगह से उठकर आरोपियों के साथ में जा बैठा. इस पर हैरानगी भरे अंदाज में न्यायाधीश महोदय ने पूछा- यह उचके वाला कौन है? एवं क्या यह भी आरोपियों में शामिल होना चाहता है? इस पर पूरी अदालत में हंसी का फौव्वारा छूट गया.

एक समय तो ज्ञान-प्रकाश मिश्रा एवं चन्द्रकान्त शाह ऊंची-ऊंची आवाजों में बोलने लगे एवं न्यायाधीश महोदय को उन्हें चुप कराना पड़ा था उसी समय प्रत्यक्षदर्शियों ने ज्ञान प्रकाश के मुंह से भद्दी सी गाली सुनी.

शाम ५.०० बजे के बाद अदालत कमरे के बाहर परिसर में मूलचन्द शाह एवं २-३ अन्य साथियों एवं छ.मु.मो. कार्यकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए यह कहते सुना गया कि इन्हें सबक सिखाने वालों को वह ५०-५० हजार रुपया ईनाम देगा

वे खुली अदालती कार्यवाही से बौखलाए हैं

मूल बात है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब से मुकदमें की कार्यवाही बन्द अदालत से खुली अदालत में शुरू हुई है, हत्यारे बौखलाए हुए हैं एवं येन-केन-प्रकरेण, उत्तेजना फैलाकर फिर से बन्द अदालत करना चाहते हैं. काली कोठरी में कालाधन के असर से अपनी काली करतूतों को ढकने की उनकी योजना खुली अदालत होने से धराशायी हो गई है.

इधर समस्त जन-मानस भी जागरूक हो चुका है एवं समझ रहा है कि न्याय-पालिका की आधार नीति के तहत जन-साधारण न केवल न्यायिक कार्यवाही के दर्शन का हकदार है बल्कि न्याय की गारन्टी भी अन्त: तो वस्तुत: जन-साधारण की उपस्थिति एवं भागीदारी में निहित है.

न्याय-हित का तकाजा है कि -

(१) मूलचंद, नवीन, चन्द्रकान्त, ज्ञान प्रकाश एवं अभय सिंह की जमानत रद्द की जाए.

(२) प्रभुनाथ मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए.

यदि शासन ने इन आदमखोरों की हरकतों पर रोक नहीं लगाई तो, छत्तीसगढ़ की जनता के धीरज का बांध टूट जायेगा. शासन के औचित्य पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा.

इनके मुंह में खून लग चुका है

मूलचंद-प्रभुनाथ गिरोह, घावला दंपत्ति हत्याकांड, बिंदा हत्याकांड, केडिया डिस्टलरी बम कांड आदि कारनामे जग जाहिर हैं. बहुचर्चित हवाला कांड के बी.आर. जैन के साथ मिलाई माफिया एसोसिएशन कि माफिया गतिविधियां हैं. अभी तक काला धन के प्रभाव से हमेशा बचकर निकल जाने के कारण इनके आदमखोर हौसले बढ़ चुके हैं. मगर अब समय आ चुका है कि, छत्तीसगढ़ में आदमखोरों को खुले विचरण करने की अनुमति छत्तीसगढ़ की जनता नहीं देगी.

तोर चाकू ला थाम दिही, हमर उघरा छाती।
तोर गुंडा फौज के चक्रव्यूह ला, चीर दीहि हमर लहू के धार।
तोर चाकू के धार ले तेज हवे, हमर लहू के धार।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से साथी जनकलाल ठाकुर द्वारा प्रकाशित, संपादन-अनूप सिंह

CHHATTISGARH NAYAYAGRAHA

DISCUSSION OF LEGAL ISSUES IS NOT TO REMAIN A MONOPOLY OF A SELECT FEW.

The working people claim their participation in the judicial process and proclaim that the judicial system derives legitmacy from the people, and not vica-versa.

छत्तीसगढ़ के मजदूर किसानों की आवाज ...

संगठन ही जनता की शक्ति का आधार है
- शहीद शंकर गुहा नियोगी

निजी वितरण हेतु | न्यायाग्रह विशेषांक | सहयोग राशि 2/- रुपये

जम्मो भिलाई आन्दोलन के मजदूर मन ल कार्य/वेतन देए म आनाकानी बन्द करो, जौन मन ल औद्योगिक न्यायालय द्वारा पुन: स्थापना के पात्र घोषित करे जा चुके हावे

All the workmen of Bhilai movement declared as 'deserving to be reinstated' by the award of Industrial Court must be given work / wages.

आधा पेट खाए के बीमारी म हमर मजदूर परिवार के मृत्यु के, न्यायिक-हत्या के सूची 120 से उपराहा हो चुके हावे।

The list of the victims of Judicial murders i.e. those who have died in semi-starvation conditions consists of more than 120 persons of workers families.

पुन: स्थापना के पात्र मजदूर मन ल 'जीवनयापन भत्ता' नई दिला सकय ले हाईकोर्ट ह का अइसन उम्मीद करही कि आधा पेट खवइया मजदूर अपन पेट ल अऊ काट कर के हाईकोर्ट के मुकदमे बाजी के भारी बोझा ल डोहारही ?

While not ensuring payment of subsistance allowance to the workmen 'deserving to be reinstated' does the Hight Court expect these semi starved workmen to make a further cut on their already meagre 'half-meals' to carry the burden of the logistics of litigation in the High Court ?

16.10.99 के फैसला ल लागू करे के अवधि 26 नवंबर 99 के दिन गुजर गीस, एखर बाद 26 दिसम्बर तक के एक महीना के अवधि के इंजीनियरिंग आधा पेट खाने वाले मजदूर के ब्याज की राशि 200 रु. प्रति महीना अउ डिस्टीलरी मजदूर के ब्याज के राशि लगभग 1600 रु. प्रति महीना धन आखरी वेतन ला इकारे के इजाजत कइसे करके देइसे ? अउ ये दे इकारे के पूता चलतेच हरे !

The date fixed for implementation of award dated 16.10.99 passed on 26 Nov. 99. How come the High Court has permitted these industrialists to stomach Rs.200 of each of the semi-starved workers of engineering industries and Rs. 1600 plus the last wages drawn from each of worker of distilleries for one month period, which concluded on 26th Dec. 99. And the same contiunes !

का हमर उच्च न्यायालय भिलाई के मजदूर ल जीवन चलाए बर भत्ता दिलाए के साधन बनही, जौन अधिकार एम.पी.आई. आर. अधिनियम के धारा 65 (3) म मजदूर मन ल देए गए हावे ? औद्योगिक न्यायालय के फैसला ल हाईकोर्ट म चुनौती देए के विचाराधीन मामला के दौरान मजदूर मन ल ओखर आखिरी वेतन के बराबर भुगतान करे बर जरूरी हरे।

Will our High Court become an instrument to ensure payment of subsistance allowance to Bhilai workers. which in a right conferred on them by M.P.I.R. Act,Section 65 (3) ? Workmen have to be paid 'the wages last drawn' by them during the pendency of proceedings involving challange to the award of Industrial Court in the High Court.

या

OR

ये दे न्यायालय ह भिलाई उद्योगपति के अइसन औजार बनही, जेखर से मुकदमेबाजी की व्यवहारिकता के भारी बोझा ल मजदूर के मूड़ म टिका के ओखर अप्रत्यक्ष ब्लैकमेल न्यायिक प्रक्रिया द्वारा करे जा सकय ?

Will it become an instrument of Bhilai industrialists such that, the logistics of litigation for poor workmen is a burden that Bhilai Industrialists try and use by a covert blackmail of judicial process?

ऐ दे न्याय व्यवस्था के अग्नि परीक्षा हरे

OUR JUDICIAL SYSTEM IS AT TRIAL, HERE !

Decision of Chhattisgarh Nyayagrah is being written ! the pen is that of the judge, but ink is the blood of the workers.

When influence of Bhilai Industrialist' black money over the judge was discovered- CMM gave a call for yet another"Rail-Roko". We reminded Congress-big-wigs Digvijay Singh, Shyamacharan Shukla, Ajit Jogi, Motilal Vora etc. of their utterances after brutal police firing at Bhilai on 1st Jule92 that.

"during B.J.P.s patwa regime workers of Chhattisgarh died of bullets but during Digvijays rule over 120 persons including innocent children Mayank Lanjewar & Deepak Sahu have fallen victim to judicial murders".

छत्तीसगढ़ न्यायाग्रह के फैसला हा लिखावत हे कलम न्यायधीश के, स्याही हावे मजदूर के लहू

1 जुलाई गोलीकाण्ड जांच आयोग का निष्कर्ष

"उद्योगपतियों का कृत्य अवैध, अनैतिक, अपराधिक"

"संभवतः उद्योगपतियों को ऐसी आशंका नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के सीधे सादे लोग भी इस सीमा तक संगठित हो सकते हैं कि स्वयं उद्योगपतियों के मनमानीपूर्ण कार्यों का विरोध करने के लिए खड़े हो सकते हैं।"

औद्योगिक न्यायालय रायपुर के जज श्री पेंडसे ने 31.7.99 के आदेश में गंभीर तथ्यात्मक भूल को आधार बनाकर 4200 श्रमिकों के परिवारों का निवाला छीना। यूनियन द्वारा भूल-सुधार हेतु आवेदन पर त्वरित कार्यवाही नहीं कर बहुमूल्य समय बिताया जा रहा है। -

अब ऐसे जज के हाथों में हजारों हजार श्रमिक परिवारों के जीवन एवम् न्याय को सुरक्षित कैसे समझ सकते हैं ?

जनता को मारोगे बन्दूक से ये बात भूल जाओ
मजदूर को मारोगे कोर्ट से ये बात भूल जाओ

जब छत्तीसगढ़ के सीधे सादे मजदूरों ने उद्योगपतियों की मनमानी के विरोध में आन्दोलन किया तो सुन्दरलाल पटवा ने सैकड़ों निहत्थे महिला पुरुषों को गोलियों से घायल किया, 17 साथी शहीद हुए।

कांग्रेसी नेताओं ने सहानुभूति के आंसू बहाए-

श्यामाचरण शुक्ल

"उन्होंने गोली चालन को पूरी तरह अमानवीय और नादिरशाही वाला कृत्य बताया। भिलाई की घटना पर श्री शुक्ल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने सभी प्रजातांत्रिक मूल्यों को बेमतलब साबित कर शांतिपूर्ण श्रमिक आन्दोलन को किसी भी तरह कुचलने का प्रयास किया।..." *(नई दुनिया, 3 जुलाई 1992)*

दिग्विजय सिंह

"मोर्चा के श्रमिक 25 मई से अपने नेता स्व. शंकरगुहा नियोगी के हत्यारों को गिरफ्तार करने व छत्तीसगढ़ के उद्योगों में श्रम कानून लागू करने की मांग लेकर आन्दोलनरत हैं, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया है।

(नई दुनिया, 3 जुलाई 1992)

मोतीलाल वोरा

"यदि सरकार ने समय रहते इस समस्या को सुलझाने में रुचि दिखाई होती तो घटना की नौबत नहीं आती।"

(नई दुनिया, 10 जुलाई 1992)

अरविन्द नेताम

"राज्य शासन की टाल-मटोल की नीति के कारण ही प्रशासन को मजदूरों पर गोली चलानी पड़ी। प्रदेश के उद्योगमंत्री कैलाश जोशी ने लगभग एक माह पूर्व श्रमिकों को उनकी मांगों के बारे में आश्वासन दिया था जिसकी वजह से श्रमिकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन आश्वासन के एक माह बाद भी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया।"

(नई दुनिया, 10 जुलाई 1992)

अजीत जोगी

"कांग्रेस (इं) के राज्य सभा सदस्य श्री अजीत जोगी ने कहा कि इस घटना ने भाजपा शासन की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को रेखांकित किया है।"

(नई दुनिया, 3 जुलाई 1992)

विद्याचरण शुक्ल

"श्री शुक्ल ने प्रदेश सरकार पर छत्तीसगढ़ के श्रमिक आन्दोलन को कुचलने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ वार्ता की पहल की जाती तो इस घटना को टाला जा सकता था।"

(भास्कर 5 जुलाई 1992)

पटवा के राज में छत्तीसगढ़ के मजदूर गोलियों से मरे थे,

दिग्विजय के राज में मासूम बालक मयंक लांजेवार, दीपक साहू सहित मजदूर परिवार के 120 लोग न्यायिक हत्या के शिकार हो चुके हैं।

शहीद मन के रद्दा मा चलत हन .... यमराज के पाछू मा सावित्री अस पड़े हन ...

सत्यवान की देह मा परान फूंके ल पड़ही.. छत्तीसगढ़ के मजदूर ल न्याय देए बर पड़ही

आन्दोलनकारी मजदूर ल न्याय नई मिलहीं तो
20 सितम्बर के अन्दर रेल के चक्का जाम होही

न्यायिक प्रक्रिया में राजनैतिक हस्तक्षेप

म.प्र. हाईकोर्ट की फुलबेंच के आदेश के अनुसार काम से निकाले 15 कंपनियों के 4200 श्रमिकों के 15 प्रकरणों पर औद्योगिक न्यायालय को 10 सितम्बर तक फैसला सुनाना था। 27 अगस्त तक 10 प्रकरणों में बहस पूरी हो चुकी थी एवं मामले आदेश हेतु सुरक्षित हो गए। शेष 5 प्रकरणों के लिए 1 सितंबर तक की तिथियां तय हो चुकी थी एवम् प्रतीत हो रहा था कि 10 सितंबर के पूर्व मजदूरों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में राजनैतिक हस्तक्षेप हुई है एवम् भिलाई के उद्योगपतियों के धनबल ने प्रभाव दिखाया और मजदूरों को न्याय से वंचित कर दिया गया।

10 सितंबर, रायपुर प्रदर्शन सीधी कार्यवाही की चेतावनी

न्यायिक प्रक्रिया में राजनैतिक हस्तक्षेप एवं उद्योगपतियों के कुप्रभाव के खिलाफ एवं मजदूरों के न्याय दिलाये की मांग के साथ हजारों मजदूरों ने रायपुर में प्रदर्शन किया। समस्त जन मोतीबाग में एकत्रित होकर 2.00 बजे दोपहरजुलूस बंजारी चौक, कोतवाली, जयस्तंभ चौक, शास्त्री चौक होते हुए नगरघड़ी चौक पर आमसभा के रुप में परिवर्तित हुआ। आम सभा में साथी जनक लाल ठाकुर ने इन्दौर हाईकोर्ट की फुलबेंच के आदेश के अनुरुप 10 सितम्बर तक मजदूरों का फैसला देने में टाल मटोल की निन्दा करते हुए ऐलान किया कि यदि मजदूरों को न्याय नहीं मिला तो 20 सितम्बर के अन्दर छत्तीसगढ़ में रेल का चक्का जाम होगा। सभा को साथी शेख अंसार, अनूपसिंह, मेघदास वैष्णव, बिसेलाल निषाद, बहन सुधा बाई, चन्द्रकला बाई ने छत्तीसगढ़ राज्य अखंड धरना के श्री उदयभान टाकुर ने भी संबोधित किया। जनकवि साथी कलादास डेहरिया ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किए एवं सभा का संचालन साथी मानिक लाल साहू ने किया।

12 सितंबर शहीद दिवस, संकल्प दिवस राजनांदगांव कार्यक्रम में भी रेल रोको आन्दोलन की चेतावनी दोहराई गई। आन्दोलन की सूचना मुख्यमंत्री एवं तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित की जा चुकी है।

न्यायिक प्रक्रिया को कुप्रभावित करने की प्रवृत्ति

कुख्यात हवाला कांड में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा ने एवं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर में भिलाई औद्योगिक विवाद प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिनांक 3 सितंबर 1996 को जस्टिस दीपक वर्मा ने भरी अदालत में भिलाई के उद्योगपतियों द्वारा धन शक्ति से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों को उल्लेखित किया था।

संघर्ष के लिये निर्माण

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

नये भारत के लिये

निर्माण के लिये संघर्ष

मुख्य कार्यालय :
दल्लीराजहरा, जिला-दुर्ग (म.प्र.)
फोन : 07748 - 83719, 54230

शाखा :
लेबर केम्प जामुल, भिलाई : फोन : 0788-383101
शहीद नगर, बीरगांव, रायपुर फोन : 0771-326388

नया छत्तीसगढ़

पत्र क्रमांक ---------------

दिनांक --------------

Nine-Year-Long Nyayagraha, the Struggle for Right to Life & Livelihood of the Bhilai Workers Movement leads to a Historic Victory.

Hundreds of villages shall participate in the Shaheed Jyoti Yatra for immersion of Shaheed Comrade Niyogi's ashes.

The toiling people of Chattisgarh renew their ~~role~~ resolve to "follow the path of the martyrs" and build "A New Chattisgarh for A New India"

On 16th October 1999, the Industrial Court, Raipur delivered its verdict regarding the victimisation and illegal dismissal of 3200 workers of 15 companies in the Bhilai Industrial belt, who had had the gates shut on them for forming "red-green" trade unions of the Chattisgarh Mukti Morcha nine years ago.

Reinstatement with 66% of back wages is ordered For 1539 of these workers belonging to the Kedia Group of Distilleries. For almost all other workers the Industrial Court's finding is that :

a) the workers were employees of their respective companies and the "contract labour system" in these companies was indeed a bogus one;

b) that these workers were illegally and wrongfully dismissed; and

c) that these workers deserved to be re-instated with their back wages,

Of course, after these bold conclusions the Court has felt "compelled" by a remarkable distortion and concoction of facts and law (or is it something else ?) to award lump sum compensation to each of the workers in place of what was, according to the Court, due to them in the eyes of the law.

While the facts of the case, the law of the land and the Industrial Court's own conclusions logically lead only to re-instatement with back wages for all the workers - a demand for which the Chattisgarh Mukti Morcha shall continue to fight; nevertheless in today's times when puppet governments are mounting severe attacks on worker's rights to make way for their master MNC's, this tide-turning victory of the Bhilai workers in effectively abolishing the illegal contract system in the industrial belt, establishing trade union rights and punishing the hitherto noveau riche kingpins — the Hawala Jains, Shahs of Simplex, and liqour-baron Kedias - is a tremendous one and has reverberated through Chattisgarh.

With the Slogan " We have won, and we shall win" on the 29th & 30th of October, thousands gathered to watch the re-instated workers submit their joining reports at the Chattisgarh Distillery at Kumhari and Kedia Distillery at Bhilai.

Those of our friends who have been associated these past years with the movement in Bhilai are well aware that this victory is not that of a "stroke of a pen" but has been wrested by a grim life-and-death struggle- by the sacrifice, steadfast courage, and commitment to a vision of the toiling people of Chattisgarh.

In these nine long years of semi-starvation, scores of workers were attacked by goondas of the industrialists some fatally; hundreds of workers were time and again lathi-charged and jailed,

Com. Niyogi was brutally murdered and seventeen of our comrades were shot in police firing in Bhilai. False criminal cases of murder were instituted against 23 activists of CMM including its leaders Janak Lal Thakur, Anoop Singh, Sheikh Ansar and Meghdas Vaishnav.

We remember with pride our week-long 'Economic Blockade' of the Hawala Jains, our industrial strike against explosions and firings at the Kedia factories, our struggles for justice which led to the conviction of murderers Moolchand Shah and Chandrakant Shah by the Sessions Court and our fearless second Rail Roko agitation at Kumhari.

With workers leadership of the peasantry on all fronts - be it against land grabbing and pollution by the industry, police repression and false cases, corruption of forest, bank or revenue officials, or the demand for irrigation facilities; and with their all round intervention in the industrial belt - whether to get hundreds of families ration cards, stop bull-dozing of bastees or by their 'Ekta-Bhaichara' rallies during and in fact just before the Babri Masjid demolition leading to freedom from communal tension - the workers of Bhilai have become the much-loved freedom fighters of the whole of Chattisgarh.

It is the material support of the mine workers of Dalli-Rajhara, the sympathy of lakhs of Chattisgarhi people, the solidarity of struggling, organisations all over the country and the support of our friends among the patriotic intellectuals over the past decade, that has led to today's victory. We owe you all our heart-felt thanks.

In the wake of this momentous victory, hundreds of Mukhiyas of Chattisgarh Mukti Morcha, who are its decision-making authority, have taken a solemn decision to immerse the ashes of Com. Niyogi (which had been kept at Dalli-Rajhara since 1991 awaiting justice for the Bhilai workers) at Shivrinarayan in the confluence of the Mahanadi, Sheonath and Arpa rivers which water Chattisgarh. People of hundreds of villages in Chattisgarh have urged that the Yatra for immersion pass through their villages so that they may collectively take a solemn vow to 'Follow the path of the Martyrs' and to struggle on to build 'A New Chattisgarh For a New India':.

Today, the challenges before the people of Chattisgarh to create a Chattisgarh free from un-employment, free from the repression and corruption of those in power, and free from deprivation of basic social wants is a tremendous one. And that in an era when the reduction of import duties has led to losses and fears of the sale of the major industry - Bhilai Steel Plant. When hundreds of ancilliaries and auxillaries have closed down, when so-called joint ventures are grabbing land and exploiting water and mineral resources, where investment in irrigation is pathetic leading to perennial drought and migration, and when irrational and uneconomic levels of 'mechanisation' are leading literally to the cutting of productive hands. On this occasion, the 22 year old Chattisgarh Mukti Morcha renews its resolve to build a democratic Chattisgarh through fierce struggle and rational alternatives against the rule of international monopoly capital codified in TRIMS & TRIPS of WTO whose ugliest face is apparent in the form of fascist regimes in third world countries.

Three-week long
Shaheed Jyoti Yatra begins at Dalli-Rajhara on 19th December, the Martyr's Day of Shaheed Vir Narayan Singh.

We invite you to participate with us in the solemn event of immersion of Com. Niyogi's ashes and renewal of our resolve.

With revolutionary greetings,

Yours in solidarity,

[signature]

(Anoop Singh)
Secretary

शहीद मन के लहू [illegible] नई होए, न कभू होई

जऊन भुईयां म [illegible] मन के लहू गिरे है,

ओ माटी हमा[illegible]गे है

छत्तीसगढ़ मोर भुईयां चन्दन जइसे महान ....

लुटेरों की जागीर नहीं-छत्तीसगढ़ हमारा है।

हम बनाबो नवां पहिचान-राज करहीं मजदूर-किसान ।।

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का संयुक्त आव्हान -

3 जून शहीद-दिवस प्रदर्शन रायपुर चलो ।।

दल्ली राजहरा के अमर शहीदों जुग-जुग जीयो - शहीदों का रास्ता अमल करो।

★ **कुर्सी का खेल खेलने वाले राजनेताओं - विदेशी कठपुतली बनकर देश के लोकतन्त्र प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता का मखौल मत उड़ाओ !**

★ **समस्त नई पीढ़ी के रोजगार-स्थान छीनना बंद करो !**

★ **द्वितीय श्रम आयोग की सिफारिशें "दूध की रखवार बिलई" रद्द करो !**

★ **जनता के बीज, पानी, जंगल, कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र ल बेच कर दलाली कमाना बन्द करो !**

★ **गोदामों में सारा है - वह अनाज हमारा है !**

★ **सरकारी खजाने का पूरा-पूरा हिसाब दो !**
उद्योगपतियों के 84 हजार करोड़ रूपये बैंक लोन डिंफाल्ट !
और 1 लाख 52 हजार 600 करोड़ रूपये टेक्स डिफाल्ट वसूल करो !

★ **31 जुलाई 2002 की लोकसभा घोषणा के अनुसार किसान मन के कर्जा माफ करो!**

★ **किसानों के धान की बकाया राशि और फसल बीमा राशि भुगतान करो !**

★ **गांव-गांव में सही में राहत कार्य शुरू करो, कोरी घोषणा बंद करो !**

★ **जनता के निस्तार बर पानी की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करों !**

★ **भिलाई आंदोलन के श्रमिकों को हाईकोर्ट की डबल बेंच के अनुरूप 6 महिने में न्याय का निराकरण करो!**

★ **वन भूमि और राजस्व भूमि में वर्षों से काबिज गरीब परिवारों को पट्टा दो !**

★ **छत्तीसगढ़ में पुलिसिया दमन का राज बन्द करो !**

★ **छत्तीसगढ़ से सी.आर.पी.एफ. की तैनाती तत्काल हटाओ !**

केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार अऊ

छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी सरकार की क्या पहचान...

विदेशी राज और पूंजीपति के आगे दुम हिलाना और

छत्तीसगढ़ की सवा दू करोड़ गरीब, भोलीभाली जनता के ऊपर बघवा असन गुर्राना।

साम्प्रदायिक भाजपा अऊ गैर साम्प्रदायिक कांग्रेस म कोई गुणात्मक फरक नई हे

एखरे सेती हमन कहिथन - आगे कुँआ पीछे खाई; कांग्रेस भाजपा भाई-भाई

★ अम्बिकापुर में हजारों गरीब बीड़ी पत्ता मजदूरो को 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जुलूस निकालने से क्यों रोका गया ? क्यों उनके नेतृत्वकर्त्ता कार्यकर्त्ताओं पर जिनमें भाकपा के एडवोकेट डी.पी. यादव, एडवोकेट अमरनाथ पांडे, एडवोकेट अरविन्द मेहता, पत्रकार राकेश सिंह शामिल है, उन पर राष्ट्रद्रोह का फर्जी मुकदमा क्यों बनाया गया है ?

★ आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारीगण बीड़ी पत्ता मजदूर संघ के इस आरोप का संतुष्टिपूर्वक जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं कि - बीड़ी-पत्ता घोटाले के तहत सिर्फ अम्बिकापुर जिला से ही प्रति सीजन 45 करोड़ रूपया अजीत जोगी को प्रेषित किया जाता है।

★ कुर्सी की राजनीति में छत्तीसगढ़िया, पिछड़ा वर्ग आदि की दुहाई देने वाले अजित जोगी ने अम्बिकापुर के पूर्व कलेक्टर विवेक देवांगन पर अविश्वास कर ट्रांसफर करके अपने विश्वासपात्र कलेक्टर राजू एवं एस.पी. बाबू को पदस्थ कर क्या छत्तीसगढ़िया और पिछड़ा वर्ग के प्रति अपनी असली भावनाओं को प्रदर्शित नहीं किया है ?

★ अदालत द्वारा जब्त धान को चोरी कर मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर में पहुंचाते हुए गुरूर थाना के टी.आई. राजू शर्मा को क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किसान यूनियन की महिलाओं ने रंगे हाथों पकड़ कर धान को पंचायत भवन, ग्राम-बासीन में खाली करवाया, बदले की कार्यवाही करते हुए आन्दोलनकारी महिलाओं सहित 83 किसानों पर ही आई.पी.सी. की धारा 395 डकैती का फर्जी मुकदमा बना दिया गया।

★ मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बार-बार यह बयान जारी किया कि नगरनार में 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय युवकों में से आज तक मात्र 98 युवकों को रोजगार दिया गया है। झूठे वायदे का भी एक आकार होना चाहिए। यहां तो कोई सीमा ही नहीं है - नगरनार, जगदलपुर क्षेत्र के हजारों बेरोजगार नवजवान स्पष्टीकरण चाहते हैं - कहां गए हमारे शेष - 39 हजार 902 रोजगार।

★ नगरनार क्षेत्र की दर्जनों आदिवासी महिलाओं पर 307, 395 आई.पी.सी. के फर्जी मुकदमे, छी.छी.छी., थू.थू.थू...

★ 3043 करोड़ रूपए के डिफाल्टर जिन्दल उद्योग के साथ अजीत जोगी की नजदीकी एवं भिलाई इस्पात संयंत्र यानि देश की संपत्ति के साथ गद्दारी कर जिन्दल को लाभ पहुंचाने वाले विक्रांत गुजराल आदि को पुरस्कृत करना भिलाई इस्पात संयंत्र के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत तो नहीं ?

★ बी.एन.सी. मिल राजनांदगांव को चालू रखकर हजारों रोजगार बचाने की जिम्मेदारी से राज्य सरकार मुंह क्यों चुरा रही है। सी.सी.आई. के अकलतरा अऊ मांढ़र कारखाना शुरू कराये के बारे में का करत हे ?

★ दल्ली-राजहरा, रावघाट लोहा खदानों में नियोगी जी द्वारा विकसित अर्ध मशीनीकरण की नीति से हजारों नौजवानों को रोजगार की मांग के बारे में राज्य सरकार की चुप्पी क्यों ?

3 जून दल्लीराजहरा अऊ छत्तीसगढ़ के
तमाम शहीद मन के लहू ये सवाल के जवाब खोजत हे ....

कब तक मजदूर किसान की छाती से लहू चूहत रही ?

छत्तीसगढ़ के गरीब मेहनतकश जनता जब-जब अपन लोकतान्त्रिक आकांक्षा बर आवाज उठाईन हे, सत्ताधारी वर्ग हमेशा पुलिसिया लाठी-गोली के द्वारा ओखर आवाज ल दबाए के प्रयास करीन हे .

★ छत्तीसगढ़ माईन्स श्रमिक संघ के गठन के तीन महीना बाद ही 2-3 जून 1977 के दल्लीराजहरा के लोहा खदान मजदूर साथी ऊपर गोलीचालन करीन, जेमा 11 मजदूर साथी शहीद होईन जेमा महिला शहीद अनुसूईया बाई अऊ बालक शहीद सुदामा हावे .

★ अंधाधुंध मशीनीकरण अऊ छटनी लागू करे बर 5 अप्रैल 1978 के बैलाडिला के मजदूर साथी मन के ऊपर बर्बर गोलीचालन जेमा महिला शहीद फगनी बाई सहित 10 साथी सहीद होइन। उहां संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक) के करीब 100 संगवारी मन ल लम्बा अवधि तक जेल म धांधे रिहीस .

★ दल्ली-राजहरा अऊ बैलाडिला के शहीद मन के कुर्बानी ले प्रेरणा ले कर दल्ली-राजहरा के मजदूर अंधाधुंध मशीनीकरण के खिलाफ अर्धमशीनीकरण के ऐतिहासिक आन्दोलन ल सफल करीन .

★ सी.आई.एस.एफ. के जवान मन द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी के विरोध में दल्लीराजहरा के आन्दोलन 1981 म साथी आशाराम शहीद होइस .

★ 12 सितम्बर 1984 के राजनांदगांव कपड़ा मजदूर संघ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आन्दोलन ल दबाए बर गोलीचालन म 4 साथी शहीद होइन जेमा बालक शहीद राधे घलो रिहीस .

★ आदिवासी मन के हजारों एकड़ जमीन साहूकार मन के द्वारा हड़पे जाए के विरूद्ध भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के आन्दोलन ल कुचले बर 17 सितम्बर 1989 के चीतालता, लुंड्रा (सरगुजा) पुलिसिया गोली म निहत्थे आदिवासी भाई-बहन कंवल साय अऊ पिछड़ी बाई शहीद होईन.

★ क्रान्तिकारी श्रमिक नेता का. शंकर गुहा नियोगी, उद्योगपति के गोली के निशाना बन के 28 सितम्बर 1991 को शहीद हुए .

★ आदिवासी महिला के संग पुलिस थाना म बलात्कार के विरूद्ध आन्दोलन करैया भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के किसान संगवारी मन ऊपर 26 मार्च 1992 के जशपुर जिला के टेंगूरजोर गांव गोलीचालन म नौजवान कार्यकर्त्ता रामनाथ नागवंशी शहीद होईस.

★ 30 मई 1992 के अभनपुर गोलीकांड में साथी रमेश परेरा शहीद होईस

★ 1 जुलाई 1992-भिलाई, उरला, कुम्हारी, टेडेसरा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर मन के रेल रोको सत्याग्रह के ऊपर बर्बर गोलीचालन, 17 साथी शहीद होइन। सैकड़ों ल जेल म धांधिस, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के प्रमुख साथी मन के ऊपर धारा 302 आई.पी.सी. के तहत फर्जी मुकदमा लगाईन.

★ धौराभाठा (बिलासपुर) गोलीचालन में साथी धनू राम वर्मा शहीद होगे

★ रायगढ़ के केलो नदी के पानी ल बचाये बर जिंदल के शोषण के खिलाफ भुख हड़ताल में बैठी बहन सत्यभामा 26 जनवरी 1998 के पुलिस हिरासत म शहीद होगे

★ बस्तर के आदिवासी जनता ला पिए के पानी के व्यवस्था सरकार नई करत हे, डाक्टर नई भेजत हे, फेर सी.आर.पी.एफ. के बंदूकधारी फौजमन ल भेजत हे.

कब तक .....

.....जब तक छत्तीसगढ़ म मजदूर किसान के राज नई होही।

जहां सबला
पिए के पानी मिले,
किसान ल सिंचाई अऊ
अपन फसल के
सही कीमत मिलही।

जहां हर हाथ ल काम मिलही।
जहां गांव-गांव म
स्कूल अऊ अस्पताल हो ही,
जहां पूंजीपति के
शोषण अऊ लूट नई हो ही ,

अईसन छत्तीसगढ़ कब बनही ....

....जब छत्तीसगढ़ म मजदूर किसान के राज होही.

हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर अमरीका का विनाशकारी हमला

जब पूरा उद्योग डूबेगा तो क्या पूंजीपति और क्या मजदूर, क्या व्यापारी सभी डूबेंगे।

रूपये पर डालर का हमला

पेट्रोलियम उत्पाद (डीजल, पेट्रोल, गैस) के लिए पिछले वर्ष का आयात बिल 85 हजार करोड़ रूपये डालर के वास्तविक मूल्य (Purchasing Power Parity) 6 रूपये के हिंसाब से यह होना चाहिए था 6/48 X 85000 करोड़ = लगभग 10600 करोड़ रूपये। अर्थात देश को सालाना 74 हजार 9 सौ करोड़ की चपत । जरा सोचिये ! इस आधार पर आज पेट्रोल का प्रतिलिटर मूल्य 35 रूपये के जगह रूपये के वास्तविक मूल्य के आधार पर होना चाहिये 35/8 = 4 रूपये 35 पैसे। जरा सोचिये।

डब्लू.टी.ओ. का हमला

अमरिका ने अपने इस्पात उद्योग को बचाने 30% कस्टम टैक्स लगाया, आई.टी. को बचाने नया न्यू जर्सी कानून बनाया, कृषि की सब्सिडी कई गुना बढ़ाई, लेकिन अमरिका के लिए कानून अलग और भारत जैसे विकाससिल देशो के लिए कानून अलग। हमें बाहरी माल के लिए दरवाजे पूरी तरह खोलने के आदेश। गोदाम भरे होने के बावजूद विदेशी अनाज का कोटा खरीदना पड़ेगा के आदेश । इसलिए सत्ताधारियों द्वारा किसानो को उचित मूल्य देने से तरह-तरह के बहाने।

विश्व बैंक, ए.डी.बी. आदि से ऋण लेकर गुलामी की शर्तें

वैट, परिवहन निगम बंद करना, शिक्षाकर्मियों को कम वेतन, सम्पत्ति कर, पानी का निजीकरण आदि सब शर्तें कर्जे के किस्तो में लिखा जा चुका है। देश की जनता, अपने चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा अपने कानून बनायेगी, प्रभुसत्ता का यह सिद्धांत विदेशी साहूकारों के पास गिरवी।

★ अर्थव्यवस्था पर विदेशी हमले से विनाश की स्थिति उत्पन्न है यह तो सभी उद्योगपति और सत्ताधारी भी स्वीकार करते हैं।

★ जब पूरा उद्योग डूबेगा तो क्या पूंजीपति और क्या मजदूर, क्या व्यापारी सभी डूबेंगे। लेकिन अंग्रेजी राज के पूर्वाग्रह से ग्रसित उद्योपति वर्ग इतना अदूरदर्शी एवं वैचारिक दिवालिया है कि दूसरे श्रम आयोग मे मजदूरों के अधिकारों पर तलवार के दृष्य से ही जश्न मना रहा है।

★ इस अदूरदर्शी पूंजीपति वर्ग की वैचारिक स्थिति उस बलि के बकरे से बेहतर नहीं है जिसे बलि के पूर्व खिला-पिला कर मोटा किया जाता है तो बहुत खुश रहता है।

★ मजदूर पर तलवार चलेगी सोच कर खुशी में मगन हो जाने वाला यह पूंजीपति वर्ग भूल जाता है कि जब उद्योग की नाव डूबेगी तो वह भी कहां बचेगा।

★ अपने देश के स्वतंत्र और औद्योगिक विकास के लिए प्रयास करने की तो ये पूंजीपति सोच ही नहीं पाते हैं।

★ इस पूंजीपति वर्ग का ऐसा वैचारिक दिवालियापन (जो कि सत्ता में बैठा वर्ग है), विदेशियों के समक्ष हमारे आत्मसमर्पण का एक सबसे बड़ा कारण है।

विनीत		
	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी	रामनाथ सरफे (जगदलपुर), मनीष कुंजाम (दंतेवाड़ा), आर.डी.सी.पी. राव (बैलाडीला), नूतनेश्वर खोब्रागड़े (रायपुर), सी.एल. पटेल (दुर्ग), छबीलाल कौशिक (राजनांदगांव), नरेश अग्रवाल (बिलासपुर) माखनलाल रजक (कोरबा), चितरंजन बख्शी (सचिव राज्य समिति)
	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	गणेश राम चौधरी (अध्यक्ष सी.एम.एस.एस., दल्लीराजहरा), अनूप सिंह (महामंत्री प्रगतिशील सिमेंट श्रमिक संघ), शेख अंसार (महामंत्री प्रगतिशील इंजिनियरिंग श्रमिक संघ), मेघदास वैष्णव (उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ, फिरत राम बरेठ (सी.एम.एस.एस.), एस.के. पटेल (पिथौरा) पुरोबी वर्मा, सुधा भारद्वाज, लीला बाई (महिला मुक्ति मोर्चा), जनकलाल ठाकुर (अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा)

Second National Commission on Labour 1999-2002

The Second National Commission on labour was constituted by the Government of India vide its resolution (No.Z-20014/8/98-Coord dated 15 October 1999) with Mr. Ravinder Varma, a former Union Labour Minister of Labour, as its chairperson and two full time members.

The Second National Commission on Labour, which was specifically mandated to bring definitive suggestion on 'Rationalisation of Labour Laws' and suggest the possibility of introducing an 'Umbrella Legislation for Workers in the Unorganised Sector', had submitted its report on June 19,2002.

The digital collection on second National Commission include:

- The Report of the Second National Commission on Labour
- The Reports of the Study Groups Constituted by the Commission on various themes such as:
    - Women and child labour
    - Social security
    - Umbrella legislation on women and child labour
    - Review of laws
    - Skill development, training and workers' education
- An Index of other Material on the Commission

This index contains the details of other material on the Second National Commission, which is now in possession of *Archive of Indian Labour*. As digitizing all the documents and keeping it in the website is found unviable, it is decided to keep the index for getting the feedback of possible users of these documents, such as researchers, trade unionists, employers, governmental agencies, social activists and professionals. Your cooperation is solicited in this regard, to carefully examine the contents of these materials, which are described in the index and tick (✔) the checkboxes provided against the titles, in case you consider the material is relevant and to be included in the digital collection in its full form. The feedback will be analysed after about 6 months to decide on the additional material to be included in the digital collection.

संगठन ही जनता की शक्ति का आधार है
– शहीद शंकर गुहा नियोगी

छत्तीसगढ़ के मजदूर किसानों की आवाज
मितान

संघर्ष और निर्माण
नए भारत के लिए
नया छत्तीसगढ़
– शहीद शंकर गुहा नियोगी

निजी वितरण हेतु | 26 फरवरी से 14 मार्च 1999 तक | सहयोग राशि 1.00 रु.

"अकाल की स्थिति में अपने देश के किसानों को सबसिडी (राहत) देने बाबत भारत सरकार ने डब्ल्यू.टी.ओ. को आवेदन देकर अनुमति मांगी"

– आकाशवाणी समाचार 31 जनवरी 1999, दोपहर 2 बजे

इसका अर्थ है कि भारत में शासन डब्ल्यू.टी.ओ. उर्फ डंकल-कानून का है, भारत सरकार का नहीं !
जरा सोचिये ! किसने हमारे देश को डंकल-डालर का गुलाम बनाया ? (पढ़िये पृष्ठ 2 पर)

मजदूर के मांग अउ किसान मन ल अकाल राहत बर
13 दिन के ऐतिहासिक भूख हड़ताल 9 फरवरी ले 21 फरवरी तक ले सम्पन्न होइस
क्रमिक भूख हड़ताल के सिलसिला जारी हावय

13 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठने वाले बी.ई.सी. कम्पनी के साथी जीवधनसाहू, ए.सी.सी. कम्पनी के साथी पुनऊ राम यादव और बी.के. कम्पनी के साथी तातारात (सामने पंक्ति में बैठे हैं)

हमारी मांगें

(1) भारत सरकार डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. से नाता तोड़े। देश के उद्योगों की और कृषि की रक्षा करें।

(2) गैर-कानूनी ठेका प्रथा पर रोक लगाओ।

(3) ए.सी.सी. मैनेजमेंट 27-7-1990 का फैसला लागू करें, नियमित हाजिरी दें, मशीनीकरण पर रोक लगाए, पावर प्लांट द्वारा पर्यावरण बर्बादी पर रोक लगाए।

(4) बी.ई.सी. कंपनी, बी.आई. डब्ल्यू. कंपनी में मजदूरों की प्रताड़ना बन्द करो। वेतन पुनर्निर्धारण करों।

(5) बी.के. कम्पनी में मजदूरों को 20% बोनस का भुगतान करो।

(6) छोटे-बड़े सभी उद्योगों में हाजरी कार्ड, वेतन स्लिप, पी.एफ. आदि श्रम विधि प्रावधानों का पालन ।

(7) किसानों को अकाल राहत दो, कर्जा माफ करो।

भारतीय जनता का संयुक्त कार्यवाही मंच (जाफिप) का आव्हान :

"बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो" नारे के साथ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, आदिवासी मुक्ति संगठन, भोपाल गैस कांड पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित मध्यप्रदेश के जनसंगठनों का खूनी यूनियन कार्बाइड के समक्ष 12 मार्च को भोपाल में जबर्दस्त प्रदर्शन

डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ.
उद्योग एवं कृषि का विनाश, देश की गुलामी

14 अप्रैल 1994 को कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने डंकल-कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. की गुलामी स्वीकार कर ली थी।

4 वर्ष बाद 18 मई, 1998 को भाजपा की अटल बिहारी सरकार ने भी डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. को स्वीकृति सील लगा दी।

हमारी आर्थिक आजादी को छीन कर हमें डंकल-डालर का गुलाम बना दिया है।

डब्ल्यू.टी.ओ. उर्फ डंकल कानून के दो भाग हैं :-

(1) ट्रिम्स (ट्रेड रिलेटिड इन्वेस्टमेंट मेजर्स)

(2) ट्रिप्स (ट्रेड रिलेटिड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राईट्स।

ट्रिम्स

✸ डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. के ट्रिम्स (ट्रेड रिलेटिड इन्वेस्टमेंट मेजर्स) प्रावधानों के तहत भारत को इस्पात सहित 314 वस्तुओं से सीमा शुल्क समाप्त करना पड़ा है। जापान, दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस्पात को हमारे देश की मार्केट में लाद रही है। माल नहीं विकने के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र, टिस्को सहित पूरा भारतीय इस्पात उद्योग संकट में है।

✸ डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. ट्रिम्स के प्रावधानों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के सैकड़ों उद्योगों की आर्थिक स्थिति के पुर्ननिर्माण की जगह उन्हें मरने के लिए छोड़ देने की नीति बनी है। इसका घातक असर छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बी.एन.सी. मिल टेक्सटाइल मिल, एच.एस.सी.एल. एवं बी.आर.पी. पर भी पड़ेगा।

✸ आर्थिक सुधारों के नाम पर आर्थिक नरसंहार की इन नीतियों के कारण उरला, टेडेसरा, भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र के करोड़ों उद्योग बंद हो गये एवं अनेक बंद होने की हालत में।

✸ ट्रिम्स प्रावधानों के तहत भारत सरकार बीमा क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना एवम् बिजली बोर्ड के निजीकरण के लिए भी बाध्य है।

✸ डंकल कानून के ट्रिम्स प्रावधानों के तहत बिजली, सिंचाई, खातू, राशनआदि पर सबसीडी समाप्त करने के लिए ये हमारी सरकार बाध्य है।

✸ डंकल कानून के ट्रिम्स (ट्रेड रिलेटिड इन्वेस्टमेंट मेजर्स) प्रावधानों के तहत ही डालर रुपये की 100% कनर्वटिबिलीटी नीति की ओर कदम बढा रहा है। इसके कारण पिछले एक वर्ष में रुपये के मुकाबले डालर 35 रु. से बढकर 43 रु. हो गया। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा समस्त आयातित मशीनों और आस्ट्रेलियाई कोकिंग कोल का बिल एक झटके में 22% बढ गया। संयंत्र की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। जबकि वास्तव में क्रय क्षमता तुलनात्मकता के हिसाब से 1 डालर मात्र 2 या 3 रुपये के बराबर है।

ट्रिप्स

यानि (ट्रेड रिलेटिड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राईट्स)

- इसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां कृषि उत्पादन एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में अपना एकाधिकार कायम करने की योजना बना चुकी है।

- जिस प्रकार 19 वीं सदी में अंग्रेजों ने फारेस्ट एक्ट लागू कर वन सम्पदा पर अंग्रेजी शासन का एकाधिकार कायम किया था एवं उसे लागू करने के लिये विशेष वन कर्मियों का बल गठित किया था,

- जिस प्रकार सरकार ने शराब के उत्पादन एवं विक्री पर एकाधिकार कायम करने के लिये आबकारी एक्ट के तहत लाइसेंस प्रणाली लागू की थी और उसे प्रभावी करने के लिये विशेष आबकारी पुलिस बल गठित किया था,

- उसी प्रकार डब्ल्यू. टी.ओ. के ट्रिप्स प्रावधानों के तहत जो नया पेटेंट कानून किया जा रहा है उससे कृषि उत्पादन एवं बीजों के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार स्थापित करने का प्रावधान है।

- जिस प्रकार फारेस्ट एक्ट के बाद से किसान अपने खेत के पेड़ को काटने के लिये स्वतंत्र नहीं है एवं वन विभाग उसे मनमौजी तरीके से चोर घोषित करने का अधिकार प्राप्त किये हुए है,

- जिस प्रकार आबकारी एक्ट के बाद से आबकारी पुलिस किसी के भी घर में घुस कर उस पर जुर्म कायम करने की ताकत रखने लगी है।

उसी प्रकार नये पेटेंट कानून के तहत बहु राष्ट्रीय कंपनियां एवं उनके बल किसानों के बीज, गाय, बछरू आदि सम्पदा के मालिक बन बैठेगें।

✸ कृषि और दवा उद्योग, इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग के लिये घातक यह नया पेटेंट कानून भारत सरकार संसद में ला रही है। डंकल कानून के ट्रिप्स (ट्रेड रिलेटिड इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स) के प्रावधान के तहत विदेशी निर्देशों का गुलाम बनकर भारत सरकार वर्तमान प्रोसेस पेटेंट प्रणाली की जगह प्रोडक्ट पेटेन्ट का सर्वनाशी कानून को ला रही है।

निर्यात हेतु कृषि भूमि का 80% बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में आ चुका है। और अब मोनसेन्टो जैसी दो-चार बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाखो-करोड़ों किसानों का स्थान लेने की तैयारी कर रहे हैं।

डब्ल्यू.टी.ओ. के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी पूंजी (Monopoly Capital) का दबाव है कि :-

✸ इस्पात सहित 314 वस्तुओं से सीमा शुल्क समाप्त करना पडा है।

✸ अकाल की स्थिति में भी अपने देश के किसानों को सबसिडी (राहत) देने बाबत डब्ल्यू.टी.ओ. को आवेदन देकर अनुमति मांगनी पड़ रही है।

✸ फ्री-ट्रेड के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी पूंजी (Monopoly Capital) यह दबाव डाल रहा है कि जब वे सस्ता इस्पात और चांवल बेच रहे है तो भारत के इस्पात संयंत्रों को इस्पात और भारत के किसानों को धान उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस विषय में प्रस्तुत है अमर किरण दिनांक 8-2-99 अंक में प्रकाशित लेख के अंश

"मोनसेंटो : विश्व विजय की तैयारी"

"मोनसेंटो को विश्व विजय की रणनीति का दूसरा पक्ष है फसलों के बीजों पर पेटेंट लेकर एकाधिकार कायम करना। डब्ल्यू.टी.ओ. के पेटेंट ने 20 साल का पेटेंट माना है, इसका लाभ मोनसेंटों उठा रही है .....। टर्मिनेटर टेक्नोलाजी का पेटेंट उसके हाथ में है। अब इस तकनीक से ऐसे बीज बन रहे हैं जो केवल एक बार ही उगेंगे यानी किसान हर साल कंपनी से बीज लेने को मजबूर होगा।..... जो किसान राउंड अप रेडी सोयाबीन खरीदते है, उन्हें एक करारनामे पर दस्तखत करने होते है जिसकी शर्ते है -किसान को हर बोरे पर 5 डालर टेक्नोलाजी फीस देनी होगी। किसान मोनसेंटो को यह अधिकार देता है कि उसके खेतों का मोनसेंटो 3 साल तक मुआयना कर सके, उसे मानिटर कर सके तथा खेतों का परीक्षण कर सके। किसान केवल मोनसेंटो का हर्बीसाइड राउंडअप ही इस्तेमाल कर सकेगा। किसान को बीज बचाने और फिर से बोने का अधिकार छोड़ना पड़ेगा, किसान को वादा करना होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को बीज न तो बेच सकेगा और न ही दे सकेगा। किसान को लिखित रुप से यह मंजूर करना होगा कि अगर वह इस समझौते के किसी भाग का उल्लंघन करता है तो उसे मोनसेंटो को उस समय की राउंडअप रेडी जीन की लागू फीस का 100 गुना गुणित स्थानांतरित बीजों की ईकाई की संख्या के रूप में देना होगा। इसमें वकील की न्यायोचित फीस तथा खर्चे भी जोड़ने होंगे।"

चुनाव के पहले

लोकसभा चुनावों पहले 20 जनवरी 98 को भाजपा ने किसानों को अकाल राहत की मांग उठाकर भूख हड़ताल आन्दोलन का नाटक किया।

सवेरा संकेत 24 जनवरी 98

मुख्यमंत्री निवास के समक्ष सुन्दरलाल पटवा का अनशन जारी । श्री पटवा ने प्रधान मंत्री इन्द्रकुमार गुजराल को पत्र लिखकर किसानों को मुआवजे हेतु 2000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की

विधान सभा चुनावों के पूर्व 3 जुलाई 98 कांग्रेस ने किसानों को अकाल राहत की मांग उठाकर प्रदर्शन गिरफ्तारी आन्दोलन की नौटंकी की।

दैनिक हिन्दुस्तान 4-7-1998

मध्यप्रदेश के हजारों किसानों ने संसद भवन पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कर रहेथे। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्ण मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल, श्री मोतीलाल वोरा, श्री माधवराव सिंधिया, श्री विद्याचरण शुक्ल सहित मध्यप्रदेश सरकार के 45 मंत्री और अनेक विधायक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री दिग्विजय सिंह ने कहा हम देश के प्रधानमंत्री से यह पूछने आए है कि ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए प्रति एकड पांच हजार रुपये देने के उनके दल के चुनावी वायदे का क्या हुआ।

चुनाव के बाद

केन्द्र में अटल बिहारी बाजपेई की भाजपा सरकार ने यूरिया खातू, चांवल, गेहूं, शक्कर, रसोई गैस के मूल्यों में भारी वृद्धि की।

राज्य में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार ने खातू, बीज, कीटनाशक, कपड़ा, एल्यूमीनियम के बर्तन, माचिस, खाद्य तेल, मट्टी तेल पर टैक्स बढ़ाया। सिंचाई दर बढ़ाकर दोगुनी की गई।

बैंक कर्जा वसूली में भेदभाव

एक के बाद एक दूसरे वर्ष भी अकाल से प्रभावित छत्तीसगढ के किसानों को कर्जा वसूली के कुर्की के नोटिस आ रहे हैं।

दूसरी ओर 45 हजार करोड रुपये कर्जा दवाकर रखने वाले नवधनाढ्य उद्योग पति मस्ती कर रहे हैं।

हम मांग करते हैं चोरों को मजा, जनता को सजा की नीति का त्याग दिया जाए एवं किसानों की जमीन कुर्की पर रोक लगाकर राजनेता, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, मजदूर को एक समान दर्जा देकर वसूली नीति अपनाई जाए और लगातार दूसरे वर्ष से अकाल की स्थिति के मद्देनजर कर्जा माफ किया जाए दूसरी ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों का 45,000 करोड़ रुपया बकाया नवधनाढ्य उद्योगपतियों से वसूला जाए।

नवभारत – 1 फरवरी 99

एक निर्देश से विभिन्न बैंकों के बडे बकायादारों में खलबची मची हुई है, जिसके तहत 25 लाख रुपये से अधिक राशि के डिफाल्टरों के नाम सार्वजनिक करना है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 45,000 करोड रुपये की राशि इसी तरह डूबत खाते में पड़ी हुई है

बिजली दरों में भारी वृद्धि

मीटर लगाने का रेट 350 रुपये से बढ़कर एक झटके में 1175 रुपये हुआ

विद्युत वोर्ड को भारी घाटा बता कर दो माह पूर्व बिजली लगाने की खर्चा एक झटके में 350 रु. से बढाकर 1175 रु. कर दिया गया है।

भिलाई के नागरिकों की बिजली दरें कई गुना वढा दी गई है।

विद्युत वोर्ड को भारी घाटा बता कर भारी पैमाने पर कर्मचारियों इंजीनियरों की छंटनी करने एवं वहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए दरवाजा खोलने की तैयारी चल रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से बिजली की प्रतियूनिट दर दुगुनी या चौगुनी 5 रु. से 8 रु. तक हो जाएगी।

छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा चोरों का मजा जनता की सजा की इन नीतियों का विरोध करता है और मांग करता है कि विद्युत क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करने पर रोक लगे, विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के नाम पर कर्मचारियों की छटनी की योजना बंद हो और जन साधारण उपभोक्ताओं को उचित दर पर बिजली उपलब्ध करायी जाय।

मीटर लगाने का खर्च 1175 रुपये से घटाकर पूर्व की भांति 350 रुपये किया जाय।

देशबंधु 30 जनवरी 1999

प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं पर विद्युत मंडल का लगभग 14 अरब रुपये बकाया है। इस राशि में से लगभग 12 अरब रुपये की राशि उद्योग, सरकारी संस्थाओं, नगर निगमों और अन्य उपभोक्ताओं पर बकाया है,

दैनिक भास्कर 2 फरवरी, 1999

नवगठित मध्यप्रदेश विद्युत आयोग के प्रथम अध्यक्ष सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति शचीद्र द्विवेदी ने कहा.. वह यह महसूस करते है कि घरेलू बिजली उपभोक्ता तो ईमानदारी के साथ अपना बिजली बिल चुकाता है, लेकिम बडे-बडे कारखानों के संचालक बिजली चोरी करते हैं।

चोरों का मजा, जनता को सजा

डंकल-डालर के दलाल नवधनाढ्य वर्ग लाखों करोड रुपया देश से निकाल कर विदेशी वैंकों में जमा करते जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार आज की तारीख में यह राशि 160,000 करोड रुपये से अधिक है। कर्जा देने वाले देश डंकल-कानून के डंडे से चमकाकर कर्ज की किश्त पटाने के लिए जनता पर टैक्स और मूल्य वृद्धि का बोझा बढाने की नीति लागू करवा रहे है। चोरों का मजा जनता को सजा की इस नीति के कारण डंकल-कानून ने दुनिया के कई देशों को मैक्सिको, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, रूस, अर्जेन्टीना, आदि को बरवाद कर दिया है और अव हमारे देश को भी इसी रास्ते पर धकेल रहा है।

डंकल-कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद हमारी सरकारों को अकाल की स्थिति में किसानों को राहत (सवसिडी के लिए भी डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. से अनुमति मांगनी पड़ रही है।)

हम भाजपाई प्रधान मंत्री और कांग्रेसी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि लगातार दो वर्षों के अकाल पीडित किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड मुआवजा देकर अपना चुनावी वायदा पूरा करें। कर्जा, भरना, वसूली वन्द करों, सिंचाई, खातू, बिजली की दरों में वृद्धि बंद करों।

आर्थिक सुधार के नाम पर आर्थिक नर संहार
उरला औद्योगिक क्षेत्र के अनेक उद्योग बंद

बंद औद्योगिक इकाईयों की सूची

क्र.	कारखाना का नाम	नियोजक का नाम
1	आनंद रोलिंग मिल, सोनडोंगरी	ओ.पी. गोयनका
2.	भवानी स्टील रोलिंग मिल, उरला	विकास अग्रवाल
3.	भारत इस्पात उद्योग, रावांभाठा	जगदीश सिंह सैनी
4.	डागा रिरोलिंग मिल, भनपुरी	राजेन्द्र डागा
5.	हिन्दुस्तान स्टील रिरोलिंग मिल, गोंदवारा	युनिस भाई, फारूक भाई
6.	जायसवाल वायर इंडस्ट्रीज	ए.एल. अग्रवाल, आर.पी.
7.	जे.जे. रिरोलर रिंग नं. 2	गफ्फार भाई, मौलाना जी
8.	महाकौशल इंजीनियरिंग एवं कांट्रेक्टर्स उरला	पारस वैद्य, ललित जैन
9.	एम.पी. स्टील प्रोसेस, गोगांव	सलीम भाई
10.	नूरी रिरोलिंग मिल, उरला	एम.जावेद राजा
11.	नेशनल स्टील रिरोलर्स एंड फैब्रिकेटर्स, भनपुरी	असलम भाई
12.	रायका इस्पात उद्योग, गोंदवारा	संजय रायका, विजय रायका
13.	रायका इंजीनियरिंग, रिरोलिंग मिल, गोंदवारा	संजय रायका, विजय रायका
14.	संजय इस्पात उद्योग, रांवाभाठा	बी.एन. अग्रवाल, राजेश अग्रवाल
15.	श्री इस्पात, उरला	दशरथ प्रसाद लेथ
16.	श्री कृष्णा उद्योग, भनपुरी	बिहारी अग्रवाल
17.	निकेता कास्टिंग, उरला	राकेश गोयल, वी.के. सरेफ
18.	स्टेप इंटरप्राइजेस प्रा.लि. उरला	
19.	रायपुर एलायज लि., भनपुरी	कमल शारडा
20.	रायपुर फेरोएलायज	रामानंद अग्रवाल
21.	सिंघानिया स्टील लि., उरला	सुशील सिंघानिया
22.	रायपुर एलायड लि. टाटीबंद	एन.के. गोयनका
23.	रायपुर कास्टिंग प्रा. लि. , उरला	
24.	राजेन्द्रा स्टील लि. सिलतरा	–
25.	स्टैण्डर्ड फेरो एलायज, युनिट-1,2	कैलाश अग्रवाल
26.	मोनेट फेरो एलायज लि. उरला	संदीप
27.	श्री निवास फेरोएलायज, उरला	
28.	गिरजा स्मेल्टर्स फेरोएलायज लि., उरला	
29.	दीपक फेरो एलायज लि. , उरला	रंजीत राठौर
30.	रघुबीर फोरे एलायज लि., उरला	
31.	नवक्रोम फोरे एलायज लि. , उरला	
32.	जैन कार्बाइड लि., उरला	
33.	हीरा फेरो एलायज लि., उरला युनिट-1	
34.	हीरा फेरो एलायज युनिट -2, उरला	
35.	आलोक फेरो एलायज लि. उरला	
36.	विकास फेरो एलायज लि. उरला	
37.	लक्ष्मी एग्रीको प्रा. लि. उरला	महावीर अग्रवाल
38.	बी.के. हाइजिन लि., उरला	विजय गुप्ता, कुलदीप गुप्ता
39.	फरिस्ता रबर प्रा. लि. उरला	
40.	बी.ई.सी. अरपा प्रा. लि., उरला	बीनू जैन, बी.आर. जैन
41.	ओरियन्ट प्लाइवुड,उरला	
42.	भालोटिया प्लाईवुड लि., उरला	सी.पी. भालोटिया
43.	भालोटिया व्हिनियर्स,लि., उरला	,,
44.	गीता प्लायवुड लि., उरला	
45.	यू.पी. मेटल लि., उरला	
46.	स्वास्तिक वायर्स प्रा. लि. भनपुरी	
47.	मोहन इन्टरनेशनल जूट मिल प्रा.लि., उरला	

- ✱ जापान, दक्षिण कोरिया के इस्पात पर एंटी -डम्पिंग ड्यूटी लगाओ, बी.एस.पी. और पूरा इस्पात उद्योग बचाओ।
- ✱ डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. को भगाओ देश की कृषि और उद्योग को बचाओ।

– छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

उद्योगों पर संकट

19 फरवरी 1999 को सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग के कार्यालय में ए.डी.एम. दुर्ग श्री नरेश चन्द्र पाल की उपस्थिति में छ.मु.मो. संबंधित प्रगतिशील इंजी. श्रमिक संघ एवं प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ यूनियन एवं बी.के. कम्पनी, बी.ई. सी. कम्पनी एवं ए.सी.सी. कम्पनी जामुल मैनेजमेंट प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई।

चर्चा में यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि मजदूरों के हिस्से का बोनस, वेतन पुनर्निर्धारण और नियमित हाजरी नहीं देने से इन उद्योगों को डूबने से बचाया जा सकता है तो उद्योग हित में आज ही अपने हिस्से का त्याग करने को तैयार है।

यूनियन प्रतिनिधियों ने उद्योगों पर संकट के कारणों का विश्लेषण करते हुए बताया है कि –

(1) डब्ल्यू.टी.ओ. उर्फ डंकल कानून के डंडे तले इस्पात सहित 314 वस्तुओं से सीमा शुल्क हटा लिया गया। इससे इस्पात उद्योग भारी संकट में।

(2) डब्ल्यू.टी.ओ. के TRIMS (Trade Related Investment Measures) के तहत भारत सरकार द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों पर खर्चे पर अंकुश। सरकारी निर्माण कार्यों पर रोक से सीमेंट एवं इस्पात उद्योग में अभूतपूर्व मंदी।

(3) डब्ल्यू.टी.ओ. उर्फ डंकल कानून के TRIPS (Trade Related Intellectal Property Rights) के तहत हमारे देश के वर्तमान प्रक्रिया पेटेंट प्रणाली (Process Patent regime) को बदल कर उत्पाद पेटेंट प्रणाली (Product patent regime) लागू करने हेतु नया पेटेंट कानून लाया जा रहा है उससे दवा उद्योग के साथ-साथ इस्पात उद्योग और इंजी. उद्योग के सामने भी भारी संकट खड़ा हो जाएगा।

(4) TRIMS (Trade Reltated Investment Measery) के तहत डालर-रुपये की 100% कन्वर्टिबिलीटी से रुपये के अवमूल्यन से आयात पर खर्चे में वृद्धि। भविष्य में यह आत्मघाती हो सकता है - मैक्सिको , इंडोनेशिया, रुस एवं ब्राजील के उदाहरण सामने है। स्मरणीय है कि क्रय क्षमता तुलनात्मकता की दृष्टि से 1 डालर 2 या 3 रुपये के बराबर है (It is to be remembered that in terms of purchasing power parity 1 dollar is equal to 2 or 3 rupees.

(5) सरकारी वित्तीय संस्थानों (Government Financial Institutions) जैसे कि सार्वजनिक बैंकों, जीवन बीमा निगम, जी.आई.सी. यु. टी. आई., आई.डी.बी.आई, आई. सी. आई. सी. आई. का जो पूंजी भंडार भारत के औद्योगिक पूंजीपतियों के लिए उपलब्ध था, TRIMS प्रावधानों के तहत उसका अधिकाधिक भाग अन्तर्राष्ट्रीय सट्टेबाज पूंजीपति की ओर खींचता चला जा रहा है।

भारत के उद्योगपति अपनी आंखों के सामने बेबस हुए अपने उस औद्योगिक साम्राज्य को उजड़ते हुए देख रहे है जिसे इन्होंने इस शताब्दी के शुरुवात से निर्माण किया था।

इस प्रकार भारतीय उद्योगों पर संकट का कारण मजदूरों को दिया जाने वाला वेतन अंश नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी पूंजी (Monopoly Capital) का हमला है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियोगी जी हत्याकांड प्रकरण में छ.मु.मो. एवम् सी.बी.आई की अपीलें मंजूर

विगत 29 जनवरी 1999 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी.एन. कृपाल एवम् न्यायमूर्ति राजेन्द्र बाबू की बेंच ने नियोगी जी हत्याकाण्ड में म.प्र. हाई कोर्ट, जबलपुर द्वारा हत्यारों को बरी करने के खिलाफ छ.मु.मो. द्वारा दायर अपील एस.एल.पी. (क्रिमनल) 3625-29/98 को मंजूर कर लिया। इसी प्रकरण में सी.बी.आई. द्वारा दायर अपील एस.एल.पी. (क्रिमनल) 2001, 2542, 3544-46/98 तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा दायर अपील एस.एल.पी. (क्रिमनल) 4138-43/98 को भी मंजूर कर लिया गया है।

उद्योगपतियों के वकील राजेन्द्र सिंह ने अभियुक्त नवीन शाह को बचाने का बहुत प्रयास किया। छ.मु.मो. द्वारा दायर याचिका पर भी भारी विरोध किया। लेकिन माननीय न्यायाधीशो ने सभी दायर अपीलों को बहस के लिए स्वीकार करने का निर्णय सुनाया।

सावधान !

ज्ञातव्य है कि नियोगी जी हत्याकाण्ड मामले में ऊपर उल्लेखित अपीलों के अलावा और कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई है। भीमराव बागडे द्वारा इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का दावा सर्वथा झूठा है एवं इस उद्देश्य हेतु जन साधारण से धन एकत्रित करना धोखा धडी पूर्ण कृत्य है। ऐसे धोखे बाजों से बचें।

श्रमिक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

छ.मु.मो. के आवेदन पर 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4200 श्रमिकों के मामले में म.प्र. हाई कोर्ट को निर्देशित किया हैकि इस प्रकरण में फुल बेंच का गठन कर मामले का निराकरण शीघ्र किया जाए।

छ.मु.मो. के आवेदन पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति नानावती एवं न्यायमूर्ति कुर्दुकर की बेंच ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना समय बीत जाने पर भी बेंच का गठन तक नहीं किया गया है, जबकि हजारों श्रमिकों की जीविका का प्रश्न इस प्रकरण से जुडा हुआ है।

ज्ञातव्य है कि करीब 7 माह पूर्व मध्यप्रदेश हाई कोर्ट इन्दौर के जस्टिल बी.ए. खान ने इस प्रकरण में फुल बेंच गठित करने का आदेश दिया था लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक यह बेंच गठित नहीं हुआ है।

बैंक, बीमा, बिजली, बी.एस.पी., बी.आर.पी., एच.एस.सी.एल, कर्मचारियों को आव्हान

तमाम राष्ट्रीय पार्टियां ने अपने ट्रेड यूनियन विभागों इन्टुक, एटक, सीटू, एच.एम.एस., बी.एम.एस. को दुमछल्ला बनाए हुए है।कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, सी.पी.एम. के मुख्यमंत्री ज्योतिबसु, सभी के सभी विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के नाम पर डंकल डालर के प्रावधानो को लागू करने जा रहे है। चूंकि ये राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें राष्ट्रीय पार्टियों की बंधुआ मजदूर बनी हुई है इसी कारण सरकार इन ट्रेड यूनियनों के द्वारा निजीकरण, सी.पी.एफ आदि के मुद्दों पर प्रदर्शन राष्ट्र व्यापी प्रदर्शनों, कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लेती है और एक के बाद एक मजदूर विरोधी कदम धड़ल्ले से उठाए जा रही है।

छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक राज्य रैयत संघ, ए.आई.पी. आर.एफ आदिवासी मुक्ति संगठन आदि लाठी गोली जेल, हर दमन का मुकाबला कर आगे बढने वाले देश के ऐसे 55 संगठनों ने सर्वनाशी डंकल कानून को उखाड फेंकने की लडाई को आगे बढाए हुए है।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बैंक, बीमा, बिजली, बी.एम.पी., कर्मचारियों के संघर्षो को समर्थन देते हुए आव्हान करता है -

टुकडे -टुकडे में आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा। हमारे उद्योग एवं कृषि का सर्वनाश करने वाले डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. को खदेड़ने के लिए एक जुट संघर्ष करना होगा।

रायगढ में 21 फरवरी को जबरदस्त रैली

रायगढ नवधनाढ्य उद्योगपति जिन्दल द्वारा जल-संपदा के निर्मम दोहन से पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो चुका है। रायगढ की जनता लम्वे अरसे से पीने के पानी एवं जिन्दल के आतंक के राज के खिलाफ संघर्ष कर रही है।

केलो वचाओ आन्दोलन के तहत अनिश्चित कालीन भूख हडताल के पर बैठी अमर शहीद वहन सत्यमाला की शहादत 26 जनवरी 98 को पुलिस हिरासत में हुई।

इसके वाद भी जिला एवम् पुलिस प्रशासन ने नवधनाढ्य अपराधी जिन्दल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसके विपरीत आन्दोलन करने वाले साथी श्री रामकुमार अग्रवाल शशिकांत शर्मा, संतोष वहिदार आदि पर फर्जी मुकदमे बाजी कर विभिन्न तरीको से प्रताडित किया जा रहा है।

हर प्रकार के दमन अत्याचार का मुकाबला करते हुए साथी गण संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं। 21 फरवरी रविवार के दिन रायगढ में जवरदस्त जवाव-तबल रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व श्री रामकुमार अग्रवाल एवं श्री शशिकांत शर्मा आदि कर रहे थे।

रायगढ के नागरिकों के लोकतांत्रिक आन्दोलन को पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा मांग करता है कि रायगढ वासियों की पानी की मांग को तत्काल पूरा किया जाए एवं नवधनाढ्य जिन्दल के खिलाफ अपराधिक प्रकरण कायम कर उसकी अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए।

कोटा, बिलासपुर : आदिवासी मजदूर संगठन के कार्यकर्ता पर जान लेवा हमने की निन्दा

जानकारी मिली है कि शराब व जंगल माफिया के गुंडों द्वारा 24 नवंबर 98 की रात करीब 4 बजे आदिवासी मजदूर संगठन के कार्यकर्ता श्री जे.पी. देवांगन का ग्राम आमामुडा (बेलगहन) से अपहरण कर लिया और उन्हें उन पर प्राणघातक हमला किया व मृत समझकर बेंदा क्षेत्र के जंगलमें छोड कर भाग गए। आदिवासी मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपरोक्त अपहरण व प्राणघातक हमला के संदर्भ में 25 नवंबर को रतनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला अस्पताल, बिलासपुर में डाक्टरी मुलाहिज़ा व एक्स रे भी कराया गया।

बेद में केस कोटा थाना स्थानांतरित कर दिया गया। कोटा पुलिसद्वारा अपरादियों के उपर नाम मात्र के लिए धारा 363, 294,325, 34 अंतर्गत भा.द.वि. लगाई गई है। अपराधी, गुंडा माफिया खुले आम घूम रहे हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

न्याय प्राप्ति के लिए साथीगण आन्दोलन कर रहे हैं। बिलसापुर जिला प्रशासन से छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा मांग करता है कि तत्काल अपराधियों पर कार्यवाही कर, न्याय प्रदान किया जाए।

रायगढ़ एवं बिलासपुर की घटनाओं की भांति छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अत्याचार, शोषण की किसी भी घटना की जानकारी मिलने पर मितान में प्रकाशित की जायेगी एवं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा हमेशा ऐसी घटनाओं का विरोध करता है।

डब्ल्यू.टी.ओ. और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनताओं का संयुक्त कार्यवाही मंच (जाफिप) 9-10 जनवरी, छत्तीसगढ़ (रायपुर) सम्मेलन

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की मेजबानी में 9-10 जनवरी 1999 को जाफिप का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में भाग लेने वालों में, जी.एन. साईबाबा, डा. दर्शनपाल (ए.आई.पी.आर.एफ.), शेषा रेड्डी (उपाध्यक्ष, कर्नाटक राज्य रैयत संघ), चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत, हरपाल सिंह (भारतीय किसान यूनियन, उत्तरप्रदेश), चौधरी घासीराम नैण, चौधरी हरिकेश मलिक, चौधरी रामफल कंडेला (भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा), सरदार हरदेव सिंहसंधु (कीर्ति किसान यूनियन, पंजाब) और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, शेख अंसार आदि शामिल थे। प्रस्तुत है चर्चा के बाद जारी किया गया प्रेस वक्तव्य :

अमर शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद शंकर गुहा नियोगी के लहूसे सिंचित छत्तीसगढ की पावन धरती पर देश भर से आये संघर्षशील किसान, मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा स्वागत करता है।

जेल से रिहा होकर सीधा छत्तीसगढ की धरती पर आयोजित इस ऐतिहासिक किसान मजदूर सम्मेलन में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा के अध्यक्ष घासीराम नैण का स्वागत हम इस नारे के साथ करते हैं कि ''जेल का ताला टूट गया हमारा साथी छूट गया।''

* डब्ल्यू.टी.ओ. उर्फ डंकल कानून और सत्ता की जन विरोधी नीतियों के विरोध में भारतीय जनता की संयुक्त कार्यवाही मंच जाफिप द्वारा 9-10 जनवरी को छत्तीसगढ के रायपुर नगर में हुए सम्मेलन में हम ऐलान करते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. भारत छोडो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत छोडो। डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्देशों के तहत हमारे देश के पेटेंट कानून, बीमा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, शहरी हतबंदी कानून, बदलने का, निजीकरण का हम विरोध करते हैं।

* छत्तीसगढ के और देश के किसानों की, एक के बाद एक तीसरी फसल, अकाल एवं पनिया अकाल की मार से बरबाद हो गई है। उन किसानों का कर्जा माफ करना होगा, पिछले वर्ष का बकाया एवं इस वर्ष का क्षतिपूर्ति मुआवजा देना होगा।

* नियोगी जी के हत्यारों को सजा दिया जाए

* 1 जुलाई 1992 के दिन भिलाई में वर्बर गोली चालन में 17 आंदोलनकारियों को गोलियों से भूनने के बाद उल्टे छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा के साथी जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, शेख अंसार, मेघदास वैष्णव सहित 23 नेताओं पर हत्या का फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। यदि मुकदमों के नाम पर छमुमो संगठन को कुचलने के प्रयासों को यदि नहीं रोका गया तो देश भर के किसान और मजदूर संगठन आंदोलन में कूद पडेंगे।

* चार-चार अदालतों के फैसले के बावजूद नौ वर्ष पूर्व काम से निकाले गये भिलाई क्षेत्र के 4200 श्रमिकों के बहाली में आनाकानी कर न्याय और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मुद्दे पर छमुमो के न्यायाग्रह आंदोलन को जाफिप पूरे समर्थन की घोषणा करता है।

* हरियाणा के किसान नेता घासीराम नैण पर, छत्तीसगढ के नेता जनकलाल ठाकुर, अनूप सिंह, शेख अंसार, मेघदास वैष्णव आदि पर, मुलताई के किसान कार्यकर्ताओं पर, आदिवासी मुक्ति संगठन, खरगोन के कार्यकर्ताओं पर और कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के नेता हरदेव संधू पर फर्जी हत्या के मुकदमों को वापस लिया जाए।

* आंध्रप्रदेश, दंडकारण्य और विहार में पुलिस बलों द्वारा फर्जी मुठभेड़ों में सैकडों नौजवानों की वर्बर हत्या एवं इज्जत अधिकार के लिये आवाज उठाने वालों पर, हर किस्म के आंदोलनों पर अभूतपूर्व दमनचक्र का हम विरोध करते हैं।

* मुलताई के अमर किसान शहीदों को नमन करते हुए मुलताई के अमर शहीदों जुग-जुग जियों और 12 जनवरी शहीद दिवस अमर रहे के नारों को बुलंद करते हुए मुलताई के संघर्षशील किसानों को देश भर के किसानों-मजदूरों का पूरा-पूरा समर्थन देते हैं।

* हम मांग करते हैं कि किसानों को उसकी फसलों का वाजिव मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित कर दिया जाए। मंडी में खरीदी के समय किसानों को परेशान करने पर तत्काल रोक लगाई जाए।

* सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान-मजदूर कर्जे में दवा है। दूसरी ओर वडे-वडे उद्योगपति, राजनेता, हजारों करोड रुपया दवाकर अय्याशी कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि किसानों की जमीन कुर्की पर रोक लगाकर राजनेता, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, मजदूरों को एक समान दर्जा देकर वसूली नीति अपनाई जाए।

2 अक्टूबर 1989 को केन्द्र सरकार की घोषणानुसार कर्जा माफी के वावजूद की जा रही जवरन वसूली को रोका जाए।

* भारत सरकार राष्ट्रीय वीज निगम को प्रदत्त वीज राशि दस करोड रुपये से बढाकर सौ करोड रुपये करें ताकि हमारा देश का यह संस्थान मौनसेंटो महिको जैसी वहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकें एवं किसानों को उचित वीज मिल सके।

* सम्मेलन में जाफिप ने आगामी 12 मार्च को वहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत छोडो नारे के साथ दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता एवं बंगलोर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष प्रदर्शन का निर्णय लिया है।

सांस्कृतिक फासिस्टों- भाजपा, आर.एस.एस., विहिप, शिवसेना, बजरंग दल द्वारा हिन्दुत्व के नाम पर अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की हम निंदा करते हैं।

* अमरीका की सैनिक गुंडागर्दी और इराक पर हमले की निंदा करते हैं।

विनीत
संयोजन समिति जाफिप

बेरोजगारी से मारा-मारी

विगत 23 फरवरी 99 को रायपुर पुलिस लाईन में पुलिस में भरती के लिये आवेदको को बुलाया गया था। 68 पदों के लिये 6,540 आवेदक पहुंचे थे। जाहिर है 6,540-68 = 6,472 आवेदक खाली हाथ वापस जायेंगे।

वापस जाने वालों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी तरह के नौजवान शामिल है। इससे स्पष्ट है कि बेरोजगारी का कारण आरक्षण नहीं लेकिन सत्ताधारियों की गलत नीतियां है।

पुलिस के अलावा आजकल किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार, भरती की खबर नहीं आती। लगता है डंकल कानून के तहत सरकार के पास जनता पर डंडा चलाने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा।

डब्ल्यू.टी.ओ. की बाध्यता के तहत नया पेटेंट कानून वर्तमान संवैधानिक ढांचा की जड़े काटने के समान

व्यवस्था के तीन स्तंभ है – विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका । विधायिका (संसद एवं विधानसभा) देश के कानून बनाती है । उन कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है । न्यायपालिका इन कानूनों के पालन की देखरेख करती है ।

स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश की सार्वभौकिता का धार इस तथ्य में बताया जाता है कि देश का कानून देश की जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाती है।

संसदीय मंत्री मदन लाल ने खुला बयान दिया है कि डब्ल्यू.टी.ओ. अर्थात विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के तहत भारत सरकार नये पेटेंट कानून को अप्रैल 1999 तक लागू करने के लिए बाध्य है । जरा सोचिये ! देश के बाहर की संस्था डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा कानून का मसौदा बना दिया गया है , और कहा जा रहा है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो इस कानून को पारित कर अप्रेल 1999 तक लागू करना ही है । यानि की सांसदों को रबर की मुहर बनकर बाहर से बनकर आये कानून पर ठप्पा लगाना है । एक स्वतंत्रत लोकतांत्रिक देश की सार्वभौमिकता के आधारभूत सिद्धांत की सरेआम धज्जियां उडाई जा रही है । निर्लज्म दलाली का तेवर देखिये कि लोकसभा में बिना चर्चा के एक ही दिन में नया पेटेंट बिल पारित नहीं होने पर राष्ट्रपति तक को बखान दिया ।

हम समस्त वकीलगण एवं विधि कार्यकर्ता के बाहरी संस्था की बाध्यता के तहत नया पेटेंट कानून लागू कर सार्वभौकिता एक संवैधानिक ढांचा की जड़ों को काटने के प्रयासों का विरोध करते हैं, और इस मुद्दे पर पूरे देश में जनमत संग्रह की मांग करते हैं ।

दुर्ग जिला न्यायालय के वकीलगण

के.एल. तिवारी, (प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, दुर्ग, म.प्र.)

मोहम्मद मुनीर, आर.बी. मिश्रा, एम.पी. सिंग, पी.के. चन्द्राकर, एस. विजयकुमार, आलोक शर्मा, हरजीतसिंग, एम.एम. बेग, वी. दुबे, वी. चौधरी, टी.के. तिवारी, वी.के. दुबे, बी.एल. पारस, रंजना बहल, स्मिता जैन, महेन्द्र शुक्ल, आर.एल. पाण्डेय, आई.पी. तिवारी, वाई. सिंग, श्रीमती चन्द्राकर, संतोष चौबे, के.डी. त्रिपाठी, डी.पी. चौधरी, पी.के. झा, जे.एल. देवांगन, एम.के. झा., कुमारी सुधा दिल्लीवार, संतोष खोडियार, एम.आई. खान, एम.ए. अन्सारी, एन.के. कलिहारी, चेतन चंद्राकर, बी.के. मोहबे, संतोष सोनी, एच.पी. शाह, राजेन्द्र प्रसाद, एल.पी. वर्मा, के.सी.दत्त , व्ही.एस. ठाकुर, डी. गुप्ता, एस.के. भट्टाचार्य, दुर्गा, ए.के. शर्मा, पी.के. पटेल, एन.के. साहू, एम.एम. देवांगन, के.के. माथुर, सोहन चंद्रपाणि, संतोष धनकर, अजीत पाल, एस. सतपथी, एम.के. अग्रवाल, आर.बी. गुप्ता, डी.के. वर्मा, रसरत जहान, पी. गुप्ता, डोमेश कुमार, रमेश कुमार साहू, रमेश प्रसाद, शकील सिद्दिकी, अजय भट्टाचार्य, मनोज मिश्रा, ए.एस. टोंगे, व्ही.एस. अग्रवाल, ए.जे. सिंग, कंचन बाला,

राजेश महाडिक, डी. संजीवी, एम.एल. मिश्रा, गिरीशचंद्र शर्मा, अमरकांत, उपेन्द्र सिंह राजपूत, दुष्यंत देवांगन, विद्या, कुंज बिहारी, विपिन कुमार शर्मा, गिरधर लाल यादव, गोविंद राम साहू, प्रसून शर्मा, दीप्ति शर्मा, श्याम मिश्रा, एम.पी. तिवारी, बी.एल. पटेल, एच.एस. साहू, डी.एस. साहू, ललित कुमार आडिल, संतोष, एम. कसार, राजेश कुमार साहू, भूपेन्द्र, गौरी, सूर्य रंजन अग्रवाल, ए.के. पुरकेत, बी.आर. , जी.के. भोसले, शिवानंद साहू, सुदेश, वाई. श्रीवास्तव, डी.के. शिरके पुरुषोत्तम स्वामी, राजेश्वर शर्मा, इन्द्रजीत चौहान, अनिल सिंग, अजय कुमार, के.के. जैन, एन.के. साहू, एन.के., सुरेन्द्र उके, निर्मल चंद्राकर, एन.आर. वर्मा, अजय पांडेय, हेमंत नायडू, पद्मकरन, अवनिन्द्र झा, अजय शर्मा, आर.के. साहू, ऋषभ वर्मा, शरीक अहमद, जी.डी. देवांगन, सुशील कुमार त्रिपाठी, के.के. द्विवेदी, एल.के. सिंग, एम.के. खान, वेद कुमार, सी. घोष, कल्पना दत्ता, बिन्दु नायर, देवेन्द्र यादव, रामबाबू गुप्ता, नवीन कुमार दुबे, अशोक कुमार दुबे, के.एन. चतुर्वेदी, एच.सी. ताम्रकर, शिवशंकर सिंह, रामेश्वर प्रसाद प्रजापति, संतोष वर्मा, नरेन्द्र प्रसाद चौधरी, एन. बनर्जी, एम. के. दिल्लीवार, श्रीमती माया गुप्ता, बशीर आलम, कु.पी. श्रीवास

(रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुन्द, बालोद, बेमेतरा आदि पूरे छत्तीसगढ में यही हस्ताक्षर अभियान जारी है ।)

सुनहर निषाद एवं मेहतर राम मंडावी की मौत

पुलिस प्रताड़ना में हमेशा गरीब आदमी ही क्यों मरते है ?

विगत 16 जनवरी को गोबरा नवापारा थाने में निर्मम पिटाई से हमाली का काम करने वाले 26 वर्षीय सुनहर राम निषाद की मौत हो गई । सुनहर गरियाबंद के पीपरछेडी गांव का रहने वाला था

14 अक्टूबर को अन्तागढ थाना में पुलिस प्रताड़ना के कारण मेहतर राम मंडावी ने दम तोड़ा था ।

डौंडी थाना में पिटाई से कन्नू हलवा की जान गई थी ।

छावनी थाना भिलाई में पुलिस प्रताड़ना से नौजवान जोजी की मौत जुलाई 1992 में हुई थी ।

दूसरी ओर बी.आर. जैन, सुरेन्द्र जैन, हर्षद मेहता जैसे सुपर अपराधियों को पुलिस के बड़े बड़े अफसर सलाम बजाते है । यदि इन्हें दो जूता लगाया जाता तो क्या ये हवाला कांड आदि सुपर अपराधों में सबूत उपलब्ध नहीं कराते ? मानवाधिकार सिर्फ जैन मेहता के ही क्यों ? क्या सुनहर निषाद, मेहतर मंडावी मानव नहीं हैं ?

12 जनवरीशहीद दिवस अमर रहे
मुलतई के शहीदों जुग जुग जियो

शहीद दिवस पर गिरफ्तारियों एवं पुलिस बंदोबस्त की निंदा

पिछले बरस 12 जनवरी को दिग्विजय सिंह सरकार ने प्राकृतिक आपदा से क्षति की पूर्ति का मुआवजा के लिये आन्दोलन करने वाले किसानों पर बर्बर गोली चालन कर 23 किसानों को गोलियों से भून डाला था ।

इस वर्ष पहले शहादत दिवस पर देश भर के मजदूर किसानों के प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर भाग लिया।दिग्विजय सरकार ने भारी पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स आदि लगाकर मुलतई में धारा 144 लगाकर शहीद दिवस मनाने पर रोक लगा दी।

तमाम मजदूर किसानों में समीपस्थ ग्राम परमंडल में एकत्रित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी उसके बाद सभी ने मुलतई की ओर प्रस्थान किया तो दिग्गी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया । गिरफ्तार होने वालों में छ.मु.मो. अध्यक्ष साथी जनकलाल ठाकुर, मेधा पाठकर, डा. सुनीलम, सुनील, राजेन्द्र सायल, सुरेन्द्र मोहन आदि शामिल थे ।

एच.एस.सी.एल. कर्मियों के समर्थन में छ.मु.मो. द्वारा कार्यक्रम

वेतन भुगतान के लिए प्रदर्शन कर रहे एच.एस.सी.एल. श्रमिकों पर 2 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठी चार्जके विरोध में विगत 3 फरवरी को छ.मु.मो. द्वारा भिलाई के मोहल्ले-मोहल्ले में मशाल जुलूस नारे बाजी का कार्यक्रम किया गया ।

शहीद नियोगी हाईस्कूल, कोण्डे-धोबे

नवां भवन के उद्घाटन 26 जनवरी, 1999 के दिन होइस जेन बिलिडिंग बर सरकार हा 10 लाख खर्चा करती ओला ग्राम धोबेदण्ड, कोण्डेकसा, दर्राटोला, कुंजाम टोला के ग्राम वासी मन अउ दल्ली खदान के मजदूर साथी मन अपने अपन जुर मिल के बना डारिन ।

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस 4 फरवरी

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के आमंत्रण पर साथी जनकलाल ठाकुर और साथी एस.के.सिंह ने 4 फरवरी 99 को धनबाद में आयोजित झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस में भाग लिया और झारखण्ड की जनता के प्रति छत्तीसगढ की जनता की एकजुटता का संदेश पहुंचाया ।

महिलाओं, बच्चों द्वारा शराब विरोधी अनिश्चितकालीन धरना जारी

छत्तीसगढ महिला जागृति संगठन द्वारा विगत 6 फरवरी 1999 से शराब बन्दी एवं किसानों को अकाल राहत की मांग के लिए रायपुर के अम्बेडकर चौक पर एवं महासमुन्द के लोहिया चौक पर धरना जारी है ।

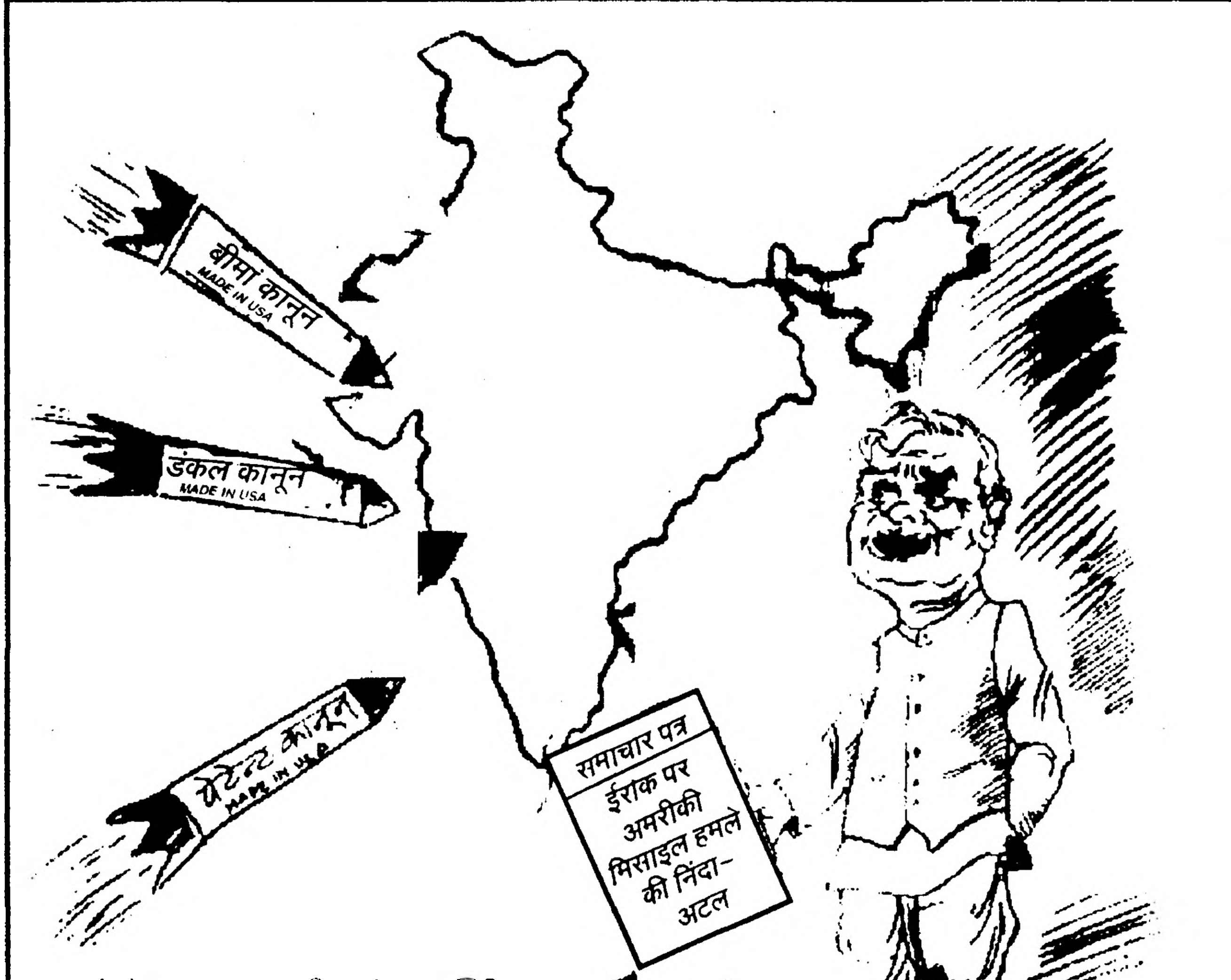

अपने देश पर अमरीका के आर्थिक हमलों के बारे में भाजपाई अटल और कांग्रेसी मनमोहन मौन क्यों ?

अमरीका एवं डंकल डालर के आर्थिक हमलों के समक्ष भाजपा-कांग्रेस ने घुटने टेके। देश की रक्षा कौन करेगा ?

किसानों को अकाल राहत अउ डंकल कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथियों को महासमुन्द पुलिस ने 20 फरवरी को गिरफ्तार किया। छमुमो द्वारा आन्दोलन की चेतावनी के बाद 21 फरवरी को उन्हें निशर्त रिहा किया गया। पुलिस द्वारा मारपीट में क्रांतिकारी नेत्रहीन साथी राममूर्ति को चोटें भी आई। जेल से छूटने के बाद रंग गुलाल से सने साथी राममूर्ति का चित्र नीचे देखिए

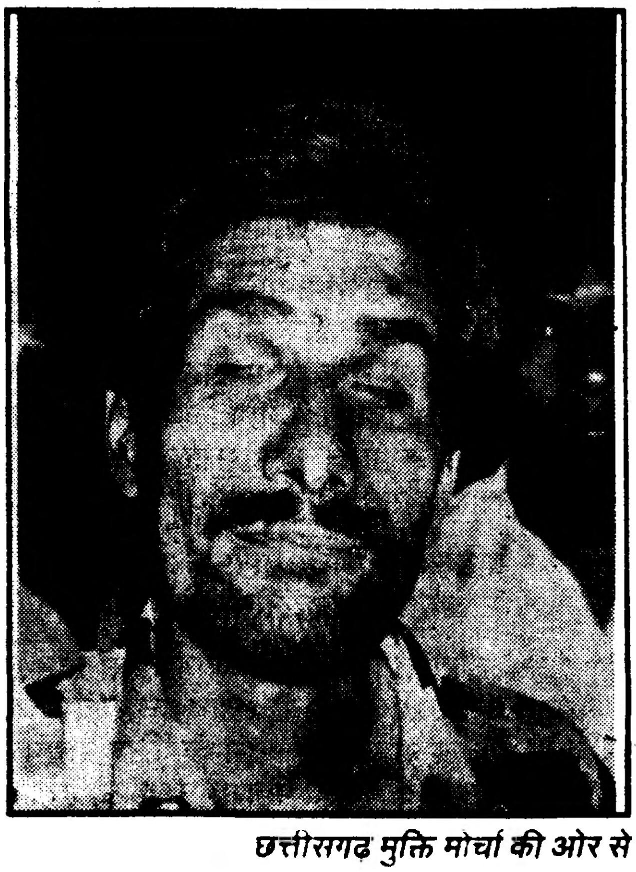

अमरीका अउ डंकल कानून उर्फ डब्ल्यू.टी.ओ. के दलाल मन ल खेदारे बर, हमर उद्योग अउ कृषि के रक्षा करे बर छत्तीसगढ़ के मजदूर किसान डटे हावय रण के मैदान म

डंकल कानून के माध्यम से देश की सम्प्रभुता पर हमले के विरोध में 26 जनवरी 99 को पिथौरा में प्रदर्शन के दौरान अमरीका के झंडे को जलाते हुए छमुमो उपाध्यक्ष साथी शेख अंसार

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से साथी जनक लाल ठाकुर द्वारा प्रकाशित संपादक - अनूप सिंह, **सौ सुनार की, एक लोहार की**

इंडिया नं. १

INDIA No. 1

- बदबू फैलाने में
- नदी-नालों में जहर घोलने में
- मछुवारों को बेरोजगार करने में
- किसानों की खेती उजाड़ने में
- बीमारी फैलाने में
- इंसानों का खून पीने में

हाउस ऑफ ~~केडिया~~ भेड़िया

HOUSE OF ~~KEDIA~~ BHENDIYA

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा जनहित में प्रकाशित

इंडिया नं. १

INDIA No. 1

डिस्टिलरी के पानी से खारून नदी में प्रदूषण

Liquor factory makes citizens life intolerable

प्रबंधन ने कहा- बचाव कार्य जारी

डिस्टलरी की गंदगी से वातावरण विषाक्त

केडिया डिस्टलरीज का डेम फटने से ८ किमी क्षेत्र का जल प्रदूषित

केडिया डिस्टलरी की जांच, भारी अनियमितताएं मिलीं

खारून में छोड़े प्रदूषित पदार्थ से मीलों तक पानी से आक्सीजन साफ, मरी मछलियों का अंबार लगा

गांव वालों को नहाने ६ कि.मी. दूर जाना पड़ा

Waste water flows into Kharun River

डिस्टिलरी के पानी से खारून की हजारों मछलियां मरीं

डेस्टलरी से हो रही बिमारियों को 'जूडो' उजागर करेगा

‌डिया डिस्टलरी में प्रदूपित पानी का म फटाःसौ से अधिक गांव प्रभावित

गांव की फसल खतरे में: मछली व मवेशी मरे

हाउस ऑफ केडिया भेड़िया

HOUSE OF KEDIA BHENDIYA

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा जनहित में प्रकाशित

इसलिये पर्यावरण की बात मत उठाओ
विकास की दौड़ से राष्ट्र को पीछे मत लौटाओ।

तुम पूछते हो कि राष्ट्र कहते किसे हैं?
ऐसे सवाल राष्ट्र-द्रोही पूछते हैं।

तुम्हें मालूम होना चाहिये कि
वह गुलाम हैं जिनकी,
सत्ता पर लगाम है जिनकी,
जिनका नियंत्रण है पूंजी पर,
जो बड़े-बड़े उद्योग चलाते हैं
फैक्टरी के कचरे से,
नदियां सड़ाते हैं,
साफ हवा में जहर मिलाते हैं।

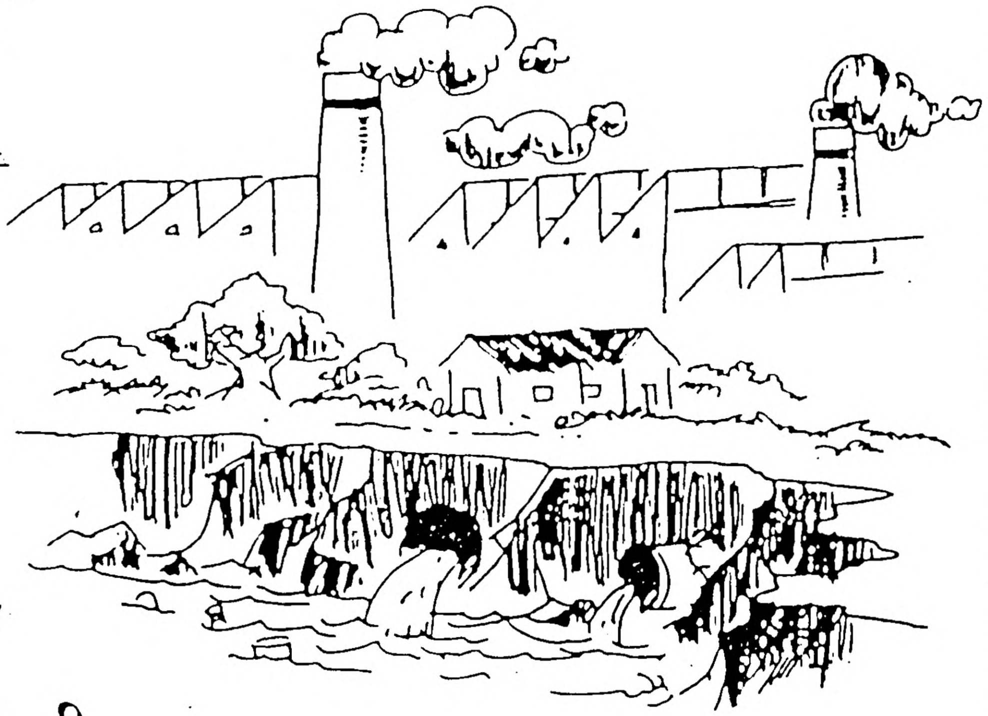

इंडिया नं. १

INDIA No. 1

डिस्टिलरी के पानी से खारून नदी में प्रदूषण

Liquor factory makes citizens life intolerable

डिस्टलरी की गंदगी से वातावरण विषाक्त

केडिया डिस्टलरीज का डेम फटने से ८ किमी क्षेत्र का जल प्रदूषित

खारून में छोड़े प्रदूषित पदार्थ से मीलों तक पानी से आक्सीजन साफ, मरी मछलियों का अंबार लगा

Waste water flows into Kharun River

डिस्टिलरी के

[illegible] पानी से खारून

छीन लिया है, जिन्होंने सूरज को,
और छिपा दिया है धुएं के पहाड़ के पीछे,
सुबह होने की खबर मिल सके,
इसलिये मिल का भोंपू बजाते हैं।

छलनी कर दिया है धरती का कलेजा
अंधाधुंध ऊर्जा के दोहन से
राष्ट्र यानी खुद के लिए
हर साल अरबों मुनाफा कमाते हैं।

अरे, राष्ट्र वो हैं, जिनके हाथ में है संपन्नता,
राष्ट्र नहीं होती भुक्खड़ जनता।

(श्री श्याम बहादुर नम्र की 'राष्ट्र नहीं होती भुक्खड़ जनता' नामक कविता से साभार)

हाउस ऑफ ~~केडिया~~ भेड़िया

HOUSE OF ~~KEDIA~~ BHENDIYA

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा जनहित में प्रकाशित

मजदूर भूख से
तिल-तिल नहीं मरेंगे,
संघर्ष के मैदान में
भले ही मर मिटेंगे।

- भिलाई के अपराधी-नवधनाढ्य उद्योगपतियों की कठपुतली बन कर पटवा सरकार ने नादिरशाही अत्याचार ढाए। नियोगीजी की हत्या, १ जुलाई को भिलाई में गोलीकांड, हजारों महिला पुरुषों को (अनेकों को बाल बच्चों सहित) जेल में ठूंसा, मजदूर नेताओं को बर्षों से कैद में रखा।

- श्रम-कानून के पालन के लिए आवाज उठाने पर हजारों मजदूर परिवार को काम से निकाल कर भूखों मारकर संगठन को तोड़ने का प्रयास जारी है।

- कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे जाहिर हो कि वे भाजपा से कोई अलग हों।

- लाल-हरा झंडा लेकर भिलाई, उरला, कुम्हारी, टेड़ेसरा, रींवागहन, महासमुंद, बलौदा बाजार, मोथीपार व बोरई के मजदूर आन्दोलन हर संकट से टकराकर आगे बढ़ता जा रहा है।

- यह आन्दोलन आज छत्तीसगढ़ के लाखों मेहनतकश जनता के दिलों की धड़कन बन चुका है।

- छत्तीसगढ़ के बलिदानी मजदूर अपराधी-नवधनाढ्य उद्योगपतियों को घुटने टेका कर ही दम लेंगे।

14 मार्च 1994 : सिम्पलेक्स के टेड़ेसरा कारखाने में जबरदस्त विस्फोट ३ श्रमिक मरे १४ घायल । महेन्द्र शाह की निजी सेना ने पत्रकारों से कैमरे छीना, दुव्यवहार किया ।

22 मार्च 1994 : दुर्ग न्यायालय परिसर में हत्यारा उद्योगपति नवीनशाह और भाड़े के टट्टू पल्टन मल्लाह में मारपीट प्रशासन कठपुतली बनकर देखता रहा ।

नवधनाढ्य छाती ठोककर कहते हैं—

सिम्पलेक्स कहता है – "वी. सी. शुक्ला ने मेरा निजी गुंडा प्रभुनाथ मिश्र के कंधे पर हाथ रखकर उसे कांग्रेस का बड़ा नेता बना दिया है ।"

बी. आर. जैन कहता है – "वी. सी. शुक्ला की मदद से रेल्वे का ठेका मुकुन्द स्टील की जगह बी. ई. सी. को दिलवाया है ।"

सी. बी. आई. द्वारा जब्त डायरी कहती हैं – "जैन बंधुओं ने मि० वालिया के माध्यम से 65 लाख रुपये से अधिक दिये है ।"

केडिया कहता है – "मेरी लड़की की शादी में सब कोई राजनेता मेरा नमक खाकर गए हैं ।"

शुक्ला परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी छत्तीसगढ़ में अपनी राजनैतिक मालगुजारी चलाते आ रहे हैं । हम "छत्तीसगढ़ के स्वयंभू-सपूत" वी. सी. शुक्ला से पूछते हैं–

(१) आपने भिलाई और दल्ली-राजहरा में जाकर और श्यामाचरणजी ने भिलाई में शहीद और घायल परिवारों में जाकर आंसू टपकाये थे ।

(२) हर चुनावी आम सभा में नियोगीजी और मजदूर आन्दोलन का हितैषी बताकर वोट की भीख मांगी थी । अब मजदूरों के दुःख दर्द को कैसे भूल गये ?

(३) पहले तो आप कहते थे कि भाजपा सरकार है । अब तो आपकी पार्टी की सरकार भोपाल में भी और दिल्ली में भी । अब हम क्यों नहीं ?

(४) प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के तुरन्त बाद आपने मुख्यमंत्री को दो पत्र लिखे थे । एक रायपुर में खण्डपीठ हेतु दूसरा बिलासपुर में रेल्वे जोन हेतु । यह तो आपने बहुत अच्छा किया । लेकिन भिलाई के औद्योगिक विवाद के समाधान हेतु आपने पत्र नहीं लिखा । क्यों ?

(५) 28 सितम्बर 1989 को हरसूद की रैली में आपने हाथ उठाकर घोषणा किया था । नर्मदा बांध की ऊंचाई कम की जाय । अब केन्द्र में जल संसाधन मंत्री होकर आप ठीक विपरीत बोल रहे है । क्यों ?

(६) क्या गुजरात में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिये मध्यप्रदेश के इलाकों को डुबोया जा रहा है, यदि नहीं तो फिर अधूरे बांध के गेट बंद करने की जिद क्यों ?

(७) प्रदेश विधान सभा में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव हो चुका है । केन्द्र में स्वयं कांग्रेस की सरकार है, फिर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन में देरी क्यों ?

(८) आपके पिता ने भिलाई में इस्पात कारखाने की स्थापना का श्रेय लूटा था । बी. एस. पी. ने अंचल के संसाधनों को लूटा । अब नई औद्योगिक आर्थिक नीति के तूफान में इस छत्तीसगढ़ के औद्योगिक केन्द्र को भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे है । रावघाट की लौह अयस्क खदानों में जापानी आस्ट्रेलियाई कंपनियों की गिद्ध नजर टिकी है । देशद्रोही मशीनीकरण के कारण लाखों नवयुवक बेरोजगारी के शिकार है । इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका कोई बयान नहीं है । अपनी नीति घोषित करें ।

(९) किसानों का सर्वनाश करने वाला और देश को गुलाम बनाने वाले डंकल प्रस्ताव के विरोध में आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है, क्यों ?

[१०] आपके द्वारा रायपुर में शहीद भगतसिंह की प्रतिमा का अनावरण एक बड़ी खबर बनी थी, लेकिन भगतसिंह की राह पर चलने वाले छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथियों के खिलाफ काला अंग्रेजों का अत्याचार जारी है, क्यों ?

हम भगतसिंह का अन्दाज बता सकते हैं,
और अशफाक के तेवर दिखा सकते हैं।
मादरे हिन्द की लाज बचाने के लिये,
बनके दरिया सड़कों पे भी उमड़ सकते हैं।

8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने दिल्ली असेम्बली हाल में बम फेंका था और कहा था—

"बहरों को सुनाने के लिये धमाकों की जरूरत होती है।"

13 अप्रैल को अंग्रेजों ने अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड रचा था। इतिहास से प्रेरणा लेकर—

---

8 अप्रेल से 13 अप्रेल तक औद्योगिक क्षेत्र में हर रूप में खिलाफत आन्दोलन होगा।

नवधनाढ्य उद्योगपतियों के पिट्ठू बनकर मेहनतकशों के पेट पर छुरी चलाने वाली व्यवस्था कायम रखने के लिये भिलाई के अपराधी उद्योगपतियों को कानून के दायरे में लाना होगा और मजदूरों की संवैधानिक मांगों को स्वीकार करना होगा।

लाल-हरा झंडा जिन्दाबाद !

प्रगतिशील इंजिनियरिंग श्रमिक संघ जिन्दाबाद !

छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ जिन्दाबाद !

प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ जिन्दाबाद !

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद !

शहीद साथी अमर रहे !

शेख अंसार
उपाध्यक्ष प्र. इं. श्र. संघ, उरला

भीमराव बागडे
महामंत्री छ. के. मि. म संघ, कुम्हारी

एन. आर. घोषाल
संगठन मंत्री प्र. सी. श्र. संघ, भिलाई

मेघदास वैष्णव
उपाध्यक्ष प्र. इं. श्र. संघ, टेडेसरा

जनकलाल ठाकुर
विधायक, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

मुद्रक : विजय प्रिंटिंग प्रेस स्टेशन रोड, बालोद

संगठन ही जनता की शक्ति का आधार है
– शहीद शंकर गुहा नियोगी

छत्तीसगढ़ के मजदूर किसानों की आवाज

मितान

निजी वितरण हेतु

11 अगस्त से 22 अगस्त 1999 तक

✱ 16 जुलाई को जयपुर में फौजी भर्ती में 20 हजार युवा बेरोजगार उमड़े, भारी अफरा तफरी, पुलिस गोली चालन में एक मृत।

✱ 16 जुलाई को ही भरतपुर में फौजी भर्ती हेतु 25 हजार से अधिक युवा बेरोजगार उमड़े भगदड़। पुलिस गोली चालन में दो युवकों की मृत्यु।

✱ 17 जुलाई को दरभंगा में फौजी भर्ती के फिर 25 हजार की भीड़ पुलिस गोली चालन में 23 की मृत्यु

✱ 17 जुलाई को छपरा में फौजी भर्ती के लिए बेरोजगार युवकों की भारी भीड़ पुलिस गोली चालन में 3 की मृत्यु हुई।

✱ 19 जुलाई को नागपुर में फौजी भर्ती के लिए भारी भीड़ 5 हजार क्षमता वाले मैदान में 25 हजार दौड़ पड़े। भगदड़, लाठी चार्ज।

देश की सुरक्षा को गंभीरतम खतरा

हमारे ही 29 नौजवान बेरोजगार
मारे गए,
हमारे ही सिपाहियों द्वारा
मगर वे नहीं है सिर्फ 29
उन 29 के पीछे,
20 करोड़ नौजवान बेरोजगार
भी हुए है शिकार
दोनों हाथ काट देने वाली बेरोजगारी के
20 करोड़ नौजवानों के हाथ
देश की पूरी युवा पीढ़ी के हाथ
देश का भविष्य संभालने वाले हाथ
काटे गए 40 करोड़ हाथ।
इस अथाह दुख पर,
दिल से निकले जो आंसू तो
हिन्द महासागर छोटा पड़ जाए
उन आंसू को बना कर अंगार
जब घूर के देखें,
इस व्यवस्था सड़ी-गली को
पोखरण परमाणु बम भी छोटा पड़ जाए।
दाने-दाने को भटकता किसान अन्नदाता
डंकल डालर की दलाली में मस्त राजनेता
विदेशी घुसपैठ उद्योग और कृषि में
उद्योगपति वर्ग विचार शून्य है बैठा
श्रम बाहुल्य देश में,
पूंजी बाहुल्य तकनीक- गले का पत्थर
बढ़ता कर्ज, घटती क्रय क्षमता
नतीजन उपजी मंदी में,
कराहता - व्यापार और उद्योग जगत,
20 करोड़ नौजवानों के
40 करोड़ हाथ काट देने वाली बेरोजगारी
देश की सुरक्षा को गंभीरतम खतरा।

From MITAN

Dated 26th February 99

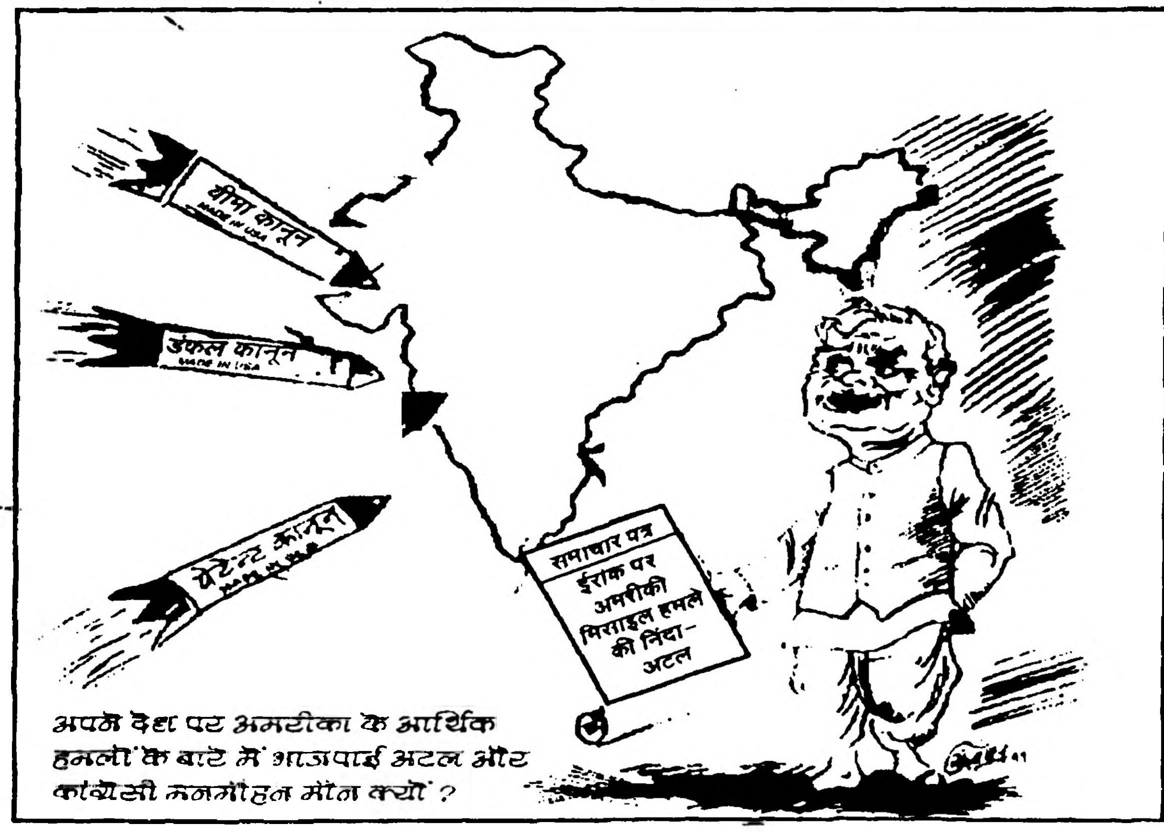

अमरीका एवं डंकल डालर के आर्थिक हमलों के समक्ष भाजपा-कांग्रेस ने घुटने टेके। देश की रक्षा कौन करेगा ?

दुनिया में आतंकवाद की खेती करने वाली अमरीका सरकार को भाजपाईयो ने अपना थानेदार बनाया

देशबन्धु दिनांक 26-7-99

''अमरीका से पाक को भेजी जा रही परमाणु सामग्री ब्रिटेन में जब्त ''

26 जुलाई के अखबारों में अमरीकी विदेश मंत्री अलब्राईट और भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंग की बातचीत के बड़े गुनगान हुए है। आर.एस.एस. और भाजपा विचारधारा के खट्टूस लोग फूले नहीं समा रहे है कि अमरीका ने भारत को दोस्त बना लिया है।

जिस दिन ये समाचार छपे उससे एक दिन पूर्व लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र संडे एक्सप्रेस का 25 जुलाई का समाचार है कि ब्रिटेन के कस्टम विभाग ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिये भेजी जा रही आवश्यक सामग्री को जब्त कर लिया है।

पाकिस्तान के खिलाफ छोटे से मुद्दे को लेकर के तूफान खड़े करके मुख्यधारा के राजनेता और मीडिया इस मामले में चुप्पी साधे है। क्यों ? जाहिर है अमरीका तो इनका माई बाप है उसके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत ये कैसे कर सकते है।

अभी कुछ दिंन पूर्व 30 मई को भारत के रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीज ने बयान दिया था कि कारगिल के घुसपैठिये वापस लौटे तो उन्हें लौटने दिया जायेगा। इस बयान पर राजनेताओं और मुख्यधारा मीडिया ने जो हाय तौबा मचाया कि पूछों मत ! सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेताओं ने खुद अपने रक्षा मंत्री की जमकर खिंचाई करने लगे। लालकृष्ण आडवानी, नरेन्द्र मोदी, कुशाभाऊ ठाकरे ललकारते सुनाई दिये - हमारे जवानों का खून बहा है हम कैसे आक्रमणकारियों को लौटने का सुरक्षित रास्ता दे सकते हैं। आदि आदि ..

थानेदार बिल क्लिंटन ने फोन करके अटल बिहारी वाजपेयी को बताया - घुसपैठिये वापस जायेंगे उनके लिये रास्ता सुरक्षित कर दो।

घुसपैठियों की सुरक्षित वापसी हो गई। अब किसी ने चूं तक नहीं की। राजनेता और मीडिया जवानों के लहू की दुहाई देने वाले सब चुप थे, सबकी बोलती बंद। थाने दार बिल क्लिंटन को बोलने की हिम्मत इनमें से किसी की नहीं।

क्या आप जानते हैं कि आई.एस.आई. को तमाम हथियार गोला बारूद अमरीका द्वारा सप्लाई की गई है। क्या आप जानते हैं कि 1985 में जियाउलहक के साथ गुप्त समझौता के बाद अमरीका ने पाकिस्तान को परमाणु तकनीकी उपलब्ध कराई थी ?

भारत, चीन, पाकिस्तान आदि पड़ोसी देश आपस में जितना लड़ेंगे उतना ही अमरीकी शस्त्र व्यापारियों को फायदा होगा और अमरीका को घुसपैठ यानि थानेदारी करने का बहाना मिलेगा।

खतरा ! सावधान !

Mitan Editorial Dt. - 5th July 98

भाजपा सरकार का बजट , अमरीकी शस्त्र व्यापारी खुश !

बजट में रक्षा व्यय में अभूतपूर्व 14% यानि 5101 करोड़ रूपये की वृद्धि. इसमें से 4 हजार करोड़ से अधिक अमरीकी शस्त्र व्यापारियों के झोली में जाना अनुमानित. भारत - पाक शस्त्र दौड़ में इस अभूतपूर्व तेजी से अमरीकी शस्त्र व्यापारी मालामाल होंगे. डालर की मार से विगत 18 वर्षों में भारतीय रूपये में 500% की गिरावट. पाकिस्तानी रूपया भी डालर के मुकाबले 500% घटा है. डालर से भारतीय एवं पाकिस्तानी रूपया की रक्षा के लिए पड़ोसी देशों को आपसी आर्थिक सहयोग जरुरी. गुजराल सरकार ने ढाका बैठक में पड़ोसी देशों के आपसी व्यापारिक सहयोग की अच्छी शुरुआत की थी. भाजपा सरकार ने आते ही युद्ध का उन्माद छेड़ दिया. रूपया, सीमा के इस पार का और उस पार का, भारी संकट में, डॉलर खुश.

Chhattisgarh Mukti Morcha has publically challenged the armanent policy of our ruling class at every important instant.

Even during the war hysteria of Kargil,
CMM members gathered in thousands and challenged
the same in 1st July public meeting at Bhilai.

Condemmation of neuclear explosion appeared in this form :

Rupee,
On this side of the border
and on that,
is being battered by dollar,
the biggest threat to
each's national secuirity

शासकों का परमाणु गौरवगान धिक्कार है

प्रधानमंत्री के नाम - छ.मु.मो. का खुला पैगाम : 17-5-98

क्यूं खुदकशी कर रहे देश के सैंकड़ों
किसान - अन्नदाता,
नवजवान अशोक नायक आत्महत्या पर
मजबूर क्यूं हो जाता ?
पनिया - अंकाल से मची छत्तीसगढ़ में हाहाकारी,
सुनसान हो रहे गांव, पलायन भारी,
जान देनी पड़ रही है पाने को
बचाने को, पीने का पानी,
गवाही रायगढ़ के बहन सत्यभामा की कुरबानी,
भूखहड़ताल में जिन्दल उद्योग के समक्ष
दिन 26 जनवरी 98 गवां दी अपनी जिन्दगानी।
इस हाल पर हम जश्न
कैसे मना लें वाजपेयी जी ?......।
करोड़ों जनता के समक्ष, रोजी - रोटी का सवाल,
खोजते - खोजते जवाब,
व्यवस्था की घोर उपेक्षा ले लेती उनके प्रांण
उस व्यवस्था द्वारा,
परमाणु - बम का गुणगान
है नीरो की बांसुरी के समान, ...।
विकास की सीढ़ी पर, दुनिया में 134 वां स्थान,
भूख गरीबी, बेरोजगारी के नाम,
फेाड़ कर एक परमाणु - बम
नहीं हो जाएगा उन्नति में छठवां (6) वां स्थान
आप कहते हैं, जश्न मना लो,
गा लो गौरव गान,

व्यवस्था के इस हाल पर हम जश्न,
कैसे मना लें वाजपेयी जी ?
हम तो करते है
धिक्कार
अपनी
हेक्क
उपेक्षा से
जनताओं को,
मौत के मुंह में धकेलने
वालों को, ...।

There are three speceis, that rejoice killing fields. Kite, vulture and the American arms dealer.

क्र य - शक्ति तुलनात्मकता में
(In Purchasing Power Parity)
डालर 3 रूपया समान,
पर डालर दलालों के बदौलत
आज 40 रूपया उसका दाम.
आने वाले बरस में हो जाए 400 रूपया भी,
तो मत होना हैरान.
हालात - ए-रूस, इंडोनेसिया, मैक्सिको इसकेप्रमाण....।
विदेशी कम्पनियों की लूट बड़ी,
देश के उद्योग और कृषि पर
अभूतपूर्व संकट की घड़ी.
दोहराया जा रहा है फिर से,
ईस्ट इंडिया कम्पनी का इतिहास ,

तलवार और तोप नहीं,
दुश्मन तो आता है अब,
लेकर व्यापार का प्रस्ताव..........।।
टीपू और मराठों को
सिखों और अफगानो को
लड़ा - भिड़ा कर अंग्रेजों ने
हिन्दुस्तान फतह पाया था.
पड़ौसियों से भारत को लड़ाने का तरीका
अमरीका ने पाया है,.......।
भारत को,
उसके पड़ोसी देशों को
और सैकड़ों गरीब देशों को
देखो, आ रहा है जीतने
'डंकल बम' और 'डालर बम' के साथ .....।
तीन ही प्रजातियों है जो
जश्न मनाती है युद्ध की संभावना में,
चील, गीध और अमरीकी शस्त्र व्यापारी,
भारत - पाकिस्तान की लड़ाईयों - तनावों में शस्त्र
व्यापारियों ने हजारों करोड़ कमाए है.
अब पेक्षपास्त्र पृथ्वी और गौरी की,
परमाणु - क्षमताओं, हथियारों, की दौड़ में
लाखों करोड़ कमाने के टारगेट बनाए हैं....।
कोशिश यह भी है कि 18-20 मई की
जेनेवा बैठक में, डंकल - कानून पर
भाजपा सरकार की सील की खबर,
परमाणु विस्फोट के शोर में दब जाए ....।।

When a day's wage was being deducted from workers salaries, we challeged the ruling class in so many words :

" Soldiers dying on either side of the borders are the sons of workers and peasants. If you have an information of any industrialist's or politician's son gettings killed, please let us know ?"

संघर्ष के लिये निर्माण
निर्माण के लिये संघर्ष

भिलाई कार्यालय MIG/I/55
आमदी नगर, भिलाई - दुर्ग
फोन नं. 322688

प्रगतिशील सीमेन्ट श्रमिक संघ

जामुल - भिलाई जि. दुर्ग (म. प्र.)
Regd. No. 4060

पत्र क्रमांक__________ दिनांक__________

प्रति,

श्रीमान् प्रबंधक,
जामुल सिमेंट वर्क्स,
ए.सी.सी. जामुल, भिलाई ।

विषय : कारगिल युद्ध के मद्देनजर आर्थिक सहयोग देने बाबत् ।

महोदय जी,

कंपनी के अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा तमाम श्रमिकों पर दबाव डाला जा रहा है, कि वे उपरोक्त बाबत् एक दिन का वेतन जमा करें । उक्त मुद्दे पर हमारी यूनियन से सम्बद्ध समस्त श्रमिक एक दिन के बजाए दो दिन का वेतन देने को स्वेच्छा से तैयार हैं । इसी के साथ-साथ व्यवस्था के अधिकारियों से पारदर्शिता [transparancy] एवं जवाबदेही [accountability] के तकाजे के तहत निम्न मुद्दों के विषय में स्पष्ट जानकारी चाहते हैं, ताकि हमारी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई के दुरूपयोग पर हम नजर रख सकें :—

[1] आम जनता की सहयोग राशि प्रधानमंत्री के कोष में जमा हो रही है । दूसरी ओर, केन्द्र सरकार के 4,500 करोड़ रूपये उस समय लुटवा दिये गये जब प्रधानमंत्री ने विदेशी टेलीफोन कंपनियों पर लाइसेन्स फीस के बकाया हजारों करोड़ की सालाना किश्त को माफ कर दिया । केन्द्र सरकार को कुल हानि एवम् विदेशी टेलीफोन कंपनियों को कुल लाभ 4500 करोड़ से कम नहीं है । प्रधानमंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की सलाह को भी नामंजूर कर दिया । अब हम ऐसे प्रधानमंत्री के कोष में अपने खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को क्यों और कैसे जमा करें । जो कि जनता की गाढ़ी कमाई विदेशी टेलीफोन कंपनियों को लुटवाता हो ?

[2] देश का करीब दो लाख करोड़ रूपया अभी बतौर कालाधन, नवधनाढ्यों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा है । युद्ध के मद्देनजर आर्थिक संकट की स्थिति में इस अपार राशि का कितना हिस्सा देश एवं सरकार में लाया गया है ? जानकारी से उत्साहवर्धक होगा ।

// 2 //

पत्र क्रमांक__________ दिनांक__________

[3] तमाम फिल्मी सितारों द्वारा युद्ध के मद्देनजर आर्थिक सहयोग का आव्हान आम जनता को किया जा रहा है । अमिताभ बच्चन सहित इन्हीं तमाम फिल्मी सितारों पर करोड़ों - करोड़ रूपया आयकर बकाया है । दान न भी करें, सरकार की बकाया राशि का सरकार को भुगतान करने से ही आज की आर्थिक स्थिति में बहुत उपयोगी होता है । इन फिल्मी सितारों द्वारा सरकार की बकाया राशि भुगतान की जानकारी उत्साहवर्धक होगी ।

[4] मात्र सुरेन्द्र जैन, बी. आर. जैन पर सरकार का करीब 200 करोड़ रूपया आयकर बकाया है । मजदूरों - कर्मचारियों के वेतन से एकत्रित 2 लाख रूपये की राशि जमा करने की आड़ में युद्ध स्थिति के आर्थिक संकट की घड़ी में भी सरकार के आयकर के बकाया 200 करोड़ रूपये दबाकर रखने वाले जैन बंधुओं के कृत्य को प्रशंसनीय कहेंगे या निन्दनीय ?

[5] सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि देश के विकास में जीवन-संचार करने वाली हृदय-स्थली के समान है । देश की इस हृदय स्थली पर विदेशी कंपनियों की घुसपैठ विश्व व्यापार संगठन के ट्रिम्स [TRIMS: Trade Related Investment measures] द्वारा कराई जा रही है । देश की व्यापक जनता इस आर्थिक गुलामी के खिलाफ आन्दोलन कर उद्योगों की रक्षा करना चाहती है, लेकिन शासक राजनैतिक वर्ग इस सबसे विनाशकारी विदेशी घुसपैठ के, का विरोध करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति हीन सिद्ध हो रहे हैं । जबकि हर किसी देश के औद्योगिक विकास की रक्षा उसके शासक राजनैतिक वर्ग द्वारा किया जाना 19 वीं. एवम् 20 वीं सदी का सबसे बड़ी ऐतिहासिक शिक्षा है । इक्कीसवी सदी की आगमन बेला में भी अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होते हुये भी अमरीकी कानून एवं हित को घोषित रूप से सर्वोच्च बता कर इसी ऐतिहासिक सिलसिले की पुष्टि की है । हमारे देश की हृदय-स्थली सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग उद्योग में विदेशी घुसपैठ के समक्ष आत्म समर्पण करने वाले राजनेताओं के कोष में चंदा जमा करने से हम उनके छद्म राष्ट्रवाद की छवि को पुष्ट करते हुये हम कहीं आत्म-समर्पणवादियों के गंभीर देशद्रोह पर पर्दा डालने के भागी तो नहीं बन रहे हैं ?

...3 पर

// 3 //

[6] क्या पूरे कारगिल, प्रकरण में सबसे गंभीर घुसपैठ क्षेत्र में अमेरिका की थानेदारी की स्थापना नहीं है ? यह अमेरिका जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य गढ़ है । एवं जिसकी दादागिरी में राहुल बजाज जैसे उद्योगपति को भी नौकर जैसे महसूस होता है ।

[7] कारगिल युद्ध में मरने वाले जवान चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के मजदूर और किसान के बेटे ही तो हैं । भारत के या पाकिस्तान के किसी भी राजनेता या उद्योगपति का बेटा, भाई, भतीजा युद्ध में नहीं मरा है । यदि आपकी जानकारी में कोई है, तो बताईयेगा ।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही के तकाजे के तहत इन मुद्दों पर साफ तौर की जानकारियों एवं संतुष्टि के होने पर हमारी यूनियन के श्रमिक एक नहीं, बल्कि दो-दो दिन का वेतन देने के लिए तत्पर हैं ।

// धन्यवाद //

दिनांक : 21/08/99

भवदीय
[signature]
[अनूप सिंह]
महामंत्री

The Associated Cement Co. Ltd
RECEIVED
21 AUG 1999
Jamul Cement Works

प्रशासन से बुद्धिजीवियों की अपील

प्रति,

श्री विवेक ढांड,
जिलाधीश, दुर्ग जिला,
दुर्ग (म.प्र.).

महोदय,

प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ द्वारा श्री शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में चल रहे श्रमिक आंदोलन ने बीस वर्षों से दमित मजदूरों की आकांक्षाओं को पुनर्जीवित किया है, उनमें आत्म- सम्मान जगाया है. जीवन के प्रति एक नई आशा का संचार किया है.

नियोगी के आतंक का हौव्वा खड़ा करने वालों का खोखलापन फिर एक बार १५ नवंबर ९० की शांतिपूर्ण हड़ताल ने सिद्ध कर दिया है. एक नये जोश के साथ, किंतु पूरी तरह अनुशासित रहकर, आंदोलनरत हड़ताली मजदूरों ने नारे लगाये. गीत गाये पर कारखानों के दरवाजों पर किसी को रोकने की कोई कोशिश नही की. इससे पूर्व इनके कई साथियों पर हमले भी हुए जिनमें दो तो प्राणघातक थे पर इस संगठन ने सब कुछ सहकर उत्तेजित न होना स्वीकार किया, कभी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नही की. इस श्रमिक आंदोलन की जड़ों की गहराई इन ३१३ साथियों की गिरफ्तारी के बावजूद सफल संचालन ने सिद्ध कर दी है.

विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की समस्याओं का यदि यथा- समय निदान कर दिया जावे तो आंदोलन की स्थिति से सदैव बचा जा सकता है. इसी सदाशय से हमारी सरकार ने श्रम- विभाग बनाया. श्रम- विभाग द्वारा श्रमिक एवं प्रबंधन पक्ष को चर्चा द्वारा विवाद के समापन हेतु नियत तिथियों पर आमंत्रित किया गया जिसमें प्रबंधन/मालिक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण चर्चा का न होना और मजदूरों में असंतोष अधिक बढ़ना स्वाभाविक है.

क्या उद्योगपतियों पर भारतीय कानून लागू नहीं होते ?

क्या पूंजीपति वर्ग भारत के संविधान से भी बड़ी शक्ति रखता है?

यदि नही, तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि वह तत्काल हस्तक्षेप कर संबंधित उद्योगों के मालिकों/ प्रबंधकों पर विधिवत व्यवहार करने हेतु दबाव डालें. मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करना दोनों पक्षों की समझदारी और तर्क शक्ति तथा श्रम एवं औद्योगिक कानून की संहिता द्वारा निर्धारित होगा, पर लोकतंत्र पर आस्था रखकर हम यह कदापि बर्दाश्त नही कर सकते कि कोई उद्योगपति स्वयं को संविधान से भी अधिक ताकतवर मानने का दुस्साहस करे और कानून की परिधि में रहकर हो रहे जनतांत्रिक आंदोलन को कानून- व्यवस्था की समस्या बनते तक नजरअंदाज कर, उसे तानाशाही ढंग से कुचला जावे.

इतिहास स्वयं इसका साक्षी है कि (संयोगवश) भाजपा के शासनकाल में मजदूर आंदोलनों को कुचलने हेतु दल्ली- राजहरा, बैलाडीला एवं हाल ही में अभनपुर में श्रमिक आंदोलनों की अवहेलना के कुत्सित प्रयास किये गये. गोलियां चलाई गई, श्रमिकों को मारा गया, पर आंदोलन दबाया न जा सका. इसी शृंखला में राजनांदगांव के बी.एन.सी. मिल का श्रमिक आंदोलन भी एक साक्षी है जहां सन् १९२०, १९३६, १९४८ और १९८४ में भी गोलियां चलाई गई पर आंदोलन न मारा जा सका. किसी भी आंदोलन को दीवारें बना कर रोकना या गोली चलाकर मारना यदि संभव होता तो अंग्रेजों ने हमारी आजादी के आंदोलन को १८५७ में ही दफना दिया होता. पर ऐसा न हुआ.

अस्तु! हमारा विवेकशील प्रशासन से निवेदन है कि अपने प्रशासकीय प्रभाव का उपयोग करके एवं व्यक्तिगत रुचि लेकर इस समस्या के विधिवत निराकरण हेतु अविलंब हस्तक्षेप करे ताकि संविधान की रक्षा के दायित्व का निर्वाह हो.

-इसी सदाशय के साथ,

मजदूरों का पसीना -ही नहीं,
खून भी बहाया है उद्योग नगरी के शोषकों ने

भिलाई इस्पात संयंत्र बनने से लेकर आज तक की कुल औद्योगिक प्रगति में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ठेका श्रमिकों की ही रही है । पर जब कभी भी ठेका मजदूरों ने संगठित होकर शोषण के विरूद्ध आवाज उठाना चाहा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया । **शोषण के इसी तांडव का शिकार हुए भुनूराम और राधेश्याम । कौन जिम्मेदार है इस अमानवीय हत्या का ?**

जबसे लालहरा झंडा लेकर दुर्ग-भिलाई के ठेका मजदूर संगठित हुए इस क्षेत्र के शोषकों की नींद हराम हो गयी । क्योंकि शोषण की चक्की का चलना कठिन महसूस होने लगा । शोषण के चक्र को चलाते रहने के लिये 26 मार्च की हड़ताल तोड़ना जरूरी हो गया और इसी लिये उन्होंने एक दुर्दान्त योजना बनायी ।

साथियो,

कुछ दिनों पहले लाल-हरा यूनियन के कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री भुनूराम को ड्यूटी से लौटते समय ट्रक से कुचलकर मार डाला गया । पर मजदूरों के संगठन को तोड़ने की यह कोशिश असफल हो गयी । संघर्ष की राह पर मजदूर चलते रहे । 24 मार्च को ए.सी.सी. में कोयला अनलोडिंग करते हुए हेल्पर राधेश्याम कोयले के ढ़ेर में दब गये, यह तो दुर्घटना थी पर उनके मृत शरीर को पीस कर सीमेन्ट बना देने की साजिश क्यों ? ताकि उसकी मौत का हर्जाना मालिकों को न देना पड़े । दुर्ग-भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ रहे नव-धनाड्यों की अमानवीयता का यह एक उदाहरण है । कानून की गिरफ्त से बचने के लिये प्रजातंत्र के दावेदार ये नवधनाड्य कुछ भी कर सकते हैं । सभ्यता का ढोंग करने वाले ये मालिक, मजदूरों की 'उफ' भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ।

क्या मजदूरों का संगठन बनाना जुर्म है ? क्या शाति पूर्ण आंदोलन द्वारा जायज मांग करना भी जुर्म है ? फिर 26 मार्च की प्रस्तावित हड़ताल तोड़ने की खूनी योजना ए.सी.सी. मैनेजमेंट ने क्यों बनायी ?

पंजीकृत मजदूर संगठनों ने 14 दिन पहले नोटिस देकर 26 मार्च से अपनी मांगों के लिये हड़ताल करने की मानसिकता बनायी थी । लाल-हरा झंडे की बढ़ती लोकप्रियता से डर कर, मजदूरों के शातिप्रिय आंदोलन से घबरा कर परिवहन मालिकों ने मजदूर नेता श्री शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर देने की गीदड़ धमकी दी । पर इतने से वे संतुष्ट नहीं हुए ।

परिवहन मालिकों द्वारा संगठित होकर मांग करना उनके मालिकों द्वारा अपराध माना गया । अतः 26 मार्च की हड़ताल से निपटने के लिये ए.सी.सी. मैनेजमेंट ने आंदोलनरत मजदूरों के तोड़ने के लिए जामुल थाने में एक मीटिंग की । यह अफवाह भी फैंलायी गयी कि हड़ताल के दिन यूनियन के मजदूरों द्वारा लाठी- भालों से हमला किया जावेगा । ऐसी ही अफवाह फैंलाकर और बाद में बम फोड़कर सिम्पलेक्स वालों ने पांच साल पहले मजदूरों की हड़ताल तोड़ने का दुस्साहस किया था । मजदूरों से लड़ने के लिये ए.सी.सी. सिम्पलेक्स और भिलाई इस्पात संयंत्र का मैनेजमेंट एक जुट हो जाता है । इन्हें असामाजिक तत्वों, गुंडों अपराधियों को जुटाने में न तो झिझक होती है न समय लगता है ।

भिलाई इस्पात के पैसों पर पलने वाले अहिवारा के बदमाश...... भैंसवाला आदि 112 लोगों को 26 मार्च की सुबह से हड़ताल तोड़ने की जिम्मेदारी दी गयी थी । हर 10 मजदूर के पीछे एक गुंडा हथियार बंद सभी गेटों पर तैनात किया गया था । भला मजदूर कैसे जान पाते कि मजदूरों की भीड़ में अपराधी कौन है ? अगर 26 मार्च की हड़ताल स्थगित न होती तो यही असामाजिक तत्व मजदूरों का खून बहाकर मजदूर आंदोलन को कुचलने का अपना "पवित्र धर्म" निभाते ।

ए.सी.सी., बी.के., बीको, सिम्पलेक्स और भिलाई इस्पात के प्रबंधकों की नींद हराम हो गयी है क्योंकि छत्तीसगढ़ के एकमात्र श्रमिक संगठन ने यहां अपना लाल हरा झंडा गाड़ दिया है । आज हर मजदूर पूछता है कि **भुनूराम की हत्या किसने की ? और राधेश्याम को पीसकर राख बनाने की योजना किसकी थी ?**

आज हर जागरूक मजदूर परिस्थिति पर निगाह रखा हुआ है । हर गुंडे और असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने की जिम्मेदारी श्रमिक खुद सम्हाल रहे हैं । अब दादागिरी के बल पर मजदूरों की जायज मांगों को दबाया नहीं जा सकता ।

> विश्वस्थ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राधेश्याम के दुर्घटना ग्रस्त शरीर को रफा-दफा करने के सिलसिले में कुट्टी के भाई रवि को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है । मजदूरों को पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक निष्पक्ष जांच के निष्कर्ष की अपेक्षा और प्रतीक्षा है ।

सरफरोशी की तमन्ना लेकर भिलाई दुर्ग के मजदूर यह सवाल कर रहे हैं कि

- ✪ स्थायी मजदूरों का विभागीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है ? ✪ मजदूरों की सुरक्षा के बंदोबस्त में ढ़िलाई क्यों ?
- ✪ ठेकेदारी के नाम पर बी.के., बीको, सिम्पलेक्स एवम् ट्रक मालिक कब तक मजदूरों पर अत्याचार करते रहेंगे ?

आज हर मजदूर इस इलाके में आतंक फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के आतंक को हमेशा के लिये खत्म करने का फैसला कर चुका है । हजारों-हजार मजदूर एक लाल हरे झंडे के साथ सड़क पर आये है, और आते जा रहे हैं..... शातिपूर्ण आंदोलन द्वारा आतंक को हमेशा के लिये समाप्त करने के संकल्प के साथ

हम चाहते है कि समस्याओं का समाधान चर्चा से हो । हम शातिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर हैं अहिंसा में हमारी ताकत है ।

आओ, मेहनतकशो आओ, मजदूरों एक साथ आओ, रूको नही ...... झुको नहीं, बढ़े चलो .... बढ़े चलो ।

लालहरा हरा झंडा जिंदाबाद । शहीद साथी अमर रहे ।

जनक लाल ठाकुर
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

पूनम वाघमकर
प्रगतिशील ट्रांसपोर्ट
श्रमिक संघ (दुर्ग)

एन.आर. घोषाल
छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ
भिलाई

भिलाई के उद्योगपति कब तक श्रम कानूनों को अंगूठा दिखाते रहेंगे?

मजदूर साथी संघर्ष के लिये तैयार हो जाओ

दिनांक १५/११/९० गुरूवार ए.सी.सी. से लेकर इंडस्ट्रियल इस्टेट के सभी उद्योगों के मजदूर हड़ताल करेंगे!

उरला और टेडेसरा के मजदूर साथी एकता बनाकर आगे बढ़ो!!

दोस्तों,

देश में आज राजनैतिक पार्टियों के गैर जिम्मेदार नेताओं ने देश की मूल समस्याओं-बेरोजगारी, मंहगाई, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, गरीबों पर अत्याचार, कमजोरों का दमन आदि को ओझल करने के लिये ऐसे मुद्दों को खड़ा कर रखा है जिनका आम-जीवन की समस्याओं से कोई ताल्लुक नही है.

यह दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट हो चुका है कि देश की वामपंथी पार्टियां-जैसे सी.पी.आई., सी.पी.एम. आदि भी पूंजीपतियों की दलाली में कम माहिर नही हैं. वामपंथियों का वैचारिक दिवालियापन और मजदूर वर्ग के प्रतिनिधित्व के दावें का खोखलापन मात्र सम्बल चक्रवर्ती को देखने से ही मालूम हो जाता है, जो मालिकों की सेवा में मजदूरों के खून से होली खेलने की साजिश साकार करने के लिये दिन-रात जुटा हुआ है. जब भिलाई के ''तथा कथित'' गुंडे, मजदूरों से टकराने से इंकार कर रहे हैं तो यह ग्रामीण बेरोजगारों को भिलाई इस्पात संयंत्र में रोजगार दिलाने के लालच में बुला रहा है. यह सब धोखेबाजी और साजिश, प्रशासन की आंखों के सामने, दिन-दहाड़े हो रही है.

भिलाई इस्पात संयंत्र का मैनेजमेंट, अपने समस्त साधनो के जरिये लाल हरा झन्डा यूनियन को भिलाई क्षेत्र में रोकने में लगा हुआ है. इस्पात संयंत्र के पर्सनल विभाग के अधिकारी बी.एस.पी. की नौकरी छोड़कर अपनी सेवाएँ बी.के., बी.को., सिम्पलेक्स, केडिया को न्यौछावर कर रहे हैं. (बाजपेई, रमाशंकर तिवारी, एस.के. वर्मा आदि). भिलाई इस्पात संयंत्र के अफसरान, भिलाई की एन्सीलरी इन्डस्ट्रीज को काम न देकर कलकत्ता, दिल्ली की बड़ी-बड़ी कंपनियों से कमीशन ऐठतें हैं, यह सर्वविदित है..।

इससे क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है. इस्पात संयंत्र के अधिकारी बाहरी पार्टी को काम देते हैं और अपने दलालों को भेंट करते हैं, भिलाई के उद्योगपतियों को. बी.एस.पी. ने अभी-अभी पिछली दलाली की कीमत स्वरूप ५-६ लाख रूपये जार्ज कुरीयन को दिया था. अब कुरीयन ने अपनी बीवी, साला और भतीजों की बी.एस.पी. में नौकरी बोनस के रूप में प्राप्त की है. इस बार बी.एस.पी. मैनेजमेन्ट ने उसे सिम्प्लेक्स का उद्धार करने के लिये भेजा है. दल्ली राजहरा के मजदूर इन दलालों को चमड़े का मेडल भेंट कर चुकें हैं. अब भिलाई के मजदूर इन्हें चमचागिरी की सर्वोच्चट्राफी से सम्मानित करेंगे. सिर्फ समय का इंतजार हैं.

''हाथ तुम्हारे हैं, पत्थर उनका है, ताकत तुम्हारी है, दिमाग उनका है,
इधर तुम भले ही सीना तानकर दादागिरी दिखाते हो
गुरूजनों को गालियों का अशिष्ट तोहफा भेंट करते हो,
मगर राजनीति की शतरंज में तुम्हारी हैसियत,
फकत एक प्यादे की है.''

भिलाई के मजदूर इस बार जाग चुके हैं. ''एकता और भाई चारा'' का पवित्र मंत्र समूची मजदूर बस्तियों में गूंज रहा है. जाति, धर्म, प्रान्त, भाषा के भेद का इस बस्ती में अब कोई स्थान नही है. दुनिया की कोई भी ताकत मजदूरों की एकता को नही तोड़ सकती. उद्योगपतियों को मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने का मजा चखा दिया जायेगा.

''हम भगतसिंह का अंदाज बता सकते हैं.
और अशफाक के तेवर भी दिखा सकते हैं.
मादरे हिंद की लाज बचाने के लिये
हम, कारखानों से निकल सड़क पर भी उतर सकते हैं.''

दिनांक १५ नवंबर गुरूवार की हड़ताल को कामयाब करो.

लाल हरा झण्डा जिन्दाबाद
प्रगतिशील इन्जीनियरिंग श्रमिक संघ जिंदाबाद
छत्तीसगढ़ केमीकल मिल मजदूर संघ जिंदाबाद
छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ ज़िन्दाबाद
शहीद साथी अमर रहें.

रामबिलास मंडल भिलाई वायर्स	**नीलरतन घोषाल** संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ, भिलाई	**रवीन्द्र शुक्ला** केडिया डिस्टीलरी लि. 11/7/90	**सुदामा प्रसाद** सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग	**मथुरा प्रसाद** सिम्पलेक्स कॉस्टिंग
राजाराम सिम्पलेक्स उद्योग	**श्रीनिवास** बी.ई.सी.	**शंकरदास माणिकपुरी** बी.के. सर्जिकल	**रामगोपाल** भिलाई	**जनकलाल ठाकुर** अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा.

बी.के. और बी.एस.पी. के सेवक संबल और एटक को कुत्त। कहने पर कुत्ते का अपमान होता है, न कि उनका !

साथियों !

कुछ दिन पहले सी.एम एस.एस के महामंत्री श्री छबीलालजी ने एक पर्चा निकाल दिया था एवं याद दिलाया था कि संबल ने अपने भाषण में कहा था कि '२४ मई तक यदि विभागीकरण नहीं हुआ तो मेरे(सम्बल)के नाम पर कुत्ता पाल लेना'। २४ मई को विभागीकरण नहीं हुआ और राजहरा के कुछ चंचल लड़को ने सारे खुजली वाले कुत्तों को 'सबल दादा' नामक बिल्ला लगा दिया था। चिखलाकसा में तो कुछ ग्रामीणों ने कुछ गधों को पकड़ कर 'संबल' का नेम प्लेट लगा दिया था। इस पर हमने काफी मनन किया। मुझे कुत्ते एवं गदहों द्वारा संबल का बिल्ला पहन का घुमना पसन्द नहीं आया। बेचारे खुजली वाले कुत्ते होटलों के, या सड़कों के इर्द-गिर्द घुमते रहते हैं। किसी का काई नुकसान नहीं करत हैं। एक-आध भजिया मिलने पर दुम हिलाते रहते हैं परन्तु संबल या लाल झंडा के सारे नेता लोग बी.के. के गोल गड्ढा में काम करने वाल मजदूरों से प्रतिदिन ६) रुपया कटवाकर माला-माल हो रहे हैं। सीधे-साधे गांव वालों से सौ रुपये से पांच सौ रुपये एव १००० रुपये तक नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठ लिये। १२) रुपया से ज्यादा, जब राहत कार्य में भी मिलता था, उस समय राजहरा के पूरे माहौल को बिगाड़ कर मार-पीट और हिन्सा की राजनीति शुरु कर किसी भी गांव वालों को लगातार एक महीना तक रोजगार नहीं दिलाया।

अब तक १०,००० ग्रामीण बेरोजगारों से कम से कम सौ रुपया लेकर दस लाख रुपया सीधा लूट लिया है। अगर ये खुजली वाले कुत्ते होते तो इन ग्रामीणों या बेरोजगारों के इर्द-गिर्द दुम हिलाते या उनकी सेवा करते ग्रामीणों से पैसा लेने वालेएवं ६ रुपया रोजाना वेतन कटवाने वाले एटक वालो ने महिला मजदूरों को बलात्कार का शिकार बनाया। ये तो उनकी जनता के प्रति वफादारी है। कुत्ता इतना बेइमान नहीं होता।

अब तो संबल का धंधा ही ऐसा बन गया है कि हर तीसरे दिन दस हजार नोटों का बन्डल लाकर पता नहीं कहां खर्च करता है। टी.के. राय बहुत खुश है क्योंकि सी.के. के देव चलते कुछ मिलता जुलता नहीं था। अब काफी मिलने लगा है।

कुछ दिन तक खूब माईक फूंका और विभागीयकरण का दम भरते रहे अब एक परचा निकालकर कह रहा है कि 'विभागीकरण के बाद ग्रे ज्यूटी लो' ठकेदारों का दलाली करते-करते स्थानकाल भी ये भूल जात हैं। नंदनी मे सोसायटी के समय का ग्रे ज्यूटी का पसा क्यों नहीं दिलाया। हिर्री माइन्स के भी ग्रे ज्यूटी का नाम याद नहीं आया था। अब ये चले दल्ली-राजहरा के मजदूरों की ग्रे ज्यूटी का पसा हजम करने। १९७२ से ८९ तक १७ साल में एक मजदूर का ग्रे ज्यूटी का कितना हक बनता है। एक-एक मजदूरों का ९-१० हजार रुपया सबल के लिये कुछ भी नहीं, क्योंकि बी.के. कम्पनी के पास गांव वालों को भेज कर दुनिया को बुध्दु समझ रहा है। गरीब मेहनतकश के १९ रुपया से ६ रुपया काटकर १३ रुपया रोजी दिलाता है। मजदूर पैसा की मांग करते हैं तो उन्हे सिर्फ आश्वासन देकर ढाढ़स बंधवाता हैं।

अब कहते हैं कि '५८ साल की बात' - इसका मतलब टी के. राय समारुलाल, मिश्रा और उनके सब पंगतो को डहाके साहब के समान एक्सटन्शन मिलने वाला है। मारपीट कर मैनेजमेंट की छटनी करने का मौका देने वाले संबल का महान नेतृत्व में अब य बताया जा रहा है कि आरीडोंगरी में भी मशीनीकरण, सी.एम एस एस. ने ही कराया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एटक के कुत्त ठेकेदार आइदान के नमक को भी इतनी जल्दी भूल जायगें।

उनको विभागीयकरण की मांग अब बदल गई है। अभी जूता निर्माण का कारखाना के लिये मांग करा है। ऐसा लगता है कि २५ तारीख के जूतों में कुछ कमी रह गई है। संबल ऐसा ही भौंकता रहेगा। ऐसी भौंकने की आदत के कारण ही भिलाई के मजदूरों ने इन्हें कई बार जूतों से स्वागत किया है। अब ये राजहरा को अत्यन्त सुरक्षित समझ कर यहां भौंकने की कार्यवाही शुरु दिया है।

सी.एम एस एस. के महामंत्री श्री छबीलाल ने इसके भौंकने की आदत के कारण उसी के भाषण का कुछ अंश छाप दिया था। परंतु ये संबल सीधे-साधे खुजली वाला घुमने वाला कुता नहीं है, जो होटलों का एक आध जूठा भजिया खाकर दुम हिलाता। ये बी के. और बी एस पी मैनेजमेंट के सहयोग से निकला हुआ एलसेशियन कुत्ता है इसलिये इस कुत्ता को सम्हालने का काम बी के. और मैनेजमेंट का है।

हम पुराना बाजार के मजदूरों की ओर से मैनेजमेंट और बी. के कंपनी को चेतावनी देते हैं कि ये अपने कुत्ते को बेल्ट लगाकर अपने महल में ही बांध कर रखें। अगर फिर संबल व एटक के कोई भी नेता भोंकने का काम करेगा और मजदूर बस्ती मे अशांति फैलायेगा, कसर में, मानपुर रोड में, नया बाजार में या ट्यूबलर शेड में मारपीट करायेगा या पागलपन शुरु करायेगा तो हम यह सोचन पर मजबूर हो जाएंगे कि यह कुत्ता पगला गया है। और इसका इलाज भी जनता को मालूम है।

त्रिवेनीसिंह

दिनांक ११-७-८९ — पुराना बाजार, दल्लीराजहरा

विजय प्रिंटिंग प्रेस, बालोद

लाखों नवयुवक आओ,

रुको नहीं झुको नहीं, बढ़ते चले आओ ।

२ अक्टूबर १९९० दिन मंगलवार नवयुवक, किसान-मजदूर सम्मेलन में भाग लेने—

भिलाई चलो,

साथियों,

हमारे देश को आजादी मिले ४३ साल बीत चुका है । देश के विकास के लिये लाखों देशवासी कुर्बानी दिये थे, उनका सपना आज भी पूरा नहीं हो सका ।

जनता का जीवन कमरतोड़ मंहगाई से बेहाल होता जा रहा है छत्तीसगढ़ से प्रतिवर्ष ५ लाख पुरुष-महिला देश को छोड़कर परदेश पलायन करते है । खेती वर्षा पर निर्भर है । देश की करोड़ों जनता मर-मर कर जी रहे है और प्रतिदिन दुखी जीवन और अपमान का घूंट पी रहे है ।

अगर हम कहें—— जब वक्त पड़ा गुलिस्तां को खून हमने दिया ।

अब बहार आई तो कहते है तुम्हें काम नहीं

आज बेड़िया पहने है असिराने वतन, फर्क इतना है कि इससे इंकार नहीं ।।

बेरोजगारी के जंजीर में बंधा हुआ लाखों नवयुवक कब और कैसे जंजीर तोड़ सकेगें ?

संविधान में काम के अधिकार का मांग किया गया, परन्तु नई सरकार आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया । कल कारखानों में मशीनीकरण का बोलबाला है जिससे दिन प्रतिदिन रोजगार की गुंजाइश कम होता जा रहा है । उद्योगों में अगर रोजगार नही मिलेगा तो कहां मिलेगा ?

छत्तीसगढ़ के बेरोजगार मजदूर, बंधुआ मजदूर, पुरुष एवं महिला अब इस बेरोजगारी के जंजीर को तोडना चाहते है । २ अक्टूबर को भिलाई के महासम्मेलन में इस जंजीर को तोड़ने का निर्णय लिया जाएगा ।

" जल-जंगल और जमीन हो जनता के अधीन "

छत्तीसगढ़ के सारे नदियों के पानी से भिलाई का प्यास बुझाया जा रहा है । जंगल पर अधिकार आरा मिल वालों एवं ठेकादारों का है, जो लकड़ी बेचकर अरबों रुपया कमाते जा रहे है और जंगल का सत्यानाश कर रहे है, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ रहा है । जंगल के पास के गांव के आदिवासियों को निस्तार के लिये भी लकड़ी नहीं मिलती है । हर वक्त जंगल विभाग के अधिकारी के आतंक से ग्रामवासी यहां तक कि उनके मुर्गी तक भी परेशान है इसलिए, अब वक्त आया है निर्णायक विरोध के प्रदर्शन करने का ।

अब वक्त आया है, जो जमीन को जोते बोये वह जमीन का मालिक होवे ।

वक्त की पुकार है, मिलके चलो ।

किसान मजदूर, नवयुवक, मिलके चलो ।

२ अक्टूबर को भिलाई चलो ।

मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो ।

विनीत—

जनकलाल ठाकुर (अध्यक्ष) — छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

एन. आर घोषाल (महामंत्री) — छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ, भिलाई

रेनु एक्का — छत्तीसगढ़ महिला जागृति संगठन, रायपुर

रत्नेश्वरनाथ — एकता परिषद, मध्यप्रदेश

प्रेमनारायण वर्मा (अध्यक्ष)– राजनांदगांव कपड़ा मजदूर संघ, राज.

भरतलाल पंथ – एकता परिषद, बिलासपुर

सीताराम सोनवानी – एकता परिषद, रायपुर

जगरामसिंह – एकता परिषद सरगुजा

निल कुमार – राष्ट्रीय लोक समिति – शाखा – सरगुजा

सिलेस्युस – एकता परिषद, रायगढ़

चार्ल्स गाडिया – छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ, राजा देवरी

गौतम बन्धोपाध्याय – एकता परिषद, छत्तीसगढ़ ईकाई

भागाबाई, घसनीनबाई, दुर्गाबाई – महिला मुक्ति मोर्चा,

अमृतलाल जोशी – छत्तीसगढ़ युवा समाज, आरंग

वृन्दावन नंद – बंधुआ मुक्ति मोर्चा, रायपुर

भीमराज बागड़े– केमिकल्स मजदूर संघ, राजनांदगांव

राजकुमार तिवारी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील युवा संघ, (हिर्री माइंस) भैयालाल दादरे (लांजी), भागाबाई (लांजी), चन्द्रवती (बिलासपुर), इन्दूनेताम (राजनांदगांव), जयकिसन प्रधान (पिथौरा), कालदीन साहू (दुर्ग), गोकरण (दुर्ग), जगदीश सिंह ठाकुर (गरियाबंद), सुमित्राबाई (गरियाबंद), लजरुमिंज (मैनपाट), वेदराय (उदयपुर), कुसिया कुजुर (अम्बिकापुर), अमरनाथ सिंह (सूरजपुर), श्याम बहादुर नम्र (अनूपपुर), मांमिनबाई (केशकाल), रामेश्वर (बस्तर), सुधूराम कुंजाम (चारामा), ताल सिंह ठाकुर (गुन्डरदेही), मनोरंजन व्यापारी (पंखाजूर), अमरीका बाई (बिलासपुर), सीतादेवी वर्मा (आरंग), पोखनलाल मंडावी (खैरागढ़), रैनसिंह कोड़ा (भानुप्रतापपुर) मन्नूभाई (अंटागढ़), गीताराम ध्रुव (हिर्री माइंस), अमरबाई दल्लीराजहरा, लीलाबाई राजनांदगांव, आशा साहू रायपुर, चमरु उदयपुर सरगुजा, पंदाराबाई कुसुमकसा, लोचन प्रसाद नर्मदा, अर्जून जूंगेरा, देवकीबाई कसडोल, मेघदास वैष्णव ग्लूकोज, राजनांदगांव।

बजाज प्रिन्टर्स, दल्लीराजहरा

छोटी-छोटी नदियां मिलकर महानदी बनती है
अनेक कल--कारखानों के मजदूर मिलकर महातीर्थ बनता है
एकता की पुकार लेकर
आओ । हम, नया भिलाई बनायें ।

साथियों,

भिलाई के पूरे उद्योगों में खलबली मची हुई हैं और सिम्पलेक्स बी. ई. सी., केडिया, बी. के. बी. को, भिलाई वायर्स, जनरल फेब्रीकेटर्स, गोलछा, केमिकन, ज्ञान रिरोलींग मिल्स जसत्रंगल स्टील इन्टरप्राईजेज भिलाई आक्सीलरी, इन्डस्ट्रीज विश्व विशाल, पूज स्टार ए. सी. सी. सभी उद्योगों में मजदूर हिम्मत के साथ लाल-हरा झंडा अपनाकर अधिकार की बात कर रहे है।

भिलाई के मेहनतकश मजदूरों ने एक के लिए सब, सबके लिए एक यह विचार के तहत मजदूरों में अटूट एकता कायम हो सकता हैं, यह पहले कभी नहीं सोचा था ।

आज भिलाई के उद्योगपतियों की धड़कन बढ़ चुकी है । वे चमचों को इकट्ठा कर रहे हैं, बेईमानों को हराम का खाना खाने की प्रर्याप्त सुविधा प्रदान कर रहे हैं । कुल मिलाकर मालिक फिकर में पड़ें है । उन्हें मालूम हो गया है कि इस एकता के स मने उनकी शोषण की व्यवस्था नहीं चलेगी ।

मजदूर एकता बनाकर, एकता का गाना गाते हुए, एकता का हथियार से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये कदम--कदम आगे बढ़ रहे है ।

मजदूर नारा लगा रहे है,
हमें न्याय चाहिये,
हमें मुक्ति चाहिये,
हमें इज्जत चाहिये,
हमें निश्चित भविष्य चाहिये ।

आईये, विश्वकर्मा पूजा के पावन दिवस पर एकता का बांध बनाकर नये भिलाई का निर्माण करें ।

मजदूर एकता जिंदाबाद
लाल-हरा झंडा जिंदाबाद
शहीद साथी अमर रहे ।

पूनम बामनकर	**जनकलाल ठाकुर**	**एन.आर. घोषाल**
प्रगतिशील ट्रान्सपोर्ट श्रमिक संघ	अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	महामंत्री इस्पात श्रमिक संघ, भिलाई

दिनांक १७-९-९० दिन सोमवार को इंडस्ट्रीयल स्टेट मैदान में (एम.पी.ई.बी हाउसिंग बोर्ड के पास) आमसभा में भाग लीजिए । हर कारखाना से जुलुस लेकर सभा स्थल पर आना है । **समय -- दोपहर १ बजे**

बजाज प्रिन्टर्स, राजहरा

★ तथ्यों को झुठलाना देशद्रोहिता है ।

★ मजदूरों के जनवादी अधिकारों पर हमला करना असंवैधानिक है ॥

★ तानाशाही ताकतों से भी ए.सी.सी. प्रबंधन जनवादी अधिकारों को कुचल न पायेगा ।।।

ए. सी. सी. को प्रगतिशील सीमेन्ट श्रमिक संघ के तरफ से एक मौका और

साथियों,

प्रगतिशील सीमेन्ट श्रमिक संघ एवं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लाल-हरे झडें के नीचे काम करने वाली सभी यूनियनें मजदूर हितैषी होने के साथ ही साथ उत्पादकता की भी हितैषी है । हम नहीं चाहते कि प्रबंधन की हर गल्ती या लेट लतीफी के लिये उत्पादन बंद हो । इसी नीयत से हम ए.सी.सी. को एक मौका फिर दे रहे हैं कि वह अपनी हठधर्मिता छोड़कर विवेकशील बने।

भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में ए.सी.सी ने जामुल सीमेंन्ट संयत्र यहां की सस्ती स्लैग, सहज मजदूरों की उपलब्धता तथा कुल उत्पादन मूल्य मे बचत को देखकर ही लगाया था। अपने २६ वर्षो के जीवन मे ए.सी.सी जामुल ने ए.सी.सी. को लगातार लाभ दिया है वास्तविकता यह है कि जामुल एवं गागल (हिमाचल प्रदेश) की इकाईयों मे होने वाले लाभ से ही कई वर्षो तक ए.सी.सी. साम्राज्य के कई अपाहिज कारखानो की घाटा पूर्ति होती रही ।

बीच में कई वर्षो तक ए.सी.सी. समूह घाटे में चली पर तब ए.सी.सी. ने एकीकृत घाटे को ही आधार मानकर बोनस की न्यूनतम दरें दी । इस वर्ष न सिर्फ जामुल कारखाना बल्कि पूरा ए.सी.सी. समूह १७.७९ करोड़ के शुद्ध लाभ पर चल रहा है। तब भी मात्र बोनस की मांग से बचने के लिए ए.सी.सी. प्रबंधन स्वयं अपने कारखाने की दक्षता अपनी प्रबन्धन क्षमता तथा मजदूरों की असफलता के विरुद्ध एक घिनौना प्रचार कर रहा है यह कतई निंदनीय है ।

किसी भी उद्योग की स्थिति को मापने के कुछ विशिष्ट पैमाने हैं जो सर्वमान्य हैं जैसे कि उद्योग में लगी पूंजी, उत्पादन (बिक्री) लाभ तथा शेयर बाजार में उसकी कीमत । ए.सी.सी. की उत्पादकता एवं बिक्री से होने वाले लाभ की पिछले एक वर्ष मे हुई वृद्धि ने अखिल भारतीय स्तर पर उसे चर्चा का बिषय बनाया और इसी कारण उसके शेयर की कीमत में लगातार वृद्धि हुई साख और लगातार बढ़ते लाभ का ही परिणाम है। साल भर पहले जिस ए.सी.सी. की साख १५३.४४ करोड़ की थी जबकि उसके पास अभी की तुलना में चार कारखाने अधिक थे। अब पिछले वर्ष की तुलना में उसकी साख ८८२.५६ करोड़ बढ़कर रु. १०३६ हो गई है ।

२८ अगस्त के बिजनेस, इंडिया ने ए.सी.सी. समूह का जिक्र करके लिखा था कि स्पष्टत: ए.सी.सी. को लाभ देने में जामुल और गागल (हिमाचल प्रदेश) का ही प्रमुख स्थान है। भारत के आर्थिक व्यवसायिक हलचल में किसी भी कम्पनी कारखाने की लाभ अर्जन की क्षमता का सर्वमान्य सूचक उसके शेयर की कीमत होती है । हर निवेशकर्ता अपनी पूंजी अधिक लाभ अर्जन करने वाली कम्पनी में ही लगाता है और शेयरों पर दिया जाने वाला लाभांश कम्पनी को हुए लाभ से ही दिया जाता है । लाभ जर्जन के आधार पर ही डेविडेड की भी गणना होती है । १९८९-९० में ए.सी.सी. द्वारा दिया गया १५ प्रतिशत डिविडेड रु. ३१.८० प्रति शेयर का लाभांश तथा १२ सितम्बर ८९ को रु. २७४ की कीमत के शेयरों का १२ सितम्बर ९० को रु. १८५० की ऊंची छलांग लगाकर वर्तमान में रु. ३००० के आसपास स्थिर होना स्वयं ए.सी.सी. के दिन प्रतिदिन बढ़ती कमाई और प्रतिष्ठा का द्योतक है और इस वृद्धि का श्रेय इसके कारखानों के कामगारों को जाता है ।

पिछले वर्ष के लगभग ६ करोड़ के घाटे से ऊपर १७.७४ करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जन करने का श्रेय जामुल और गागल (हिमाचल प्रदेश) इकाईयों को ही है ।

यह भी सर्वमान्य सत्य है कि जामुल और गागल की इकाईयों मे उत्पादन मूल्य जितना कम है उस कीमत पर सीमेण्ट उत्पादन कहीं भी अन्यत्र संभव नहीं क्योंकि स्थानीय स्लैग स्वयं कम कीमत का कच्चा माल होने के साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र से माल ढोने पर लगने वाला भाड़ा भी न्यूनतम है । इसी तरह गागल में उपयोग आने वाला कच्चा माल फ्लाई ऐस वहां की ताप विद्युत इकाईयों से आता है ।

(क्र. पृ. उ.)

आँकड़ों के आयने में ए. सी. सी.

विषय	भारत में स्थान	१९८९-९० करोड़ रु.	१९८८ ८९ करोड़ रु.	साल भर में हुई करोड़ रु.	बढ़ोत्तरी प्रतिशत
बिक्री	१०	९९०.९८	९००.००	९०.९८	१०%
लाभ	२०	६६.९८	४०. ३२	२६.५८	६५%
शुद्ध लाभ	——	१७.७९	घाटा ५.७९	२३.५८	
पूजींगत क्षमता	१०	१०.३६	१५३	८८२.५६	५७५%

जनता सरकार के आने के बाद से सीमेण्ट की कीमतों में हुई अप्रत्यशित वृद्धि से सम्पूर्ण सीमेंट उद्योग लाभान्वित हुआ है। १५.६० करोड़ बोरे सीमेण्ट उत्पादन करने वाली ए. सी. सी. के लिये सीमेण्ट की कीमत में हुई हर एक रुपये की वृद्धि का मतलब होता है १५.६० करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय। अप्रैल ९० से अब तक सीमेण्ट की कीमतों मे लगभग ९ रुपये प्रति बोरी की मूल्य वृद्धि हुई है। अगर सीमेण्ट उद्योग जानबूझकर बाजार में कमी बनाये रखने के लिये उत्पादन में कटौती न करे तो ए. सी. सी. समूह साल भर में १४१ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय करेगा।

हाल ही में ए. सी. सी. प्रबंधन ने जामुल सीमेंट कारखाने में कोयला, जिप्सम, बिजली आदि की बढ़ती हुई कीमतों का रेखाचित्र प्रस्तुत करके यह बताना चाहा कि सीमेंट उत्पादन की लागत में हो रही लगातार वृद्धि के कारण जामुल कारखाने में लाभ हो ही नहीं रहा है। उसी रेखाचित्र में बतायें गये आंकड़ों के मुताबिक प्रति इकाई पर लगने वाले अंश का हिस्सा जोड़कर देखें कि क्या इन बढ़ती कीमतों के बावजूद कारखाने को प्रति सीमेंट बोरी पर रु. १७/- का लाभ नहीं हो रहा है।

उत्पादकता को गिराये बगैर श्रमिकों की हित साधना हमारा उद्देश्य है पर यदि १५ दिनों के भीतर हमारी २० प्रतिशत बोनस तथा उद्योग में लगे हुए सभी श्रमिको को स्थाई न बनाया गया तो हम ३० नवम्बर से हड़ताल हेतु बाध्य होगें उत्पादकता को होने वाले नुकसान की जिम्मेदार ए० सी० सी० मैनेजमेंट रहेगा।

प्रगतिशील श्रमिक संघ जिन्दाबाद
छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद
शहीद साथी जिन्दाबाद

विनीत

प्रगतिशील सीमेन्ट श्रमिक संघ

उभेराम साहू — महामंत्री
हिच्छाराम साहू — अध्यक्ष

स्थाई साथी :- **मोहम्मद युनिष, बालकदास, शभु साहू, रामसिंह वर्मा, धरमराज रेड्डी**

केजुवल साथी :- **गंगाराम सिदार, रिखीराम साहू, मदनलाल यादव, दुखितराम मेश्राम, भानूराम साहू**

विजय प्रिंटिंग प्रस, बालोद

अंत में हम एक मौका और देते है। सारे औद्योगिक क्षेत्र की हड़ताल न होकर अब सिर्फ इस क्षेत्र के दो बड़े घरानों भिलाई वायर्स भिलाई तथा सिम्पलेक्स साम्राज्य के पांचो इकाइयों में ही होगी।

हमारी शक्ति का एहसास सभी को हो गया होगा फिर भी ए. सी. सी. सहित सभी उद्योग-पतियों को एक मौका हम और देते है कि वे चर्चा के जरिये समस्याओं के निराकरण तत्काल करलें।

१. क्योंकि सिम्पलेक्स समूह ही मजदूर नेताओं पर चाकू चलवा रहा है।

२. क्योंकि सिम्पलेक्स ने ही सबसे बड़ी संख्या में मजदूरों को नौकरी से निकाला।

३. क्योंकि सिम्पलेक्स मैनेजमेंट लाल हरा झंडे की कीमत आंकना चाहते है इसलिए अब हड़ताल सिर्फ सिम्पलेक्स समूह की उरला, भिलाई टेडेसरा स्थित पांचो इकाइयों में ही होगी।

- उद्योग स्थाई है अतः मजदूरों को स्थाई करना होगा।
- जीने लायक वेतन देना होगा।
- २० प्रतिशत बोनस देना होगा।
- तानाशाही रवैया हमेशा के लिए समाप्त करना होगा।
- निकाले गये श्रमिकों को काम देना होगा।

अन्य मांग—

- सी.पी.एफ. तथा ग्रेच्युटी की सुविधाएं नियुक्ति की तारीख से ही दी जावे।
- दुर्घटना से बचने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण दी जावे।
- कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को बी.एस.पी. अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा मिले।
- श्रमिक की चिकित्सा के दौरान उसे पूरा वेतन मिले।
- हर श्रमिक को अपना घर बनाने की दृष्टि से ऋण उपलब्ध कराया जावे

हर श्रमिक को साल में १५ दिन की आकस्मिक अवकाश मिले,

१० दिन का फेस्टिवल लीव्ह

३० दिनों का मेडिकल लीव्ह

नियमानुसार अर्जित अवकाश मिले

भिलाई के उद्योगपतियों से फिर एक बार अपील है कि उत्पादक हाथों वाले श्रमिकों का जायज हक संयम होकर मजदूरों को दें ताकि उत्पादकता तथा हाथों के बीच सहज संबंध बना रहे।

प्रगतिशील श्रमिक संघ जिन्दाबाद, **छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद,**

शहीद साथी अमर रहे,

एन. आर. घोषाल जनकलाल ठाकुर शंकर गुहा नियोगी

बजाज प्रिन्टर्स, राजहरा,

भिलाई के उद्योगपति कब तक श्रम कानूनों को अंगूठा दिखाते रहेंगे?

मजदूर साथी संघर्ष के लिये तैयार हो जाओ

द्रिनांक १५/११/९० गुरूवार ए. सी. सी. से लेकर इंडस्ट्रियल इस्टेट के सभी उद्योगों के मजदूर हड़ताल करेंगे!

उरला और टेडेसरा के मजदूर साथी एकता बनाकर आगे बढ़ो !!

दोस्तों,

देश में आज राजनैतिक पार्टियों के गैर जिम्मेदार नेताओं ने देश की मूल समस्याओं-बेरोजगारी, महगाई, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, गरीबों पर अत्याचार, कमजोरों का दमन आदि को ओझल करने के लिये ऐसे मुद्दों को खड़ा कर रखा है जिनका आम-जीवन की समस्याओं से कोई ताल्लुक नही है.

यह दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट हो चुका है कि देश की वामपंथी पार्टियां-जैसे सी.पी.आई., सी.पी.एम. आदि भी पूंजीपतियों की दलाली में कम माहिर नही हैं. वामपंथियों का वैचारिक दिवालियापन और मजदूर वर्ग के प्रतिनिधित्व के दावें का खोखलापन मात्र सम्बल चक्रवर्ती को देखने से ही मालूम हो जाता है, जो मालिकों की सेवा में मजदूरों के खून से होली खेलने की साजिश साकार करने के लिये दिन-रात जुटा हुआ है. जब भिलाई के ''तथा कथित'' गुंडे, मजदूरों से टकराने से इंकार कर रहे हैं तो यह ग्रामीण बेरोजगारों को भिलाई इस्पांत संयंत्र में रोजगार दिलाने के लालच में बुला रहा है. यह सब धोखेबाजी और साजिश, प्रशासन की आंखों के सामने, दिन-दहाड़े हो रही है..

भिलाई इस्पात संयंत्र का मैनेजमेंट, अपने समस्त साधनो के जरिये लाल हरा झन्डा यूनियन को भिलाई क्षेत्र में रोकने में लगा हुआ है. इस्पात संयंत्र के पर्सनल विभाग के अधिकारी बी.एस.पी. की नौकरी छोड़कर अपनी सेवाएँ बी.के., बी.को., सिम्पलेक्स, केड़िया को न्यौछावर कर रहे हैं. (बाजपेई, रमाशंकर तिवारी, एस.के. वर्मा आदि). भिलाई इस्पात संयंत्र के अफसरान, भिलाई की एन्सीलरी इन्डस्ट्रीज को काम न देकर कलकत्ता, दिल्ली की बड़ी-बड़ी कंपनियों से कमीशन ऐठतें हैं, यह सर्वविदित है..।

इससे क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है. इस्पात संयंत्र के अधिकारी बाहरी पार्टी को काम देते हैं और अपने दलालों को भेंट करते हैं, भिलाई के उद्योगपतियों को. बी.एस.पी. ने अभी-अभी पिछली दलाली की कीमत स्वरूप ५-६ लाख रूपये जार्ज कुरीयन को दिया था. अब कुरीयन ने अपनी बीवी, साला और भतीजों की बी.एस.पी. में नौकरी बोनस के रूप में प्राप्त की है. इस बार बी.एस.पी. मैनेजमेन्ट ने उसे सिम्लेक्स का उद्धार करने के लिये भेजा है. दल्ली राजहरा के मजदूर इन दलालों को चमड़े का मेडल भेंट कर चुकें हैं. अब भिलाई के मजदूर इन्हें चमचागिरी की सर्वोच्चट्राफी से सम्मानित करेंगे. सिर्फ समय का इंतजार हैं.

''हाथ तुम्हारे हैं, पत्थर उनका है, ताकत तुम्हारी है, दिमाग उनका है,
इधर तुम भले ही सीना तानकर दादागिरी दिखाते हो
गुरूजनों को गालियों का अशिष्ट तोहफा भेंट करते हो,
मगर राजनीति की शतरंज में तुम्हारी हैसियत,
फकत एक प्यादे की है.''

भिलाई के मजदूर इस बार जाग चुके हैं. ''एकता और भाई चारा'' का पवित्र मंत्र समूची मजदूर बस्तियों में गूंज रहा है. जाति, धर्म, प्रान्त, भाषा के भेद का इस बस्ती में अब कोई स्थान नही है. दुनिया की कोई भी ताकत मजदूरों की एकता को नही तोड़ सकती. उद्योगपतियों को मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने का मजा चखा दिया जायेगा.

''हम भगतसिंह का अंदाज बता सकते हैं.
और अशफाक के तेवर भी दिखा सकते हैं.
मादरे हिंद की लाज बचाने के लिये
हम, कारखानों से निकल सड़क पर भी उतर सकते हैं.''

दिनांक १५ नवंबर गुरूवार की हड़ताल को कामयाब करो.

लाल हरा झण्डा जिन्दाबाद
प्रगतिशील इन्जीनियरिंग श्रमिक संघ जिंदाबाद
छत्तीसगढ़ केमीकल मिल मजदूर संघ जिंदाबाद
छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ जिन्दाबाद
शहीद साथी अमर रहें.

रामबिलास मंडल भिलाई वायर्स	**नीलरतन घोषाल** संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ, भिलाई	**रवीन्द्र शुक्ला** केड़िया डिस्टीलरी लि.	**सुदामा प्रसाद** सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग	**मथुरा प्रसाद** सिम्पलेक्स कॉस्टिंग
राजाराम सिम्पलेक्स उद्योग	**श्रीनिवास** बी.ई.सी.	**शंकरदास माणिकपुरी** बी.के. सर्जिकल	**रामगोपाल** भिलाई	**जनकलाल ठाकुर** अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा.

।। ग्रुप

राक्षसी ताकत के बल पर, न्यायोचित मांग कर रहे सीमेंट श्रमिकों को दबाना सम्भव नहीं है।

ए.सी.सी. जामुल सीमेंट वर्क्स जामुल की मैनेजमेंट सन् १९८९-९० के सालाना बोनस ८.३३% की भुगतान की तिथि दिनांक ५-९-९० को घोषणा की। परन्तु ए. सी. सी. जामुल के मजदूर जब उसका बहिष्कार किया तो दिनांक ६-९-९० को 'बी' शिफ्ट व 'नाईट' शिफ्ट से लेकर मैनेजमेन्ट के लबादे में असामाजिक तत्वों नें जिस प्रकार मजदूरों के साथ जोर-जबरदस्ती प्रारंभ की, वह अत्यन्त निंदनीय है जिसमें एक-एक मजदूर को पकड़ के बन्द कमरे में ले जा कर, डरा, धमकाकर, बोनस राशि लेनें को बाध्य कर रहा है। इस तरह के रिपोर्ट किलन में कार्यरत मजदूर आनंद कुमार वर्मा, पैकिंग हाऊस के मजदूर अवधराम, कैलाश एवं खदान के मजदूर अगराहित सहित विभिन्न विभागों की कम से कम २५ मजदूरों नें की है। मैनेजमेंट की ओर से लेबर आफीसर श्री राकेश राजोरिया, इंटुक प्रतिनिधि श्री बी.एल. मंगोलिया आदि ने तो सब शर्म-हया त्याग कर ऐसा व्यवहार किया मानो वे एक प्रतिष्ठित कम्पनी के अफसर न हो कर, बम्बईया फिल्मों के 'दादा' हो।

संक्षिप्त भूमिका

ए. सी. सी. के अधिकाधिक श्रमिकों ने ८.३३% बोनस पेमेन्ट का बाय काट किया और २०% बोनस की मांग की। ध्यान देने योग्य तथ्य हैं कि वर्ष १९८९-९० में कम्पनी नें १७.७९ करोड़ का मुनाफा कमाया है और कानूनन अधिक बोनस देनें के लिए वह बाध्य हैं।

प्रगति शील सीमेंट श्रमिक संघ (पी. सी. एस. एस.) के नेतृत्व में ९०% से अधिक मजदूरों ने ८.३३% बोनस बहिष्कार कर इंटुक यूनियन को धता बताई, जिसने पर्चे के माध्यम से मजदूरों को बोनस लेने की अपील की थी।

अपनी पालतू यूनियन का अस्तित्व खत्म होने से मैनेजमेंट बौखला गया और इसी बौखलाहट मे ६ सित. का यह कुत्सित प्रयास किया गया एवं यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।

जनशक्ति को असुरशक्ति से दबाना संभव नहीं

इस गैर कानूनी दबाव के खिलाफ पी. सी. एस. एस. के नेतृत्व मे सैकड़ों सीमेंट श्रमिकों ने ७ सितम्बर को सुबह जुलूस निकाल कर अपना विरोध जाहिर किया और घोषणा की कि जनता को शक्ति को असमाजिक तत्वों की असुरशक्ति से दबाना सभव नहीं हैं और मैनेजमेंट को बताया कि इस तरह के हथकण्डों से औद्योगिक अशांति निर्मित होगी।

पी. सी. एस. एस. यूनियन एक बार फिर मैनेजमेंट से अपील करती है कि उसे सदबुद्धि आए और वह मजदूरों के जनवादी अधिकारों का सम्मान करें, उसी से शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता हैं।

पी. सी. एस. एस. यूनियन यह स्पष्ट घोषणा करता है कि इस वर्ष

(१) परमानेंट, कैंजुएल व ठेकेदारी मे कार्यरत सभी मजदूरों को बोनस देना होगा।

(२) ए. सी. सी. का मुनाफा को देखते हुए २०% बोनस देना होगा।

(३) बोनस देने के लिए जोर जबरजस्ती बरदास्त नहीं की जायेगी।

न्याय के लिए संघर्ष करो   **आपस मे एकता कायम करो**   **विजय की ओर आगे बढ़ो**

मजदूर एकता जिंदाबाद   **पी. सी. एस. एस जिन्दाबाद**   **लाल हरा झंडा जिन्दाबाद**

शहीद साथी अमर रहे   *धन्यवाद*

श्री हिन्छाराम साहू
(अध्यक्ष पी. सी. एस. एस.)

श्री उभेराम साहू
(महामंत्री पी. सी. एस. एस.)

एन. आर. घोषाल
संयोजक ३६ गढ़ मुक्ति मोर्चा
दुर्ग-भिलाई पाटन ईकाई
संगठन मंत्री पी. सी. एस. एस.

मनोरमा प्रकाशन गंजपारा, दुर्ग

ट्रक मालिक साथियों से अपील

"जहा इंसानियत लहु-लुहान होती है वहां घृणा पनपती है बैरी भावना से शांति बिगड़ती है और अशांति कोई भी नहीं चाहता है'।

प्रगतिशील ट्रांसपोर्ट श्रमिक संघ के झंडे तले दुर्ग एवं भिलाई के सैकडों ट्रक ड्रायवर एवं हेल्पर संगठित हो चुके है। हमारी संगठन की खबर सुनकर ट्रक मालिक साथी जिस प्रकार बैरीता मूलक व्यवहार कर रहे है जिससे हम आश्चर्य चकित है। ट्रक मालिक के ट्रक के साथ ड्रायवर हेल्पर का रिश्ता ट्रक के क्राउन व पीनियन के रिश्ता के बराबर होता है। बिना ट्रक ड्रायवर ट्रक आवाज नही करेंगी। ट्रक ड्रायवर का भी परिवार होता है। उनके भी घर में बाल बच्चे होते है। उनके बाल बच्चों को भी भूख लगती है। ट्रक मालिक साथी जिस प्रकार ट्रक ड्रायवरों के साथ व्यवहार करते हैं क्या वह मालिक है? ऐसे तो ट्रक ड्रायवर जान को हथेली में, लेकर ट्रक मालिक के लिए कार्य करता है। एक ट्रक ड्रायवर दिन में २४ घंटे में कितना काम करता है?

ट्रक मालिक भी कोई पूंजीपति नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के कारण ट्रक के स्पेयर-पार्टस वगैरह का भाव बढ़ते जा रहा है। फिर भी ट्रक मालिक अपना रेट तो बढा ही लेते है। ट्रक ड्रायवरों से ट्रक मालिक उम्मीद करते है कि ड्रायवर और हेलपर मुंह कान बंद कर अपनी शारिरीक दुख-तकलीफ की बात तो बोले ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के दुख-तकलीफ का भी ख्याल करना छोड़ दे। मात्र १५०) एक हेल्पर को दिया जाता है, छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी यहां तक की राष्ट्रीय छुट्टी से भी कर्मचारियों को वंचित किया जाता है। ट्रक लोडर (हमाल) एवं हेल्परों को जो मजदूरी दिया जाता है। क्या वह सरकार द्वारा बताए गये, "मिनिमम वेज एक्ट" के तहत न्याया संगत है?

सबसे दुख की बात तो यह है कि २ अक्टूबर को राष्ट्रीय त्यौहार के दिन छुट्टी मनाने पर "छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा" की रैली में भाग लेने के कारण ड्रायवर के ऊपर बदले की भावना से नौकरी से निकाल बाहर किया जा रहा है।

ट्रक हेल्परों से गाड़ी चलवाकर, आप ड्रायवरों के साथ बदला ले सकेंगे? समय पर तनखा न देना, अभद्र व्यवहार अनुचित है।

हम यह आपको बताना चाहते है कि हमारे संगठन के नेतृत्व में राजहरा में ट्रक मालिक भी संगठित है, ट्रक मालिक एवं ड्रायवर के बीच वहां कोई झगड़ा नहीं होता। भिलाई के ए. सी. सी. में भी हमारी संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों करें ट्रक ड्रायवर-हेल्पर संगठित है। वहां भी परिवहन के काम अच्छे से ही चल रहे है।

आप से निवेदन है कि बदला लेने की तरीका को छोड़ दें, चर्चा के जरिए स्थिति सामान्य बनाकर उचित मांगों पर विचार कर मधुर सम्बन्ध कायम किया जाय। जिससे वातावरण की कडुवाहट दूर होगी एवं परिवहन परिवार में शांति आ सकेगी।

धन्यबाद के साथ

श्री ओम प्रकाश यादव (अध्यक्ष)
श्री सुन्दर लाल चौहान (उपाध्यक्ष)
श्री बेनीप्रसाद यादव (महामंत्री)
श्री बंशीदास मानिकपुरी (सहमंत्री)
श्री पूनम बाघनकर (कोषाध्यक्ष)

जनकलाल ठाकुर
विधायक-डोंडी-लोहारा

भिलाई के सिर्फ चार नव-धनाढ्यों ने अपने का[illegible] के बल-बूते पर मजदूरों के सारे संवैधानिक अधिकारों को छीन रखा है। ये दरिंदे दिन-दहाड़े, दहाड़ते रहते हैं क्योंकि इन्होंने बरसों से गुंडों की एक निजी सेना पालकर रखी है। और धनबाद के माफिया स्टाइल में मजदूरों पर हमला बोलते रहते हैं।

क्या दारू वाले, टैक्स चोर कैलाशपति केड़िया, बब्बू और कई अन्य हत्याकांड में लिप्त उद्योगपति शाह परिवार, कल के फर्टीचर आज के अरबपति कुलदीप-विजय गुप्ता, अरविंद जैन-बी.आर.जैन को रायपुर में भी इसी प्रकार बेरोकटोक मजदूरों के खून से होली खेलने की छूट होगी? क्या रायपुर के राजनेता और जागरूक जनता इनके कहर को मूक-दर्शक के रूप में सहती रहेगी?

रायपुर के पुलिस कप्तान श्री आनंद कुमार (आई.पी.एस. अफसर) से क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि "आप इन चार पूंजीपतियों को एवं हजारों मजदूरों को एक ही तराजू से तौलेंगे। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, आपकी सहानुभूति मजदूरों की तरफ होनी चाहिये।"

आपसे चंद सवाल

- *दिनांक २४ अगस्त की घटना क्या सिर्फ मजदूरों के दो समूहों के बीच मारपीट की घटना थी?*
- *घटना के तत्काल बाद सिम्पलेक्स के मालिक नवीनशाह सुबह ७-०० बजे अपनी फैक्ट्री में पहुंच गये, क्या यह महज संयोग था?*
- *फैक्ट्री के भीतर से इतनी सारी तलवारें लेकर लोग निकले, इन तलवारों को फैक्ट्री में रखने के पीछे क्या अपराधिक नीयत नहीं थी?*
- *क्या प्रदर्शनकारी अपने पंडाल में सोये हुये नहीं थे? और वे संख्या में सिर्फ ७ (सात) ही थे।*
- *८०-१०० लोगों ने फैक्ट्री गेट से निकलकर मजदूर नेताओं पर हमला करने के पीछे क्या सुनियोजित साजिश नहीं थी?*
- *क्या ७ व्यक्ति १०० लोगों पर हमला करने की हिम्मत कर सकते थे?*
- *मारपीट का घटना-स्थल कहा है? यह पी.ई.एस.एस. का धरना पंडाल है। हमलावार कारखाने से निकल कर आये थे। अब आप बताइये कि इस घटना के लिये कौन जिम्मेदार है, मालिक या मजदूर?*
- *रायपुर के अखबारों में जिन घायलों के फोटो छपे थे वे सभी खून से सने मजदूर नेताओं के फोटो थे। पैसे वाले गुंडों को सेक्टर -९ अस्पताल ले गये, इसलिये मजदूर नेताओं पर ३०७ धारा का जुर्म कायम हुआ और हमला करने वालों पर ३२४ का? आप डी.के. अस्पताल एवं भिलाई अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करके ही जुर्म कायम करते तो सही नहीं रहता?*
- *१०० लोगों [illegible] किसने किसको मारा, ? क्या यह संभव नही कि गुंडों ने एक दूसरे के सर फोड़े?*
- *आपने १८५ लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भिजवा दिया, जिसमें १५० लोग सिम्पलेक्स के मजदूर नहीं थे बल्कि बी.ई.सी. कंपनी में कार्यरत मजदूर थे। इस प्रकार बी.ई.सी. के मजदूरों को गिरफ्तार कर क्या आपने बी.ई.सी. के मालिकों को नये मजदूर भर्ती करने का रास्ता तो नहीं बताया है? १५० मजदूरों के जेल जाने पर अब बी.ई.सी. कारखाना ठप्प हो चुका है, यह भी किसी साजिश के तहत तो नहीं?*
- *सिम्पलेक्स में जिन लोगों को नया भर्ती किया गया, क्या आपने उनके पिछले रिकार्ड की जांच कराई है? क्या वे भिलाई व आसपास क्षेत्र में रहने वाले गुंडे नहीं हैं?*

क्या यह महज संयोग था कि-

दिनांक १८ अगस्त को मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा के रायपुर आगमन पर भिलाई के ४ बड़े उद्योगपति उनसे मिले और १९अगस्त को प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष श्री उमाशंकर राय पर प्राणघातक हमला हुआ?

उसी प्रकार श्री सुंदरलाल पटवा ने भिलाई के उद्योगपतियों को बुलाकर २३अगस्त को भोपाल में उनसे बातचीत की और फिर सिम्पलेक्स उरला में पंडाल में सोये हुये मजदूर नेताओं पर प्राणघातक हमला हुआ?

जनहित में श्री पटवा को बयान जारी कर यह बताना चाहिये कि उद्योगपतियों से क्या-क्या बातचीत हुई? क्या उस बैठक में सिर्फ गृह-विभाग के अफसर ही उपस्थित थे या उद्योग व श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे?

हम रायपुर वासियों से एवं छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवी, मजदूर-किसानों से अपील करते हैं कि भाजपा की सरकार मजूदर एवं मजूदर नेताओं के खून से होली खेल कर अपने भगवा झंडे का अस्मिता रक्षा कर रही है। भिलाई, उरला-टेडेसरा के मजदूरों की एकता को वे (अपवित्र?) बाबरी-मस्जिद समझ रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाले केड़िया अब गुंडों के बल पर सामाजिक जीवन को भी प्रदूषित कर रहा है। सिम्पलेक्स से लेकर मोदी तक सभी मालिकों ने पटवा पुलिस राज्य में मजदूरों की जुबान को दबाने के लिये हर प्रकार का दमनात्मक तरीका अपनाया है। भिलाई के ये चार उद्योगपतियों के इशारे पर उनकी रखैल गुंडावाहिनी के जरिये अब तक बारह मजदूर एवं मजदूर नेताओं पर प्राणघातक हमला किया जा चुका है। मजदूर नेता शंकरगुहा नियोगी को २महिना बिना कारण जेल की काल कोठी

में रखा गया। उन पर अब जिला-बदर का प्रकरण चला[illegible] जा रहा है।

हम पूछते हैं कि

* क्या ट्रेड यूनियन करना भारत के संविधान के खिलाफ है?
* मजदूरों का अपने कानूनी हक के लिये संगठित होना क्या व्यवस्था के खिलाफ बगावत है?
* ११ महीनों से चल रहा मजदूर आंदोलन अगर शांतिपूर्ण आंदोलन न होता तो क्या यह आंदोलन इतने दिन चल सकता था?
* क्या जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने मालिकों को नई भर्ती करने की छूट देकर मालिकों की तरफदारी नहीं की है? उनकी गुंडागर्दी को प्रोत्साहन नहीं दिया है? सैकड़ों की संख्या में नई भर्ती के बाद भी उत्पादन ठप्प क्यों है? नये लोगों को फिर क्यों भर्ती किया गया?
* क्या मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिये श्रम-विभाग ने एक बार भी बैठक का आयोजन किया?

हम छत्तीसगढ़ के जागरूक जनमत से सहयोग की अपील करते हैं और तानाशाही ताकतों को चेतावनी देते हैं कि हिटलर, मुसोलिनी जैसी हस्तिया मजदूर आंदोलन की गहराई को नहीं नाप पाई तो केडिया- शाह- जैन- गुप्ता- पटवा जैसे मेंढक आये हैं गहराई को नापने के लिये। हमारा यह संघर्ष विजय की मंजिल प्राप्त करके ही दम लेगा।

लाल हरा झंडा जिंदाबाद! शहीद साथी अमर रहे!

अनूप सिंह
प्रगतिशील इंजि. श्रमिक संघ

जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

लड़ रहे हैं इसलिये कि प्यार जग में जी सके।
आदमी का खून कोई आदमी न पी सके।

दरिंदों ने उद्योगप[illegible] बन कर,
इंसान के लहू से अपनी सेज सजाई।
मजदूर जब हक मांगने निकले तो,
खून के प्यासों ने अपनी तलवार चलाई।।

हलधर सुरेन्द्र सिह सुखलाल

२४ अगस्त दिन शनिवार की सुबह ६-४५ बजे सिम्पलेक्स कारखाने में छिपे मालिक नवीन शाह व मूलचंद शाह के गुंडों ने प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष श्री एस.के. सिंह, सचिव श्री हलधर व कोषाध्यक्ष श्री सुकलाल को तलवार, राड व लाठियों से मार-मार कर लहुलुहान कर दिया। ये तीनों बेहोश होकर गिर गये।

घंटों तक सिम्पलेक्स के मालिक नवीन शाह के नेतृत्व में सरदार भगवान सिंह, सरदार के.जी. सिंह, सरदार जोगेन्दर सिंह, सरदार ज्ञान सिंह, सरदार गुरचरण सिंह व सरदार बुआ सिंह आदि ने खून की होली खेलकर दहशत का माहौल बनाकर रखा। अभी हाल में कारखाने में भर्ती किये गये ८०-६० मजदूर उर्फ गुडे, खतरनाक हथियारों से लैस होकर इनके साथ तांडव नृत्य करते रहे।

उरला औद्योगिक नगरी रायपुर क्षेत्र में स्थित है। रायपुर को छत्तीसगढ़ की भावी राजधानी के रूप में देखा जाता है। रायपुर के बुद्धिजीवी, स्कूल-कालेज के विद्यार्थी, छत्तीसगढ़ के हित में हमेशा अपनी जुबान खोलते रहे हैं। यहीं के विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण जी, केयूर भूषण जी, पुरूषोत्तम कौशिक, नरेन्द्र दुबे, चंद्रशेखर साहू, रमेश बैस, पवन दीवान आदि नेतागण छत्तीसगढ़ के जाने माने जन नेता हैं और उनके नाम व काम बरसों से अखबारों की सुर्खियों में बने हुये हैं।

२ अक्टूबर के विशाल जुलूस की तैयारी करो

भिलाई के मजदूरों ने बहादुरी के साथ भिलाई के उद्योगों में लाल-हरा झंडा फहराया।

"मची खलबली लुटेरों के घर में,
गड़बड़ी फैलाने वालों में अब लगी है हड़बड़ी"।

मजदूर साथी,

अपनी जीत को सुनिश्चित करो,
एकता के झंडा को बुलंद करो।

दोस्तों,

दिनांक १७ सितम्बर की जुलुस ए. सी. सी. के बोनस बाईकाट और हर उद्योगों में मजदूर साथियों ने जिस बहादुरी के साथ मालिकों के खिलाफ मुकाबला कर रहे है, उससे मालिकों की चड्डी ढीली होती जा रही है। चारों तरफ आन्दोलन का माहौल बना हुआ है। इस बार भिलाई के मजदूर शपथ ले चुके हैं कि, मालिकों की दादागिरी अब चलाने नहीं दिया जाएगा। गुण्डों के सहारे चलाये जाने वाले औद्योगिक सम्बन्ध के ढाचे को समाप्त कर जनवादी आधार पर नए ढांचे का निर्माण किया जायेगा। मजदूर इस बार तय कर चुके हैं, कि एक के लिए सब खड़े होंगे और सबके लिए हर एक तत्पर रहेगा।

अब भिलाई के मालिक मजदूर सम्बंध में अपना हिस्सा बरकरार रखने के लिए दलाल एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। निलामी की बोली चढ़ रही है, पर जब बी. एस. पी. के समान वेतनमान का सवाल आता है तो सम्बल चक्रवर्ती कहता है कि "यह तो मिलना सम्भव नहीं है"। लगता है कि सम्बल चक्रवर्ती के पास मालिकों की तिजोरी की चाभी सौंपा गया है। केडिया देवरिया जिला मजदूर साथियों से सम्पर्क कर जातिवाद जिन्दाबाद फैलाने में लगा है, जबकी एक देवरिया वाले को सिम्पलेक्स के "मूलचंद" ने मारने पीटने का काम सौंपा और उस पाखंडी ने देवरिया जिला निवासी ईमानदार मजदूर साथी सूरजदेव वर्मा को बेरहमी से मारपीट कर अधमरा कर दिया।

इन्सान के खून पीने वाले, उद्योग घराना के मालकों,
गुण्डागर्दी का रास्ता छोड़ दो, कितने लोगों को तुम लोग मार सकते हो। हमारे साथ लाखों मजदूर हैं। अगर मजदूरों की आंखे सिर्फ लाल हो जाती है तो तुम उसके सामने पीले पड़ जाओगे, फिर बहादूरी क्यों? हमारी हिदायत सुनो, आतंक फैलाना बन्द करो।

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है" "केडिया" को "भेड़िया" याद आना चाहिए। बी. आर. जैन को मौन त्यागना होगा। जनाब कुलदीप को डिजाइन और ड्राइंग में गुस्सैल मजदूरों का चेहरा नजर आयेगा। सिम्पलेक्स उरला और टेड़ेसरा में मजदूर लाल-हरा झंडा ही फहरायेगा। २ अक्टूबर की रैली में सभी मालिकों का हिसाब किताब बताया जायेगा।

लाल हरा झंडा जिन्दाबाद!
शहीद साथी अमर रहे।

लड़ने के लिए हिम्मत करो।
जीतने के लिए हिम्मत करो।

विनीत :

पूनम बावनकर	भानसिंह श्रीवास	एन. आर. घोषाल	जनकलाल ठाकुर
अध्यक्ष	अध्यक्ष	महामंत्री	अध्यक्ष
प्रगतिशील ट्रा० श्रमिक संघ, दुर्ग-भिलाई	प्रगतिशील स्पात श्रमिक संघ, भिलाई	छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ, भिलाई	छत्तीसगढ़ मु. मो.

(मुद्रक : विजय प्रेस, बालोद)

भिलाई औद्योगिक क्षेत्र का मजदूर

अब मजबूर नहीं...

भिलाई इस्पात कारखाना बननें के बाद इस अंचल में सैकड़ों छोटे एवम् मध्यम उद्योग पनपें है और इस अंचल में उत्पादकता की वृद्धि हुई है। परन्तु उत्पादन को तीव्रता देने वाले मजदूर बरसों से अमानवीय शोषण के शिकार रहे हैं। स्थाई उद्योगों में जिंदगी भर काम करने वाले ठेका मजदूर ही नहीं, स्थाई मजदूरों की नौकरी भी मालिकों की मर्जी पर निभर रही है।

इस तरह कें जुल्मों के खिलाफ, कई बार मजदूरों ने आंदोलन किये, पर हर बार मजदूर आंदोलन असफल हुए और मजदूर घोर निराशा में डूब गए।

इस वर्ष, एसीसी के ७७ ठेकेदारी मजदूरों ने, लाल-हरा झंडा कें नेतृत्व में एक जोरदार आन्दोलन में विजय प्राप्त करके आशा की एक लहर पैदा की है। आज समस्त इंडस्ट्रीज के मजदूर लाल-हरा झंडा को अपना कर आंदोलन करनें के लिए तैयार हैं।

पर इस बार हमें, अपनी पुरानी गलतियों को समझना है और समझकर, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग चुनना है तभी इस आंदोलन में सफलता प्राप्त होगी।

अब तक इंडस्ट्रीज का मजदूर-आंदोलन नाकामयाब क्यों रहा ?

१) यूनियन के नाम पर दलाल व गुंडों का नेतृत्व हावी रहा।

२) अलग-अलग कारखानें के मजदूर बंटे रहे और कारखानें के भीतर भी सप्लाई, ठेकेदारी, कैजुअल व रेगुलर के नाम पर बंटे रहे।

इस प्रकार हर कारखाने के मजदूर अलग-अलग समूह में आंदोलन करते गए और मालिक हर आंदोलन को कुचलते गए।

मालिकों का नारा : फूट डालो राज करो।

अब हमें क्या करना है?

१) हर सेक्शन, हर युनिट व हर कारखाने में ईमानदार व लड़ाकू नेतृत्व कायम करना है।

२) इस बात को समझना है कि सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। इस विचार के साथ सभी कारखानों में ठेकेदारी, सप्लाई, कैजुअल व रेगुलर मजदूर एकता कायम करें और एकजुटता के साथ संघर्ष की राह अपनाएं।

हमारा नारा : १. एक के लिये सब और सब के लिये एक
२. एक आवाज में सब एक साथ

ए.सी.सी. के मजदूरों ने जिस गंगा को भिलाई में बहाया है, उसी धारा में, कुम्हारी डिस्टिलरी से नागपूर इंजिनियरिंग तक, हर उद्योग की धाराएं मिलाकर एक ऐसे महासागर का निर्माण करें जिसकी लहर पर, यानी मजदूरों के हर कदम पर, मैनेजमेंट की चाल को मात देते हुए, मजदूर-आंदोलन कदम-दर-कदम विजय की नई मंजिलें हासिल करें।

लाल-हरा झंडा जिन्दाबाद ! छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद !!

शहीद साथी अमर रहें !!!

पूनम बावनकर
प्रगतिशील ट्रांस्पोर्ट श्रमिक संघ

एन. आर. घोषाल
संगठन मंत्री,
छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ, भिलाई रजि. नं. ३१४१
संगठन मंत्री,
प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ रजि. नं. ४०६०
महामंत्री
प्रगतिशील इस्पात श्रमिक संघ रजि.नं. ४०६१

जनकलाल ठाकुर
अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

विप्लव, रायपुर

22-1-90

अब यह जाहिर है कि ए. सी. सी. के संघर्षरत मजदूरों को कुचलने के लिए वे खून पिपासु बन चुके हैं ।

मजदूर भी उनसे निपटने के लिए पूर्ण रुप से तैयार हैं ।

सोधी कार्यवाही के तहत दिनांक २३-७-९० को शंकरगुहा नियोगी अनिश्चितकालीन अनशन शुरु करेंगे ।

साथियों,

जैसे कि आप लोग अब तक यह महसूस करते आ रहे हैं कि "बिना युद्ध के पांच गांव" भी मैनेजमेंट रुपी कौरव ने न देने की ठान ली है। मजदूरों की मांग- सेफ्टी उपकरण, १०-१५ वर्ष से कार्यरत मजदूरों का स्थायीकरण आदि समस्यायें हल नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है । भाजपा सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ अखड़ची लड़ाई में अनर्गल शेखी बघारते रहते हैं । परन्तु मालिकों के दरबार में वे इंटक (कांग्रेस) के साथ गले से गले लगाकर "मालिकम् शरणम् गच्छामि" चरितार्थ कर रहे हैं । भिलाई के सारे पूंजीपति(उद्योगपति) एक चंडाल चौकड़ी बनाकर मजदूरों को सदा से ही निर्मम शोषण करते आ रहे हैं । मजदूर मजदूर में फूट डालकर असामाजिक तत्वों के जरिये गुण्डागर्दी करवा कर वे मजदूरों को दबाकर रखते हैं अब समय आ चुका है कि मजदूरों को भी एक जूट होना होगा । जब उद्योगों के मालिक लोग मिलकर मजदूरों के खिलाफ साजिस करते हैं, तो फिर विभिन्न उद्योगों के मजदूर एक जूट होकर मालिक वर्ग के साजिसों का जवाब क्यों नहीं देंगे ?

छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भिलाई के पूंजीपतियों की निरंकुश अत्याचार, शोषण, निपीड़न एवं दमन बरदाश्त नहीं करेंगे । लम्बी शान्तिपूर्ण आन्दोलन के जरियें, अत्याचारियों को मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा । कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं और शहीदों की कुर्बानियों से सीख लेकर हम आगे बढ़ते जायेंगे ।

सिम्पलेक्स, बी.के., बीको, भिलाई इस्पात संयंत्र के सारे मजदूर साथियों से अपील है कि ए.सी.सी. मैनेजमेंट के खिलाफ संघर्षरत मजदूरों को अपनी नैतिक एवं सक्रिय समर्थन दें । मजदूर भाईचारा की सीमेंट से मजदूर एकता को मजबूत बनायें । हजारों की संख्या में अन्याय का विरोध करने के लिए आवाज बुलन्द करें।
अभिनन्दन के साथ,

– भवदीय –

पूनम बावनकर	भानसिंह	एन. आर. घोषाल	जनकलाल ठाकुर
प्रगतिशील ट्रांसपोर्ट श्रमिक संघ भिलाई-दुर्ग	अध्यक्ष ए. सी. सी. श्रमिक संघ	संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ, भिलाई	अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

छत्तीसगढ़

शहीद साथी अमर रहे ।
लाल-हरा झंडा जिन्दाबाद ।
भूख के खिलाफ संघर्ष जारी है, जारी रहेगा ।
लूट के खिलाफ संघर्ष जारी है, जारी रहेगा ।

मुद्रक : विजय प्रेस, बालोद.

ए. सी. सी. मैंनेजमेंट के शोषण व दमन के खिलाफ

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ललकार

ए. सी. सी. मैंनेजमेंट नें शुरु से ही बड़ी चतुराई के साथ दमनात्मक नीति अपनाते हुए स्थायी कार्य में करीब करीब १००० कुशल, अर्धकुशल और अकुशल मजदूरों कें न्यायोचित हकों को मागने कें लिए उन्हे २४-२५ ठेकेदारों के मार्फत काम पर रखा ताकि विभागीय श्रमिकों को मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा सके। मैंनेजमेंट की काली करतूतों पर पर्दा डालने का काम मैंनेजमेंट की गोद में पलने वाला यूनियन इंटुक ने किया। श्रमिकों के अधिकारों का रक्षक यूनियन ही अगर भक्षक बन जाये तो विनाश से कैसे बचा जा सकता है ? उदाहरण के तौर पर डावड़ा ब्रदर्स के एवं निजी वाहनों के ड्रायव्हर, हेल्फर, मेकेनिक, प्रोसेसिंग में कोयला, जिप्सन आदि की लोडिंग, अनलोडिंग, किलन, चार्जिग, पैकिंग एवं नाना प्रकार सिविल व मेंन्टेनेन्स कार्य में कार्यरत मजदूर। मजदूरों को संगठित न होने देने की नियत से स्थानीय मजदूरों को किसी न किसी बहानें नौकरी से हटाकर भुखमरी कें मुंह में ढकेंल दिया जाता है। जबकि बाहरी प्रान्तों से मजदूरों को लाकर नौकरी बहा ली की जातीहै और मैंनेंजमेंट के जूठन पर पलने वाला इंटुक मूह ताकते रहताहै।

ए. सी. सी. मैंनेंजमेंट का कायदा है कि सी. पी. एफ उन्हो मजदूरों को मिलता है जो प्रोसेस जाब में तीन महीने में कम से कम ६० दिनों की हाजिरी पाये हो। यदि थोड़ी भी ईमानदारी रखी जाये तो इन मजदूरों को ३ महिने में १२० हाजिरी मिलनी चाहिए क्यों कि १ हाजिरी तो सिर्फ ८ घंटे की होनी चाहिए। जहां मजदूरों के काम की अवधि और समय की कोई सीमा ही न हो वहाँ कें मजदूरो की सही हाजिरी मिलेगी कैसे ? यदि ईमानदारी से हाजिरी दी जाती तो इन मजदूरों को उनकें सी. पी. एफ. और ग्रेज्युटी का हक भी देना होता। इन दोनों से बचने के लिए ही ५ लायसेंसधारी ठकेंदारों और १९-२० चमचे ठेकेदारों को संरक्षण देकर मजदूरों की हाजिरी कभी भी पूरी नहीं होनें दी जाती। अपनें झोपड़ों में रहनें वाले इन मजदूरों को दिन हो या रात जैंसे ही कोयले या जिप्सन की रेंक आती है काम पर लगना होता है। न्याय संगत ढंग से ८ घंटे में ४ मजदूरों द्वारा १ वैंगन खाली होता हैऔर एक-एक हाजिरी भी बनती है पर वैंगन पर वैंगन खाली करने के बाद भी मजदूरों को हाजिरी के लाले पड़े रहते है। जिस हाल में आज ए. सी. सी. कें मजदूर है उनकी हालत पर शायद बन्धुआ मजदूरों को भी तरस आएेगा। पर यह मैंनेंजमेंट मानवता को दर किनार रख कर अपनें मजदूरों से गुलाम की तरह काम लेता है और मेंनेंजमेंट वहां की मान्यता प्राप्त इन्टुक युनियन उसी मैंनेंजमेंट को देवता की तरह पूजा करती रहती है।

प्रबंध निदेशक श्री ए. के. पाठक जी क्या आपके पास इस मजदूर विरोधी कार्य और जुल्म की कोई सीमा है ?

अपनी जवानी के दिनों को उद्योग में लगाकर अपनें खून पसीने से उत्पादन करके स्थायी कार्य में १५-२० वर्ष काम करनें के बाद भी ठेका मजदूर के ही रुप में रिटायर्मेंट हो जाता है। क्या आपका कारखाना भारत के संविधान कानून से भी ऊपर और अधिक ताकतवर है ? यदि नहीं तो फिर प्रचलित श्रम कानूनों के तहत दी जाने वाली सी. पी. एफ. और ग्रेच्युटी के हक से इन मजदूरों को आप क्यों वंचित रखे हुए है ? क्यूं इन मजदूरों को विभागीय मजदूरों से अलग रखा है ?

सिर्फ ठेका मजदूर ही नहीं ए. सी.सी. का स्थायी मजदूर भी शोषित है

ए. सी. सी. का ठेका मजदूर गुलाम है और स्थायी मजदूर भी बन्धुआ मजदूर की जिन्दगी जी रहा है। जहां स्थायी औद्योगिक श्रमिकों को साल में २२ दिनों की ग्रेच्युटी दी जानी चाहिए वहां आज भी ए. सी. सी. का मजदूर सिर्फ १५ दिनों की ग्रेच्युटी पाता है। बात इतनी ही नहीं, इस हाल में रहने वाले स्थायी मजदूरों पर दबाव डाला जाता है कि वे स्वैच्छिक पदमुक्ति (वालेन्ट्री रिटायर्मेंट) ले लेवे। यह शायद भारत की उन चंद कारखानों में से एक है जहां "बोर्ड आफ आर्बीट्रेटर्स सीमेंट इन्डस्ट्री" का एवार्ड आज भी पूरा लागू नहीं हो पाया है।

तानाशाही के बलबूते पर लगातार ए. सी. सी. मैंनेंजमेंट अपने श्रमिकों का शोषण करते आ रहा है। १५-२० वर्षों से काम करने वालों की ग्रेंच्युटी, बोनस आदि में हेराफेरी, सिनियारिटी को तोड़ मरोड़कर प्रमोशन में भाई भतीजे की नीति अपनाकर

अपने पिट्ठुओं को पदोन्नती देने वाली यह संस्था मान्यता प्राप्त इंटुक यूनियन को कुछ टुकड़े देकर मजदूरों के हक को छीनें हुए है। बिना हेल्पर के ड्रायव्हरों से काम लेना, एक ही काम के लिए एक वेतनमान न देना, सवैंतनिक, साप्ताहिक अवकाश न देना, यहां की आम बात है।

सिर्फ मजदूरों को नही सरकार को भी लूटता है ए. सी. सी. मैंनेजमेंट

ए. सी. सी. एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसके एक तरफ मजदूर कटता है दूसरी तरफ सरकार भी लूटती है। अपने ही लीज की खदानों से आने वाले कच्चे माल का हिसाब कभी भी सही नहीं रखा जाता ताकि अपनी खदान से रायल्टी की चोरी हो सके। फिर सीमेंट बनानें की प्रक्रिया को पूरी न करके हर महीनें कम से कम १५ हजार टन क्लींकर बाहर भेज दिया जाता है। क्योंकि क्लिंकर फिनिश्ड (Fincssed) माल की श्रेणी में नहीं आता इसलिए उससे प्राप्त आमदनी का जिक्र भी ए.सी.सी. के खाते में नहीं होता है। क्लींकर के इतनें बड़े हिस्से को गायब करने के बाद बचे हुए क्लींकर से सिमेंट बनाया जाता है। फलत: कम्पनी के खाते में निर्मित माल (सिमेंट) की मात्रा कम हो जाती है। जिसके आधार पर कम्पनी की आमदनी भी कम हो जाती है। इससे पहला फायदा यह होता है कि एक्साइज डियूटी कम देना पड़ता है, दूसरे आयकर कम देना पड़ता है और मजदूरों को न्यायोचित बोनस से भी वंचित रखने में सहायक होती है।

ए. सी. सी. के मजदूरों पर अब और अत्याचार नहीं होने देंगे

मजदूरों के शोषण और अत्याचार से बचाने एवं अपने न्याय संगत अधिकारों को पानें की गरज से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का लाल, हरा, झण्डा अब ए. सी. सी. के मजदूरों नें भी अपने हाथों में उठा लिया है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ अब मजदूरों की हर न्यायोचित मांगे एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को दिलाने के लिए ए. सी. सी. कें मजदूरों को नेतृत्व प्रदान करेगें। लोकतंत्र में आस्था रखने वाला यह यूनियन अब और अत्याचार न होने देने के लिए जनतांत्रिक तरीके से अपना आन्दोलन चलाएगी और गांधीवादी हथियारों, सत्याग्रहों, धरना आदि के माध्यम से प्रशासन और मैंनेजमेंट को ललकारेगी।

ताकि जनता हकीकत को जानें, मैंनेजमेंट अपने औकात में रहे, और प्रशासन वस्तु स्थिति को जानकर तत्काल समुचित कार्यवाही करे।

किसान मजदूर एकता जिन्दाबाद ! इन्कलाब जिन्दाबाद !!

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद

लाल हरा झण्डा जिन्दाबाद, शहीद साथी अमर रहे

आपके साथी

(१) श्री जनक लाल ठाकुर
अध्यक्ष
छत्ती. मुक्ति मोर्चा
(बिधायक डौंडी लोहारा)

(२) श्री भानसिंह श्रीवास
अध्यक्ष
छत्ती. श्रमिक संघ
भिलाई

(३) श्री भागवत दास साहू
महामंत्री
छत्ती. श्रमिक सघ

(४) श्री बिसेलाल निषाद
उपाध्यक्ष
छत्ती. श्रमिक संघ

श्री एन. आर. घोषाल
संयोजक
छत्तीसगढ़ मुक्त मोर्चा
भिलाई जामुल, दुर्ग

कार्यकर्ता :- हिन्छाराम साहू, श्री केशवप्रसाद गुप्ता, श्री अग्रहित यादव, श्री उभेराम साहू, श्री सूरजभान साहू, श्री गंगा प्रसाद विषाद, श्री हिरावन सिन्हा, श्री कुजलाल यादव, श्री भरत चौहान, श्री टेकराम चौहान, श्री धनराज ठाकुर, श्री दीपक सरकार,

(मनोरमा प्रकाशन गजपारा, दुर्ग)